रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-73

REGISTERED NO. D. (D. N.)—73

B 6684

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7, 1984/चैत्र 18, 1906

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7, 1984/CHAITRA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1984

का०आ० 1126.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स दकन फाइबर ग्लास लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 8वी मंजिल (वेस्टर्न विंग)" परिश्रमा भवनम्", 5-9-58 बी बशीरबाग, हैदराबाद-500029 के कथित अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1669/83) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[[illegible]]

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 22nd March, 1984

S.O. 1126.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Deccan Fibre Glass Limited, having its registered Office at 8th Floor (Western Wing) 'Parisrama Bhavanam", 5-9-58/B, Bashirbagh, Hyderabad-5000029, under the said Act (Certificate of Registration No. 1669/83).

[No. 16/44/83-M-III]

का० आ० 1127.—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स कैलाश कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-1/25-26, एमआईडीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, चींचवाड, पूना-411019, के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या 1650/83) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[सं० 16/2/84/-एम-3]

S.O. 1127.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Cent'al Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Kailas Castings Private Limited, having its registered Office at D-1/25-26, MIDC Industrial Area Chinchwad, Poona-411019 under the said Act (Certificate of Registration No. 1650/83).

[No. 16/2/84-M. III]

का०आ० 1128—एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) की धारा 26 की उप-धारा (3) के अनुसरण के केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स [illegible] फाइन केमीकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 97-ई, भोसारी इंडस्ट्रीयल एरिया, पूना-411026, के कथित अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या [illegible]/83) के निरस्तीकरण को अधिसूचित करती है।

[संख्या 16/2/84-एम-3]

के० पी० गुप्त, निदेशक

1592 GI/83—1

S.O. 1128.—In pursuance of Sub-section (3) of Section 26 of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969), the Central Government hereby notifies the cancellation of the registration of M/s. Tulsi Fine Chemical Industries Private Limited, having its registered Office at 97-E, Bhosari Industrial Area, Poona-411026, under the said Act (Certificate of Registration No. 1648/83).

[No. 16/2/84-M-III]

V. P. GUPTA, Director.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1984

का० आ० 1129.—केन्द्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री एन० एस० माथुर, अधिवक्ता को दिल्ली जिला और सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में विशेष पुलिस स्थापना नियमित मामला आर० सी० 2/80 सी० आई० यू० (ए) में अभियुक्तों के और दिल्ली उच्च न्यायालय में इस मामले से उत्पन्न विषयों के अभियोजन के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है।

[सं० 225/2/84-ए०वी०डी०-II(ii)]

एच० के० वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri N. S. Mathur Advocate, as Special Public Prosecutor for conducting the prosecution of the accused in the Delhi Special Police Establishment Regular Case R.C. 2/80 CIU (A) in the Court of District and Sessions Judge, Delhi as well as in the Delhi High Court in the matters arising out of this case.

[No. 225/2/84-AVD. II(ii)]

H. K. VERMA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 1984

प्रधान कार्यालय संस्थापन

का० आ० 1130.—केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, (1963 का संख्यांक 54) की धारा 3 के उपखंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री डी० आर० चक्रवर्ती को, जो पिछले दिनों मुख्य आयुक्त प्रशासन) और आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल-I, कलकत्ता के रूप में तैनात, 2 मार्च, 1984 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य के रूप नियुक्त करती है।

[फा० सं० ए-19011/1/84-प्रशा० I]

जी० एस० मेहरा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th March, 1984

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT

S.O. 1130.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Central Boards of Revenue Act, 1963 (No. 54 of 1963), the Central Government hereby appoints Shri D. R. Chakraborty, an officer of the Indian Revenue Service (Income-tax) & lately posted as Chief Commissioner (Admn.) & Commissioner of Income-tax, West Bengal-I, Calcutta, as Member of the Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of the 2nd March, 1984.

[F. No. A-19011/1/84-Ad. I]

G. S. MEHRA, Dy. Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1984

आयकर

का० आ० 1131.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पहले जारी की गई अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रों के आयकर आयुक्त (अपील), अनुसूची के स्तम्भ (2) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर बोर्डों, परिमण्डलों, जिलों और रेंजों में आयकर अथवा अतिकर या ब्याज कर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों के बारे में, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खंड (क) से (ज), कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा ब्याजकर अधिनियम, 1974 (1974 का 45) की धारा 15 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी भी आदेश से व्यथित हुए हैं, और ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों की बाबत भी, जिनके लिए बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 246 की उपधारा (2) के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार निदेश दिया है या भविष्य में निदेश दें, कार्य निर्वहन करेंगे,

अनुसूची

अधिकार क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय	आयकर बार्ड तथा परिमंडलों/जिला/रेंज
1	2
1. आयकर आयुक्त (अपील)-I नई दिल्ली	1. निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज, XVII नई दिल्ली (पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज VI-क नई दिल्ली के तौर पर पदनामित था और इसमें वे सभी वार्ड/परिमंडल/जिले आते हैं जो उस रेंज के क्षेत्राधिकार में हैं।
	2. निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज VI-क, नई दिल्ली (पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त रेंज-I ख, नई दिल्ली के रूप में पदनामित था) और उस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमंडल/जिले।
	3. निरीक्षी सहायक आयुक्त, VI-ग, नई दिल्ली (पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज-I ग, नई (दिल्ली के तौर पर पदनामित था) और उस रेंज के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड परिमंडल/जिले।

1	2
	4. निरीक्षी सहायक आयुक्त, कंम्पनी रेंज II, नई दिल्ली पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज I घ, नई दिल्ली के तौर पर पदनामित था) और उस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमंडल/जिले।
	5. निरीक्षी सहायक आयुक्त (निर्धारण) रेंज XIII नई दिल्ली तथा उस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले।
2. आयकर आयुक्त (अपील)-V नई दिल्ली।	1. निरीक्षी सहायक आयुक्त (निर्धारण), रेंज XVIII नई दिल्ली (पहले कंपनी परिमंडल XXI, नई दिल्ली के तौर पर पदनामित था) तथा उस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सारे वार्ड परिमंडल/जिले,
	2. निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त, रेंज IV-क, नई दिल्ली तथा इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सारे वार्ड/परिमंडल/जिले।
	3. निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज IV-ख नई दिल्ली तथा इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सारे वार्ड/परिमण्डल/जिले।
	4. निरीक्षी सहायक आयुक्त, कंपनी रेंज-I, नई दिल्ली (पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त, रेंज-Iक, नई दिल्ली के तौर पर पदनामित था) तथा इस के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमंडल/जिले।
	5. निरीक्षी सहायक आयुक्त (निर्धारण) रेंज I, नई दिल्ली (पहले निरीक्षी सहायक आयुक्त रेंज I-क , नई दिल्ली के तौर पर पदनामित था) तथा इस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमण्डल/जिले।
	6. निरीक्षी सहायक आयुक्त, (निर्धारिण) रेंज ii-च, नई दिल्ली के तौर पर। पदनामित था) तथा इस रेंज के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी वार्ड/परिमंडल/जिले

यतः, जहां कोई आयकर परिमंडल, वार्ड अथवा जिला अथवा उसका कोई भाग इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज में अन्तरित कर दिया गया हो, अतः वहां उस आयकर वार्ड/परिमंडल, अथवा जिले अथवा रेंज अथवा उसके किसी भाग में किये गये कर निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और इस अधिसूचना की तारीख से तत्काल पूर्व, रेंज के उस आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विचाराधीन पड़ी अपीलें, जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त आयकर वार्ड, परिमण्डल, जिला अथवा रेंज अथवा उसका कोई भाग अंतरित किया गया हो, इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से रेंज के उस आयकर आयुक्त (अपील) को अन्तरित की जायेंगी और उसके द्वारा निपटाई जायेंगी जिसके अधिकार क्षेत्र में उक्त वार्ड, परिमण्डल, जिला, रेंज अथवा उसका कोई भाग, अन्तरित किया गया है

यह अधिसूचना 21-8-1983 से प्रभावी है।

[सं० 5614 फा० /सं० 261/10/83-आ०क० -या०]

के० एम० सुल्तान, अवर सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 7th February, 1984

(INCOME-TAX)

S.O. 1131:—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121-A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the notifications issued earlier, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals) of the charges specified in column No. 1 of the Schedule below, shall perform their functions in respect of such persons assessed to Income-tax or surtax or interest tax in the Income-tax Wards, Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding entries in column 2 thereof as are aggrieved by any of the orders mentioned in clauses (a) to (h) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax Act, 1961, in sub-section (1) of section 11 of Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964) and in sub-section (1) of section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also in respect of such persons or classes of persons as the Board has directed or may direct in future in accordance with the provisions of clause (1) of sub-section (2) of section 246 of the Income-tax, Act, 1961.

SCHEDULE

Charges with Headquarers	Income-tax Wards/Circles/ Districts/Ranges
1	2
1. Commissioner of Income-tax (Appeals)-I, New Delhi	1. IAC (Assessment), Range-XVII, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-VI-A, New Delhi) and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range.
	2. IAC, Range-VI-B, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-I-B, New Delhi) and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range
	3. IAC, Range-VI-C, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-I-C, New Delhi) and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range.
	4. IAC, Companies Range-II, New Delhi (formerly designated as IAC, Rango-I-D, New Delhi) and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range.
	5. IAC (Assessment) Range-XIII, New Delhi and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range.
2. Commissioner of Income-tax (Appeals)-V, New Delhi	1. IAC (Assessment) Range XVIII, New Delhi (formerly designated as Company Circle-XXI, New Delhi) and all Wards/Circles/Districts within the jurisdiction of that Range

1	2
	2. IAC, Range-IV-A, New Delhi and all wards/Circles Districts within the jurisdiction of that Range.
	3. IAC, Range-IV-B, New Delhi and all Wards/Districts/Circles within the jurisdiction of that Range.
	4. IAC, Companies Range-I, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-I I-A, New Delhi) and all Wards/Circles/District within the jurisdiction of that Range.
	5. IAC (Assessment) Range-I, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-I-E, New Delhi) and all Wards/Circles / Districts within the jurisdiction of that Range.
	6. IAC (Assessment), Range-II, New Delhi (formerly designated as IAC, Range-I-F, New Delhi and all Wards / Circles / Districts within the jurisdiction of that Range.

Whereas Income-tax Ward, Circle, District or Range or part thereof stands transferred by this Notification from one charge to another charge, appeals arising out of assessments made in that Income-tax Ward, Circle, District or Range or part thereof and pending immediately before the date of this Notification before the Commissioner of Income-tax (Appeals of the Charge from whom the Income-tax Ward, Circle, District or Range or part thereof is transferred, are to be dealt with by the Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge to whom the said Ward, Circle, District or Range or part thereof is transferred.

This notification shall take effect retrospectively from 21-8-1983.

[No. 5614 (F. No. 261/10/83-ITJ)
K.M. SULTAN, Under Secy.
Central Board of Direct Taxes

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1984

(आयकर)

का०आ० 1132—यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने गुजरात-I, गुजरात-II, गुजरात-III, बड़ौदा, सूरत तथा राजकोट के आयकर आयुक्तों के समवर्ती क्षेत्राधिकार आयकर आयुक्त (जांच), गुजरात, अहमदाबाद को प्रदत्त किये हैं, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 121 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, एतद्द्वारा निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट आयकर आयुक्त, जिसका प्रधान कार्यालय उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में अकेले कार्यों का निर्वहण करेगा और गुजरात-I, गुजरात-II, गुजरात-III, बड़ौदा, सूरत तथा राजकोट के आयकर आयुक्त उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) में यथाउल्लिखित मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में कार्य नहीं करेंगे ।

अनुसूची

आयकर आयुक्त	प्रधान कार्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3
जांच, गुजरात, अहमदाबाद	अहमदाबाद	(क) विशेष परिमंडल, अहमदाबाद सर्वेक्षण परिमंडल, अहमदाबाद विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, राजकोट विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, बड़ौदा विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, सूरत विशेष सर्वेक्षण परिमंडल, जामनगर सर्वेक्षण परिमंडल और विशेष सर्वेक्षण परिमंडल का क्षेत्राधिकार निम्नलिखित मामलों के संबंध में आयकर आयुक्त (जांच) द्वारा उन्हें सौंपे गये प्रादेशिक क्षेत्रों में निहित होगा :— (क) वे सभी नये मामले, जहां विवरणियां स्वेच्छा या दाखिल की गई हों और जिनमें विगत में कोई कर निर्धारण नहीं किया गया हो। (ख) वे सभी नये मामले, जिनमें पहले कोई कर-निर्धारण नहीं किया गया हो और जिनमें धारा 139(2)/148 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाने हों । परन्तु सर्वेक्षण परिमंडल के आ०क० अधिकारी ऐसे मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं रखेंगे, जहां प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से पूर्व कम से कम एक कर निर्धारण पूरा कर लिया गया हो और ऐसे मामले उस तारीख से गुजरात-I, गुजरात-II, गुजरात-III, बड़ौदा, राजकोट और सूरत के आयकर आयुक्तों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रीय आ०क० अधिकारियों को अंतरित समझे जायेंगे । (ख) आयकर आयुक्त, गुजरात-I, गुजरात-II, गुजरात-III, बड़ौदा, सूरत तथा राजकोट के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण की सामान्य शक्तियां ।

1	2	3
		(ग) सर्वेक्षण से अथवा अन्यथा उत्पन्न होने वाले नये मामलों के निपटान के लिये आयकर आयुक्त (जांच) द्वारा, उसे धारा 124(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, सृजित कोई परिमंडल तथा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से ऐसे मामलों के संबंध में राज्य क्षेत्रीय आ० क० अधिकारियों का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा। तथापि, कंपनियों, लोक पूर्त न्यासों, वेतन भोगी कर-निर्धारितियों और वापसी परिमंडलों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के संबंध में क्षेत्राधिकार यथापूर्व निहित रहेगा।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1984 से लागू होगी।

[सं० 5714/फा०सं० 187/27/83-आ०क० (नि०-I)]

आर०के० तिवारी, अवर सचिव,
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर-बोर्ड

New Delhi, the 13th March, 1984

Income-Tax

S.O. 1132.—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the I.T. Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes have conferred on Commissioner of Income-tax (Investigation) Gujarat, Ahmedabad jurisdiction concurrent with those of the Commissioners of Income-tax, Gujarat-I, Gujarat-II, Gujarat-III, Baroda, Surat and Rajkot the Central Board of Direct Taxes in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 121 and in supersession of all previous orders in this regard, hereby directs that the Commissioner of Income-tax specified in Column (1) of the Schedule hereto annexed with head-quarters specified in Column (2) thereof shall alone perform function in respect of such cases or classes of cases as are referred to in Column (3) of the said schedule and the Commissioners of Income-tax, Gujarat-I, Gujarat-II, Gujarat-III, Baroda, Surat and Rajkot shall not exercise functions over the cases or classes of cases as are referred to in Column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

Commissioner of Income-tax	Headquarter	jurisdiction
1	2	3
Investigation Gujarat, Ahmedabad.	Ahmedabad	(A) Special Circles, Ahmedabad. Survey Circles, Ahmedabad. Special Survey Circle, Rajkot. Special Survey Circles Baroda Special Survey Circle, Surat Special Survey Circle, Jamnagar. The jurisdiction of the Survey Circles and Special Survey Circles will be in the territorial areas assigned to them by the Commissioner of Income-tax (Investigation) over :—
		(a) All new cases where returns are filed voluntarily and in which no assessment has been framed in the past. (b) All new cases where no assessments have been framed in the past and where notices under section 139 (2)/148 are to be issued. Provided that the I.T.Os Survey Circles will cease to have jurisdiction over such cases where at least one assessment has been made before 1st April of each year and such cases will stand transferred to the territorial I.T.Os within jurisdiction of Commissioners of Income-tax-Gujarat-I, Gujarat-II, Gujarat-III, Baroda, Rajkot and Surat on that date. (B) General powers of survey in respect of areas comprised in the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Gujarat-I, Gujarat-II, Gujarat III, Baroda, Surat and Rajkot. (C) Any Circles created by Commissioner of Income-tax (Investigation) under the powers vested in him by Section 124(1) to deal with new cases arising out of survey or otherwise and the territorial I.T.O. will have no jurisdiction over such cases from the date to be notified. However, in respect of companies, Public Charitable Trusts Salaried assessees and cases falling under the refund circles, the jurisdiction will continue to vest as hitherto before.

This notification shall take effect from 1st April, 1984.

[No. 5714 (F. No. 187/27/83-IT(AI)]

R. K. TEWARI, Under Secy
Central Board of Direct Taxes

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का०आ० 1133—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार,

श्री प्रेम प्रकाश शर्मा के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री वी०के० सिबल को एतद्द्वारा केनरा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है ।

[संख्या एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(1)]

गुरदेव सिंह, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1133.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri V. K. Sibal, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Canara Bank vice Shri P. P. Sharma.

[No. F. 9/46/83-BO. I(1)]

GURDEV SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 मार्च, 1984

का०आ० 1134.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अरुण सिन्हा के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार को एतद्द्वारा यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(2)]

New Delhi, the 14th March, 1984

S.O. 1134.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the United Bank of India vice Shri Arun Sinha.

[No. F. 9/46/83-BO. I(2)]

का०आ० 1135.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अरुण सिन्हा के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली की उप सचिव सुश्री ताजवर रहमान को एतद्द्वारा देना बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(3)]

S.O. 1135.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 the Central Government hereby appoints Sushri Tajwar Rahman, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Dena Bank vice Shri Arun Sinha.

[No. F. 9/46/83-BO. I(3)]

का०आ० 1136.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना, 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अशोक कुमार के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री देवेन्द्र राज मेहता को एतद्द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(5)]

S.O. 1136.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Devendra Raj Mehta, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Union Bank of India vice Shri Ashok Kumar.

[No. F. 9/46/83-BO. I(5)]

का०आ० 1137.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री एस०एस० हसूरकर के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार को एतद्द्वारा सिंडीकेट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(4)]

S.O. 1137.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Kumar, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Syndicate Bank vice Shri S. S. Hasurkar.

[No. F. 9/46/83-BO. I(4)]

का०आ० 1138.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री देवेन्द्र राज मेहता के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री अशोक चन्द्र को एतद्द्वारा बैंक आफ महाराष्ट्र के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ०-9/46/83-बी०ओ०-I(6)]

S.O. 1138.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Chandra, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Bank of Maharashtra vice Shri Devendra Raj Mehta.

[No. F. 9/46/83-BO. I(6)]

का०आ० 1139.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1980 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अशोक चन्द्र के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के उप सचिव श्री प्रेम प्रकाश शर्मा को एतद्द्वारा आन्ध्र बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(7)]

S.O. 1139.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri Prem Prakash Sharma, Deputy Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi as a Director of the Andhra Bank vice Shri Ashok Chandra.

[No. F. 9/46/83-BO. I(7)]

का०आ० 1140.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1980 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री च०वा० मीरचन्दानी के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के निदेशक श्री एस०एस० हसूरकर को एतद्द्वारा कारपोरेशन बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ०-9/46/83-बी०ओ०-I(8)]

बी० के० सिबल, संयुक्त सचिव

S.O. 1140.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri S. S. Hasurkar, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Corporation Bank vice Shri C. W. Mirchandani.

[No. F. 9/46/83-BO. I(8)]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

का०आ० 1141.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1980 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री वी०के० सिबल के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के निदेशक श्री एन० बालसुब्रह्मण्यन को एतद्द्वारा न्यू बैंक आफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० एफ० 9/46-83-बी०ओ०-I(9)]

गुरदेव सिंह, अवर सचिव

S.O. 1141.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri N. Balasubramanian, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division), New Delhi as a Director of the New Bank of India vice Shri V. K. Sibal.

[No. F. 9/46/83-BO. I(9)]

GURDEV SINGH, Under Secy.

का०आ० 1142.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1980 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री देवेन्द्र राज मेहता के स्थान पर वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के निदेशक श्री एस०एस० हसूरकर को एतद्द्वारा ओरियंटल बैंक आफ कामर्स के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/46-83-बी०ओ०-1(10)]

S.O. 1142.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri S. S. Hasurkar, Director, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Oriental Bank of Commerce vice Shri D. R. Mehta.

[No. F. 9/46/83-BO. I(10)]

का०आ० 1143.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1980 की धारा 3 की उपधारा (ज) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, श्री अरुण सिन्हा के स्थान पर वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री अशोक चन्द्र को एतद्द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[संख्या एफ० 9/46/83-बी०ओ०-I(11)]

बी० के० सिबल, संयुक्त सचिव

S.O. 1143.—In pursuance of sub-clause (h) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, the Central Government hereby appoints Shri Ashok Chandra, Joint Secretary, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi as a Director of the Punjab and Sind Bank vice Shri Arun Sinha.

[No. F. 9/46/83-BO. I(11)]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1984

का० आ० 1144.—केन्द्रीय सरकार की निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि घरेलू विद्युत् उपकरणों का निर्यात से पूर्व निरीक्षण किया जाये;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिये नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाये हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त उप-नियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं सं० का०आ० 2304 तारीख 16 जुलाई, 1977 और का०आ० 1593 तारीख 19 मई, 1979 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित करती है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव भेजने का इच्छुक कोई व्यक्ति उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर, (11वीं मंजिल) 26, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008, को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि घरेलू विद्युत् उपकरणों का निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण किया जायेगा;

(2) क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को इस आदेश के उपाबन्ध 'क' में दिये गये घरेलू विद्युत् उपकरण निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो निर्यात से पूर्व ऐसे घरेलू विद्युत् उपकरण को लागू होगा।

(3) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों को घरेलू विद्युत् उपकरण के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना।

(4) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में ऐसे घरेलू विद्युत् उपकरणों के निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक के द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि ऐसे घरेलू विद्युत् उपकरण क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं और निर्यात योग्य हैं या उन पर उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिन्ह या मोहर लगा है;

2. इस आदेश की कोई बात भावी खेपों को भूमि, समुद्री या वायु मार्ग द्वारा घरेलू विद्युत् उपकरण के वास्तविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी।

3. इस आदेश में "घरेलू विद्युत उपकरण" से नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित कोई भी उपकरण अभिप्रेत है;

अनुसूची

क्रम० सं०	घरेलू विद्युत् उपकरण
1.	विद्युत् इमरशन जल उष्मायक
2.	संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत् हीटर
3.	घरेलू एवं उसके समक्ष प्रयोजनों के लिये स्विच
4.	विद्युत् प्रेस
5.	विद्युत् स्टोव
6.	विद्युत् हॉट प्लेट
7.	घरेलू विद्युत् खाद्य मिश्रक (द्रव मिश्रक तथा ग्राईंडर)
8.	विद्युत् टोस्टर
9.	विद्युत् कॉफी परकोलेटर (बिना रेग्यूलेटर के)
10.	घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिये विद्युत् केतली और जग।
11.	कपड़े धोने की घरेलू विद्युत् मशीन (बिना स्वचालित के)
12.	विद्युत् रेडिएटर
13.	पानी उबालने का विद्युत् यंत्र
14.	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत् यंत्र।
15.	खाना पकाने के घरेलू विद्युत् ओवन
16.	मुख्य परिचालित विद्युत् शेवर
17.	स्टीम प्रैस
18.	घरेलू प्रयोग के लिये हीटिंग पैड के नम्य विद्युत् यंत्र।
19.	सुवाह्य मुख्य हस्तचालित मसाजर।
20.	सुवाह्य धीमी गति वाली खाद्य मिश्रक मशीन
21.	संयोजक उपकरण तथा लगाये हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के, तीन पिन) संयोजक उपकरण
22.	संयोजक उपकरण तथा लगाये हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन प्रकार के पिन) प्रवेशिक उपकरण।
23.	विद्युत् जल हीटर के साथ प्रयुक्त थर्मोस्टेट।
24.	सोर्ला की तरह तापन अवयव।
25.	हीटिंग एलिमेंट के लिये प्रतिरोधक तार, पट्टियां तथा धारियां।
26.	अन्तःस्थापित प्रकार के ठोस हीटिंग एलिमेंट।
27.	खनिज से भरा आवृत्त हीटिंग एलिमेंट।
28.	विद्युत् ओवन के सामान्य प्रयोग के लिये थर्मोस्टेट।
29.	अभ्रक युक्त उष्मारोधी हीटिंग एलिमेंट
30	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिये स्विच 2 ए, एम पी एस।
31.	विद्युत् के सुवाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रैकिट।
32	तीन पिन प्लग तथा सार्किट निगम।
33.	लचकदार सामान से बनाये हुए तीन पिन प्लग
34.	बेयोनेट लैंप होल्डर।
35.	क्षणिक पानी गर्म करने के लिये विद्युत् हीटर।
36.	एक सतही बेकिंक ओवन।

उपाबंध—"क"

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम घरेलू विद्युत् उपकरण का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,:—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित कोई निर्यात निरीक्षण अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) "घरेलू विद्युत उपकरण" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में वर्णित कोई उपकरण अभिप्रेत है।

3. निरीक्षण का आधार:—निर्यात के लिए घरेलू विद्युत उपकरणों का निरीक्षण यह देखने के विचार से किया जाएगा कि घरेलू विद्युत उपकरण अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों अर्थात् राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक तथा निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानकों के अनुरूप है।

या

(क) यह सुनिश्चित करके किया जाएगा कि उत्पादों का विनिर्माण इस अधिसूचना के उपाबंध-1 में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादन के दौरान आवश्यक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके किया गया है।

या

(ख) इस अधिसूचना के उपाबंध-II में विनिर्दिष्ट ढंग से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर किया जाएगा।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया:—(1) घरेलू विद्युत उपकरणों के परेषण का निर्यात करने का इच्छुक निर्यातकर्ता निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देश का ब्यौरा देते हुए, अभिकरण को लिखित सूचना देगा जिससे अभिकरण नियम 3 के अनुसार निरीक्षण कर सके;

(2) घरेलू विद्युत उपकरणों का निर्यात करने के लिए जिनका विनिर्माण उपाबंध-I में अधिकथित उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके और परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह न्याय निर्णित करके कि उत्पादन के दौरान यूनिट में पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण क्रियें है किया गया है, निर्यातकर्ता उपनियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह घोषणा भी देगा कि निर्यात के लिए आशयित घरेलू विद्युत उपकरणों के परेषण का विनिर्माण उपाबंध-I में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग करके किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता अभिकरण को निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।

(4) उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी, जब कि उपनियम (2) के अधीन घोषणा सहित सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उप नियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन घोषणा, यदि कोई हो की प्राप्ति पर अभिकरण :—

(क) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माता ने उपाबंध-1 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के संबंध में परिषद्/अभिकरण द्वारा जारी कि

गए अनुदेशों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है, तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है वहां भी परेषण का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन तथा या निरीक्षण यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है।

अभिकरण निर्यात के लिए आशयित कुछ परेषणों की स्थल पर ही जांच करेगा और विनिर्माण एककों द्वारा अपनाई गयी उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियाओं की पर्याप्तता का सत्यापन करने के लिए नियमित अंतरालों पर विनिर्माण एकक में जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक में विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों का प्रयोग नहीं किया गया है या परिषद्/अभिकरण की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किया गया है तो यह घोषणा कर दी जाएगी कि यूनिट के पास उत्पादन के दौरान पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण क्रियाएं नहीं हैं। ऐसे मामलों, में, यदि यूनिट ऐसा चाहे तो उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण क्रियाओं की पर्याप्तता को बनाए रखने के बारे में अधिनिर्णय करने के लिए फिर से आवेदन करेगा।

(ख) जहां निर्यातकर्ता ने उपनियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि उपाबंध-1 में अधिकथित पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया वहां वह अपना यह समाधान करने पर कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है उपाबंध-II में यथा अधिकथित किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर ऐसे किए गए निरीक्षण के सात दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है:

परन्तु जहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां वह घोषित करते हुए कि घरेलू विद्युत उपकरणों का परेषण निर्यात योग्य है, प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार कर देगा और ऐसे इंकार किए जाने की सूचना निर्यात कर्ता को उसके कारणों सहित सात दिनों के भीतर दे दी जाएगी।

(ग) उस दशा में, जहां विनिर्माता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उपनियम (5) (ख) के अधीन निरीक्षण किया गया है, वहां अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् तुरन्त परेषण में से पैकेजों को इस रीति से मुहरबंद करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मुहरबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं की जा सकती है। परेषण के अस्वीकृत किए जाने की दशा में यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण, अभिकरण द्वारा मुहरबंद नहीं किया जाएगा परन्तु ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृति के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. निरीक्षण का स्थान :—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण—

(क) ऐसे उत्पादों के विनिर्माता के परिसर पर, या (ख) उन परिसरों पर किया जाएगा कि जहां निर्यातकर्ता द्वारा माल प्रस्तुत किया जाता है परन्तु यह तब जब कि वहां निरीक्षण के लिए अपेक्षित सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस :—यथास्थिति विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नानुसार दी जाएगी :—

(1) नियम 3 (क) के अधीन निरीक्षण करने के लिए न्यूनतम 20-रु० प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2% की दर से।

(2) नियम 3 (ख) के अधीन निरीक्षण करने के लिए न्यूनतम 20-रु० रुपए प्रति परेषण के अधीन रहते हुए, पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4% की दर से।

(3) (1) और (2) में दी गयी निरीक्षण फीस पर 10% की छूट उन लघु उद्योग एककों को दी जाएगी जो संबंधित राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के पास रजिस्ट्रीकृत हैं।

7. मान्यता प्राप्त चिन्ह का चिपकाना और उसकी प्रक्रिया भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) 1955 और भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के उपाबंध निर्यात से पूर्व घरेलू विद्युत उपकरणों पर मान्यताप्राप्त चिन्ह या सील चिपकाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा संभव लागू होंगे और इस चिन्हित घरेलू विद्युत उपकरण निर्यात से पूर्व नियम 3 के अधीन किसी भी निरीक्षण के अधीन नहीं होंगे।

8. अपील—(1) नियम 4 के उपनियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे इंकार किए जाने की सूचना प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञों के पैनल को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात व्यक्तियों से मिलकर बना होगा अपील कर सकेगा।

(2) पैनल में विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के दो-तिहाई सदस्य गैर-सरकारी होंगे।

(3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।

(4) अपील इसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपबंध—1

[नियम 3(क) देखिए]

विनिर्माता, घरेलू विद्युत उपकरण का क्वालिटी नियंत्रण इससे संलग्न अनुसूची-II में दिए गए नियंत्रण के स्तरों सहित अभिकथित उत्पादों के विनिर्माण, संरक्षण तथा पैकिंग के विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित नियंत्रणों को लागू करते हुए प्रयोग करेगा।

1 क्रय की गयी सामग्री तथा संघटकों का नियंत्रण :—(क) विनिर्माता प्रयुक्त किए जाने वाली सभी सामग्री या संघटकों की विशेषताओं और सह्यताओं सहित विस्तृत विमाओं को समाविष्ट करते हुए, क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करते हुए, उत्पादक का परीक्षण प्रमाण-पत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाण-पत्र के न होने पर क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुरूपता की जांच करने के लिए प्रत्येक परेषण में से नमूनों की नियमित जांच की जाएगी उत्पादक के परीक्षण प्रमाण-पत्र की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए पांच परेषणों में से कम से कम एक की पुनः जांच की जाएगी।

(ग) आने वाले परेषण का निरीक्षण और परीक्षण, सांख्यिकी नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।

(घ) निरीक्षण और परीक्षण किए जाने के पश्चात् दोषों के निपटाने तथा उचित पृथक्करण के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट नियंत्रणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप से रखे जाएंगे।

2. प्रक्रिया नियंत्रण :—(क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।

(ग) प्रक्रमित सामग्री की प्रक्रिया विनिर्देशों के साथ अनुरूपता की जांच के लिए नमूना (जहां कहीं अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(घ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान अपनाए गए नियंत्रणों का सत्यापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखे जाएंगे।

3. उत्पाद नियंत्रण :—(क) मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(ख) परीक्षण के लिए नमूना लिया जाना (जहां अपेक्षित है) अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) विनिर्माता किए गए परीक्षणों के संबंध में पर्याप्त अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप में रखेगा।

4. माप संबंधी नियंत्रण:—उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त मेजों और उपकरणों की कालिकजांक या अंशशोधन किया जाएगा और अभिलेख वृत्तकार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

5. परिरक्षण नियंत्रण :—(क) विनिर्माता उत्पाद को मौसम के प्रतिकूल प्रभावों से सुरक्षित करने के लिए विस्तृत विनिर्देश अधिकथित करेगा।

(ख) उत्पादों को भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

6 पैकिंग नियंत्रण —उत्पाद(दों) की पैकिंग तथा निर्यात किए जाने वाले पैकेजों के लिए विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे और उनका कठोरता से पूर्णतया पालन किया जाएगा।

उपाबंध-II

(नियम 3(ख) देखिए)

1. घरेलू विद्युत उपकरणों के परेषणों का निरीक्षण तथा परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप हैं।

2. नमूना लेने और अनुरूपता के मानदण्डों के संबंध में संविदात्मक विनिर्देशों में किसी विशिष्ट अनुबंध के न होने की दशा में वहीं अनुबंध लागू होंगे जो नीचे दी गयी सारणी में अधिकथित हैं।

2.1 सारणी—1 में दिए गए लाटों में से चुने गए नमूनों के लिए सुसंगत राष्ट्रीय मानकों में दिए गए स्वीकृत परीक्षण किए जाएंगे और लाटों को सारणी-1 में दिए गए अनुरूपता के मानदंडों के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा।

सारणी—1

नमूना आकार और पुष्टि के लिए मानदण्ड

लाट आकार	प्रथम नमूना	द्वितीय नमूना	स्वीकृत संख्या	प्रथम अस्वीकृत संख्या	द्वितीय अस्वीकृत संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50 तक	5	5	0	2	2
51 से 100 तक	8	8	0	2	2
101 से 300 तक	13	13	0	2	2
301 से 500 तक	20	20	0	2	3
501 और अधिक	32	32	0	3	4

नोट :—लाट में एक परेषण में एक ही बनावट, माडल तथा प्रकार के एकत्रित किए गए सभी उपकरण अभिप्रेत हैं।

2.2 चुनाव की बेतरतीबी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आई० एस० 4905-1968 में दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

2.3 सारणी-1 के स्तंभ-1 तथा II के अनुसार एक साथ चुने गए उपकरणों का अलग-अलग उपकरण विनिर्देश में विनिर्दिष्ट स्वीकृत परीक्षण किया जाएगा। कोई भी उपकरण स्वीकृत परीक्षणों में से किसी का भी समाधान करने में असमर्थ होता है तो उसे दोषपूर्ण समझा जाएगा। यदि नमूने में दोषों की संख्या स्वीकृत संख्या (स्तंभ 4 देखें) के बराबर या कम पाई जाती है तो लाट को अपेक्षाओं के अनुरूप समझा जाएगा और यदि नमूने में दोषों की संख्या पहली अस्वीकृति संख्या (स्तंभ 5-देखिए) के बराबर या अधिक है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यदि दोषों की संख्या स्वीकृत संख्या और पहली अस्वीकृत संख्या के मध्य आती है तो उसी आकार का दूसरा नमूना (स्तंभ 3 देखिए) उसी समय लिया जाएगा और परीक्षण किया जाएगा। यदि दोषों की संख्या मिश्रित नमूनों में दूसरी अस्वीकृत संख्या (स्तंभ 6 देखिए) के बराबर या अधिक पाई जाती है तो लाट अस्वीकृत कर दिया जाएगा अन्यथा स्वीकृत कर दिया जाएगा।

2.4 निरीक्षण करने के पहले अभिकरण अपना समाधान कर लेगा कि प्रत्येक उपकरण पर ऐसे दैनिक परीक्षण जो कि सुसंगत मानक दिए गए हैं, नियंतिकर्ता विनिर्माता द्वारा परेषण पर कर लिया गया है।

2.5 विनिर्माता नियंतिकर्ता द्वारा निरीक्षण के लिए दिये गए एक ही प्रकार तथा दर के उपकरणों के बस निरन्तर परेषणों के (या एक वर्ष में कम से कम एक बार) एक में से दो नमूने लिए जाएंगे और मान विनिर्देशों में दिए गए अनुसार प्रकार परीक्षण किया जाएगा और दोनों नमूनों को प्रकार परीक्षण में पास होना चाहिए।

2.6 परीक्षण की पद्धति:—यदि निर्यात संविदा में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है तो परीक्षण प्रक्रिया सुसंगत राष्ट्रीय मानक विनिर्देश के अनुसार या भारतीय मानक विनिर्देशों का नवीनतम रूपान्तर होगी। अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देश के अधीन नमूनों के सभी परीक्षण किए जाएंगे।

अनुसूची 1

क्रम सं०	घरेलू विद्युत उपकरण
1.	विद्युत इमरशन जल उष्मायक
2.	संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत् हीटर
3.	घरेलू एवं उसके समरूप प्रयोजनों के लिए स्विच
4.	विद्युत् प्रेस
5.	विद्युत् स्टोव

क्रम सं०	घरेलू विद्युत उपकरण	क्रम सं०	घरेलू विद्युत उपकरण
6.	विद्युत् हॉट प्लेट	22.	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन प्रकार के पिन) प्रवेशिकक उपकरण।
7.	घरेलू विद्युत् खाद्य मिश्रक (ड्रय मिश्रक तथा ग्राईंडर)	23.	विद्युत् जल हीटर के साथ प्रयुक्त थर्मोस्टाट।
8.	विद्युत टोस्टर	24.	गोली की तरह तापन अवयव।
9.	विद्युत काफी परकोलेटर (बिना रेग्यूलेटर के)	25.	हीटिंग एलिमेंट के लिए प्रतिरोधक तार, पट्टियां तथा धारियां।
10	घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिए विद्युत् केतली और जग।	26.	अन्तः स्थापित प्रकार के ठोस विद्युत् हीटिंग एलिमेंट।
11.	कपड़े धोने की घरेलू विद्युत् मशीन (बिना स्वचालित् के)	27.	खनिज से भरा आवृत्त फीटिंग एलिमेंट ।
12.	विद्युत् रेडिएटर	28.	विद्युत् ओवन के सामान्य प्रयोग के लिए थर्मोस्टट
13.	पानी उबालने का विद्युत् यंत्र	29.	अभ्रक युक्त उष्मारोधी हीटिंग एलिमेंट
14.	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत् यंत्र	30.	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिए स्विच 2 ए एम पी एस
15.	खाना पकाने के घरेलू विद्युत् ओवन	31.	विद्युत् के सुग्राह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रेकिट।
16.	मुख्य परिचालित विद्युत् शेवर	32.	तीन पिन प्लग तथा साकिट-निर्गम।
17.	स्टीम प्रेस	33.	लचकदार सामान्य से बनाए हुए तीन पिन प्लग।
18.	घरेलू प्रयोग के लिए हीटिंग पैड के नम्य विद्युत् यंत्र।	34.	बेयोनेट लैंप होल्डर।
19.	सुग्राह्य मुख्य हस्तचालित मसाजर।	35.	अणिक पानी गर्म करने के लिए विद्युत् हीटर।
20.	सुग्राह्य धीमी गति वाली खाद्य मिश्रक मशीन।	36.	एक सतही बेकिंग ओवन।
21.	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन) संयोजक उपकरण।		

अनुसूची-II

(उपाबंध 1 देखें)

नियंत्रण के स्तर

(उत्पाद के लिए लागू मान्य मानकों के सीमित परीक्षण)

क्रम सं०	निरीक्षण/परीक्षण की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूना आकार	लॉट आकार	टिप्पण
1	2	3	4	5	6
1.	कच्ची सामग्री और खरीदे गए संघटक				
	(क) चाक्षुष निरीक्षण (कार्य कौशल और फिनिश सहित)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(ख) विमाएं (i) क्रान्तिक (ii) अन्य	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए	प्रत्येक लॉट	
	(ग) संघटकों के लिए विद्युत परीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए	प्रत्येक लॉट	
	(घ) अन्य कोई अपेक्षाएं	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलिखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।	प्रत्येक लॉट	
2.	दैनिकी परीक्षण				
	सुसंगत मानक विनिर्देशों में दिए गए अन्य कोई परीक्षण तथा उपयुक्तता पर निर्भर होते हुए, विनिर्माण यूनिटों में उत्पादित प्रत्येक उपकरण पर दैनिकी परीक्षण किया जाएगा ।				
	(क) चाक्षुष जांच तथा निरीक्षण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण		
	(ख) विद्युत घात से सुरक्षा	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण		

1	2	3	4	5	6
	(ग) उच्च वोल्टता परीक्षण (फ्लैश परीक्षण)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण		
	(घ) उष्मारोधी प्रतिरोधी परीक्षण (शुष्क)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक उपकरण		
	(ङ) भू योजन संपर्क	मानक विनिर्देशो के अनुसार	प्रत्येक उपकरण		
3.	स्वीकृत परीक्षण उपयुक्तता पर निर्भर रहते हुए यहा नीचे वर्णित उपकरणों पर निम्नलिखित ग्राह्य परीक्षण किए जाएंगे ।				
	(1) विद्युत इमरशन जल उष्मायक	मानक विनिर्देशो के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणो के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) नमी परीक्षण				
	(2) संग्रहणी प्रकार के स्वचालित विद्युत जल हीटर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) दाब परीक्षण				
	(iii) मूल क्षमता				
	(iv) तापमान वृद्धि				
	(v) निवेश				
	(vi) स्थिर हानि				
	(vii) अंशकालिक डायल का विचलन				
	(3) घरेलू एवं उसके समक्ष प्रयोजनों के लिए स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणो के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) नमी प्रतिरोधता				
	(iii) सम्पर्क रोध तथा तापमान वृद्धि				
	(iv) उच्च वोल्टता तथा अधिक करेंट धारिता				
	(v) क्षमता परीक्षा				
	(vi) एसीद्वैरक परिपथ के लिए स्विच				
	(vii) यान्त्रिक शक्ति				
	(viii) अधिकतम खिंचाव				
	(4) विद्युत प्रेस	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाल करेंट (गर्म)				

1	2	3	4	5	6
	(iii) नमी प्रतिरोध				
	(iv) निवेश				
	(v) तापमान वृद्धि				
	(vi) उष्मा समय				
	(vii) सोलप्लेट तापमान का माप				
(5)	विद्युत स्टोव	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
(6)	विद्युत हाट प्लेट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोध				
	(iv) निवेश				
	(v) तापमान सीमा				
	(vi) थर्मल दक्षता				
(7)	घरेलू विद्युत खाद्य मिश्रक (द्रव मिश्रक तथा ग्राइंडर)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) निवेश				
	(ii) विद्युत उष्मारोध तथा परिचालित तापमान पर रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोध				
	(iv) उष्मारोधी प्रतिरोध विद्युत क्षमता				
	(v) परिचालन परीक्षण				
	(vi) बाउल के लिए सह परीक्षण तापमान				
(8)	विद्युत टोस्टर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोध				
	(iv) निवेश टोस्टिंग परीक्षण				
	(v) टोस्टिंग परीक्षण				
	(vi) तापमान सीमा				
(9)	घरेलू और सामान्य प्रयोग के लिए विद्युत केतली तथा जग	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) परिचालित तापमान पर विद्युत ऊष्मारोधन, रिसाव करेंट (गर्म)				
	(ii) नमी प्रतिरोध				

1	2	3	4	5	6
	(iii) निवेश				
	(iv) उबालने की दशीय क्षमता का समय				
	(v) तापमान वृद्धि				
(10)	विद्युत काफी परकोलेटर (बिना रेगुलेटर के)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) तापमान प्रतिरोध				
	(vi) थर्मल क्षमता				
(11)	कपड़े धोने की घरेलू विद्युत मशीन (बिना स्वचालित)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) निवेश				
	(v) तापमान वृद्धि				
	(vi) निष्पादन				
(12)	घरेलू रेडिएटर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) नमी प्रतिरोधकता				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) निष्पादन				
	(vi) रिसाव करेंट				
(13)	पानी उबालने का विद्युत यंत्र	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) नमी प्रतिरोधकता				
(14)	केश सुखाने का मुख्य परिचालित विद्युत यंत्र	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) तापमान वृद्धि				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) उच्च वोल्टता				
	(iv) नमी प्रतिरोधता				

1	2	3	4	5	6
	(v) निवेश				
	(vi) उष्मारोधी प्रतिरोध (गर्म)				
	(vii) असामान्य परिचालन				
	(viii) थर्मस्टेट तथा थर्मल का निष्पादन				
	(ix) आरम्भ				
	(x) निष्पादन				
	(xi) क्षमता परीक्षा				
(15)	खाना पकाने के घरेलू विद्युत ओवन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) निवेश				
	(iv) तापमान की एकसमरूपता				
	(v) तापमान वृद्धि				
(16)	मुख्य परिचालित विद्युत शेवर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) अधिक तथा कम वोल्टता पर संचालन				
	(iv) नमी प्रतिरोधता				
	(v) तापमान सीमा				
(17)	स्टीम प्रेस	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) निवेश				
	(v) तापमान सीमा				
(18)	घरेलू प्रयोग के लिए हीटिंग पैड के लिए विद्युत यंत्र	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) दबाव सहायता				
	(ii) डाइइलैक्ट्रिक क्षमता				
	(iii) उष्मारोधी प्रतिरोध				
	(iv) निवेश				
	(v) मतल ताप				
	(vi) नमी प्रतिरोधता				
	(vii) जल सह (केवल जल सह पैड पर लागू)				
(19)	सुखाने, मुख्य हस्तचालित विद्युत समाजर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) उच्च वोल्टता तथा निम्न वोल्टता पर संचालन				

1	2	3	4	5	6
	(iv) नमी प्रतिरोधता				
	(v) तापमान सीमा				
	(vi) निष्पादन				
	(vii) अति भार पर संचालन				
	(viii) नियमित संचालन				
	(ix) निवेश				
	(x) स्टार्टिंग				
(20)	सुखाद्य धीमी गति वाली खाद्य ग्राइंडरिंग मशीन	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) फिनिश				
	(ii) गिराव (ग्रीले ग्राइंडर के लिए)				
	(iii) सहतापमान (केवल प्लास्टिक तथा कागज के हापर के लिए)				
	(iv) रिसाव करेंट				
	(v) उच्च वोल्टता				
	(vi) नमी प्रतिरोधता				
	(vii) निवेश				
	(viii) तापमान वृद्धि				
	(ix) संचालन तथा निष्पादन				
(21)	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (अप्रतिवर्ती प्रकार के तीन पिन) संयोजक उपकरण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) विमाओं का विस्तार				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) प्रभावकारी स्पर्श				
	(iv) निकासी खींचना				
	(v) नमी प्रतिरोधता				
	(vi) तापमान सीमा				
	(vii) क्षमता				
(22)	संयोजक उपकरण तथा लगाए हुए उपकरण (बिना प्रतिवर्ती के तीन प्रकार के पिन) प्रवेशिका उपकरण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) विमाओं का विस्तार				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
(23)	पानी गर्म करने वाले विद्युत हीटर के प्रयोग के लिए थर्मोस्टेट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) उष्मीय विशेषताएं				
(24)	गोली की तरह तापन अवयव (बिना अन्तःस्थापित प्रकार)	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) निवेश				

1	2	3	4	5	6
(25)	हीटिंग ऐलिमेंट के लिए प्रतिरोधक तार, पट्टियां तथा धारियां	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) भौतिक दशा				
	(ii) भौतिक विमाएं				
	(iii) काम करने का अधिकतम तापमान				
	(iv) तनन विशेषताएं				
	(v) प्रतिरोधता				
	(vi) प्रतिरोधता की एकरूपता				
	(vii) लपेटना				
	(viii) क्षमता परीक्षा				
(26)	अन्त: स्थापित प्रकार का ठोस विद्युत हीटिंग ऐलिमेंट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) रिसाव करेंट				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
(27)	खनिज से भरा आवृत हीटिंग ऐलिमेंट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) रिसाव करेंट				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) निवेश				
	(v) उष्मारोधी प्रतिरोधता				
	(vi) हाइड्रोस्टेटिक दबाव				
(28)	विद्युत् ओवन के सामान्य प्रयोग के लिये थर्मोस्टेट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) रिसाव करेंट				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) अंशशोधन परिशुद्धता तथा विभेदक				
	(v) श्रेणी (रेंज)				
(29)	अभ्रक उष्मारोधी हीटिंग ऐलिमेंट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए ।		
	(i) रिसाव करेंट				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
(30)	घरेलू तथा सामान्य प्रयोगों के लिये स्विच	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये ।		
	(i) उच्च वोल्टता				
	(ii) नमी प्रतिरोधता				
	(iii) सम्पर्क प्रतिरोधता तापमान वृद्धि				
	(iv) अधिक वोल्टता तथा अधिक करेंट धारिता				
	(v) क्षमता परीक्षा				
	(vi) यांत्रिक शक्ति				
	(vii) ऐसी प्रेरण परिपथ				

1	2	3	4	5	6
(31)	विद्युत के सुवाह्य लैंप स्टैंड तथा ब्रेकिट	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) परिचालन परीक्षण				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) रिसाव करेंट				
	(iv) तापमान सीमा				
	(v) नमी प्रतिरोधता				
	(vi) स्विचों के लिये परीक्षण				
(32)	तीन पिन प्लग तथा साकेट निर्गम	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।		
	(i) विनिमय योग्यता				
	(ii) उच्च वोल्टता				
	(iii) नमी प्रतिरोधता				
	(iv) तापमान वृद्धि				
	(v) टूटन क्षमता				
	(vi) ऊष्मारोधी प्रतिरोधता				
	(vii) यांत्रिक शक्ति				
	(viii) सम्पर्क का प्रभाव				
	(ix) क्षमता परीक्षा (केवल शटर के लिए)				
	(x) निकासी खिंचाव				
(33)	लचकदार सामान से बनाए हुए तीन पिन प्लग	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) विनिमय योग्यता				
	(ii) ऊष्मारोधी प्रतिरोधक				
	(iii) उच्च वोल्टता				
	(iv) नमी प्रतिरोधता				
	(v) तापमान वृद्धि				
	(vi) टूटन क्षमता				
	(vii) यांत्रिक शक्ति				
	(viii) कान्टेक्ट का प्रभाव				
(34)	बेयोनेट लैम्प होल्डर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) तेज परख				
	(ii) ऊष्मारोधतक प्रतिरोधक				
	(iii) उच्च वोल्टता				
	(iv) तनन परीक्षण				
	(v) मूसल दबाव परीक्षण				
	(vi) नियन्त्रक रस्सी				
(35)	क्षणिक पानी गर्म करने के लिये विद्युत हीटर	मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।		
	(i) दबाव				
	(ii) तापमान वृद्धि				
	(iii) निवेश				
	(iv) रिसाव करेंट				
	(v) उच्च वोल्टता				
	(vi) स्विच प्रवाह का संचालन				
	(vii) निकासी जल तापमान				

1	2	3	4	5	6
(36) एक परत बेकिंग ओवन		मानक विनिर्देशों के अनुसार अभिलिखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाए।			
(i) उच्च वोल्टता					
(ii) रिसाव करेंट					
(iii) निवेश					
(iv) तापमान की एकरूपता					
(v) तापमान की वृद्धि					
4. प्रकार परख					
संगत मानक विनिर्देशों में दिये गये इन परीक्षण तथा उपयुक्तता पर निर्भर होते हुए निम्नलिखित प्रकार परीक्षण किया जायेगा।					
(i) अग्नि प्रतिरोधक विशेषताएं		मानक विनिर्देशों के अनुसार अभिलिखित अन्वेषणों के आधार पर नियत किया जाये।			जहां और जैसे कच्ची सामग्री का प्रकार बदला जाता है जैसे हीटिंग ऐलिमेंट आदि तो सभी प्रकार के परीक्षण के लिये दो नमूनों का परीक्षण किया जायेगा
(ii) रगड़ के लिये काल परीक्षण					
(iii) विकर्षण की प्रतिरोधता					
(iv) यान्त्रिक दाब					
(v) टिकाऊपन					
(vi) बहुमुखी केबलों तथा रस्सी के लिए परीक्षण					
(vii) पुर्जों के बीच कोई गार्ड और संबंधित विस्थापन					
(viii) पेंच और संयोजक					
(ix) सिरे					
(x) यान्त्रिक शक्ति					
(xi) जंग प्रतिरोधता					
(xii) फिनिश के लिये परीक्षण					
(xiii) तापमान वृद्धि					
(xiv) संचालन तापमान पर विद्युत् उष्मा-रोधम रिसाव करेंट (गर्म)					
(xv) नमी प्रतिरोधक					
(xvi) उष्मारोधी प्रतिरोधक, रिसाव करेंट (ठण्डा) तथा विद्युत् शक्ति					
(xvii) निवेश					
(xviii) स्लका					
(xix) असाधारण संचालन					
(xx) दूरी तथा स्पष्टीकरण तथा निकासी					
(xxi) तापस्थायी तथा उष्मा रोक का निष्पादन					
(xxii) अधिक भार के अधीन संचालन तथा उच्च वोल्टता सुरक्षात्मक यंत्र के लिये परीक्षण					
(xxiii) मोटर संचालन उपकरण का आरम्भ					
(xxiv) क्षमता परीक्षा					

[नं० 6(5)/82-ई०आई०एण्डई०पी०]

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 7th April, 1984

S.O. 1144.—Whereas the Central Government is of the opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient so to do for the development of the export trade of India that the Household Electrical Appliances should be subjected to inspection prior to export;

And, whereas, the Central Government has formulated the proposal specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce Nos. S.O. 2304, dated the 16th July, 1977 and S.O. 1593, dated the 19th May, 1979, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days from the date of publication of this order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, Municipal Market Building (4th floor), 3, Saraswati Marg, Karol Bagh, New Delhi-110005.

PROPOSALS

1. To notify that Household Electrical Appliances shall be subject to quality control and inspection prior to export;

2. To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Household Electrical Appliances (Quality Control and Inspection) Rules, 1983 set out in Annexure 'A' to this Order as the type of quality control and inspection, which shall be applied to such Household Electrical Appliances prior to export;

3. To recognise National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council, as the standard specifications for the Household Electrical Appliances;

4. To prohibit the export in the course of international trade of such Household Electrical Appliances unless the same are accompanied by a certificate issued by any one of the agencies recognised or established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), to the effect that the Household Electrical Appliances satisfy the conditions relating to quality control and inspection and are exportworthy or carry a mark or seal recognised by the Central Government under section 8 of the Act;

2. Nothing in this order shall aply to the export by land, sea or air of bonafide samples of Hosehold Electrical Appliances to prospective buyers.

3. In this order, Household Electrical Applicances shall mean any of the appliances mentioned in the Schedule given below :—

SCHEDULE

S. No

Hoschold Electrical Appliances

1. Electric immersion water heaters.
2. Storage type automatic electric water heaters.
3. Switches for domestic and similar purposes.
4. Electric Irons.
5. Electric Stoves.
6. Electric Hot Plates.
7. Domestic Electric Food Mixers liquidizers, blenders and grinders.
8. Electric Toasters.
9. Electric Coffee Percolaters (Non-regulator type).
10. Electric Kettels and Jugs for household and similar use.
11. Domestic Electric Clothes Washing Machine (Non-automatic).
12. Electric radiators.
13. Electric water boilers.
14. Mains-operated electric hair dryers.
15. Domestic electric cooking ovens.
16. Mains-operated electric shavers.
17. Steam Irons.
18. Flexible, Electric Heating Pads for domestic use.
19. Portable hand-held mains-operated electric massagers
20. Portable low speed food grinding machine.
21. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors.
22. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance inlets.
23. Thermostats for use with Electric Water Heaters.
24. Catridge type heating elements (non-embeded type).
25. Resistance Wires, tapes and strips for heating elements
26. Solid embeded type electric heating elements.
27. Mineral filled sheathed heating elements.
28. Thermostats for general purpose electric ovens.
29. Mica insulated heating elements.
30. 2 Amps. switches for domestic and similar purposes.
31. Electric portable lamp stands and brackets.
32. Three pin plugs and socket-outlets
33. Three pin plugs made of resilient materials.
34. Bayonet lampholders.
35. Electric instantaneous water heaters.
36. Single walled baking oven.

ANNEXURE 'A'

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Household Electrical Appliances (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any of the Export Inspection Agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras under section 7 of the Act;

(c) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(d) "Household Electrical Appliances" means any of the appliances mentioned in Schedule—I annexed to these rules.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Household Electric Appliances for export shall be carried out with a view to seeing that the Household Electrical Appliances conform to the specification recognised by the Central Government under section 6 of the Act namely the National and International Standards and Standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council;

Either

(a) by ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Annexure I to this notification,

or

(b) on the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Annexure II to this notification.

4. Procedure of inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Household Electrical Appliances shall give an intimation in writing to the agency furnishing

therein details of the contractual specification alongwith a copy of the export contract or order to enable the agency to carry out inspection in accordance with rule 3;

(2) For export of Household Electrical Appliances manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Annexure I and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a Panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the exporter shall also furnish along with the intimation mentioned in sub-rule (1) a declaration that the consignment of Household Electrical Appliances intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Annexure-I and that the consignment conforms to the standard specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while in the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the declaration, if any, under sub-rule (2), the agency—

(a) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality controls as laid down in Annexure I and followed the instructions if any issued by the Council/Agency in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall within three days issue a certificate declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthy. In case where the manufacturer is not the exporter, however the consignment shall be physically verified and such verification and or inspection if necessary shall be carried out by the agency to ensure that the above conditions are complied with.

The agency shall however carry out the spotcheck of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit. If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council/Agency, the unit shall be declared as not having adequate inprocess quality control drills. In such cases, the unit if so desires shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter has not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Annexure I had been exercised, on satisfying itself that the consignment of Household Electrical Appliances conforms to the standard specification recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Annexure II, shall within seven days of carrying out such inspection issue a certificate declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthy.

Provided that where the agency is not so satisfied it shall refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of Household Electrical Appliances as exportworthy and shall communicate such refusal within seven days to the exporter alongwith the reason therefor.

(6) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule (5) (a) or consignment is inspected under sub-rule (5) (b), the agency shall, immediately, after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tempered with. In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the agency but in such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of inspection.— Every inspection under these rules shall be carried out either—(a) at the premises of the manufacturer of such products; or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter provided required facilities for inspection exists therein.

6. Inspection fee.—The inspection fee shall be paid by the manufactures/exporters to the agency as under :

(1) For inspection under rule 3(a) @ 0.2 per cent of f.o.b. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment

(2) For inspection under rule 3(b) @ 0.4 per cent of f.o.b. value subject to minimum of Rs. 20 per consignment.

(3) A rebate of 10 per cent on the rate of inspection fee given in (1) and (2) shall be given to small scale units registered with the concerned State Governments or Union Territories.

7. Affixation or recognised mark and procedure thereof. The provisions of the Indian Standards Institution (Certification Mark) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standards Inspection (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955 shall so far as may apply in relation to the procedure of affixation of the recognised mark or seal on Household Electrical Appliances prior to export and Household Electrical Appliances so marked shall not be subject to any inspection under rule 3.

8. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the referred of the agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may within 10 days of the receipt of the communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts constituting of not less than three but not more than seven persons appointed for the purpose by the Central Government.

(2) The Panel shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership of the panel of experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed off within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE-I

(See under rule 3(a))

The quality control of the Household Electrical Appliances shall be exercised by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, prevention and packing of the products as laid down together with the levels of control as set out in Schedule II appended hereto.

1. Bought out materials and components control.—(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

(b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificate, samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counterchecked at least once in five consignments to verify the correctness.

(c) The incoming consignment shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

(d) After inspection and tests are carried out, systematic methods shall be adopted for proper segregation and disposal of defectives.

(e) Adequate records in respect of the above mentioned controls shall be systematically maintained.

2. Process Control.—(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specification.

(c) Sampling (Wherever required) for checking the conformity of the processed materials with the process specifications shall be based upon the recorded investigation.

(d) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls adopted during the process of manufacture.

3. Product Control.—(a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specification.

(b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on recorded investigations.

(c) Adequate records in respect of tests carried out shall regularly and systematically maintained by the manufacturer.

4. Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control.—(a) A detailed specification shall be laid down by the manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather condition.

(b) The products shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control.—Specifications shall be laid down for packing the product(s) and as well as for export packages and the same shall be strictly adhered to.

ANNEXURE-II

(See under rule 3(b))

1. The consignments of Household Electrical Appliances shall be subjected to inspection and testing to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of any specific stipulation in the contractual specifications as regards sampling and criteria of conformity, the same as laid down below shall become applicable.

2.1 The acceptance tests as given in the relevant national standards shall be carried out on the samples selected from the lots as given in Table I and the lots shall be accepted or rejected on the basis of criterion for conformity given in *Table I*.

TABLE—I

Sample size and Criterion for Conformity

Lot Size	First Sample	Second Sample	Acceptance Number	First rejection Number	Second rejection Number
1	2	3	4	5	6
Upto 50	5	5	0	2	2
51 to 100	8	8	0	2	2
101 to 300	13	13	0	2	2
301 to 500	20	20	0	2	3
501 and above	32	32	0	3	4

Note.—The lot shall mean all appliances of the same make, model and type grouped together in a consignment.

2.2 In order to ensure the randomness of selection, procedure given in IS : 4905—1968 shall be followed.

2.3 The appliances selected at random according to col. 1 and 2 of Table I, shall be subjected to the acceptance tests specified in the individual appliance specification. An appliance failing to satisfy any of the acceptance tests, shall be considered as defective. The lot shall be considered as conformity to the requirements if the number of defectives found in sample is less than or equal to the acceptance number (see col. 4) and shall be rejected if it is greater than or equal to the first rejection number (see col 5). If the number of defectives lies between the acceptance number and first rejection number, the second sample of the same size (see col. 3) shall be chosed at random and tested. If the number of defectives found in the combined samples is greater than or equal to the second rejection number (see col. 6), the lot shall be rejected, otherwise the lot shall be accepted.

2.4 Before undertaking the inspection, the Agency shall satisfy itself that the routine tests on each appliance as given in the relevant standard have been crried out on the consignment by the exporter/manufacturer.

2.5 Two samples out of one of ten consecutive consignment (or at least once in a year) of Household Electrical Appliances of same type and rating offered for inspection by exporter/manufacturer shall be drawn and tested for type tests as given in the standard specifications and both the samples should pass the type tests.

2.6 Methods of testing.—If not otherwise specified in the export contract, the testing procedure shall be as prescribed in the relevant national or latest version of Indian Standard Specifications. The samples shall be subjected to all tests as per standard specification recognised under section 6 of the Act.

SCHEDULE I

Sl. No.

Household Electrical Appliances

1. Electric immersion water heaters.
2. Storage type automatives electric water heaters.
3. Switches for domestic and similar purposes.
4. Electric Irons.
5. Electric Stoves.
6. Electric Hot Plates.
7. Domestic Electric Food Mixers (Liquidizers, blenders and grinders.
8. Electric Toasters.
9. Electric Coffee Percolaters (Non-regulator type).
10. Electric Kettels and Jugs for household and similar use.
11. Domestic Electric Clothes Washing Machine (Non-automatic).
12. Electric radiators.
13. Electric water boilers.
14. Mains-operated electric hair dryers.
15. Domestic electric cooking ovens.
16. Mains-operated electric shavers.
17. Steam Irons.
18. Flexible, Electric Heating Pads for domestic use.
19. Portable, hand-held mains-operated electric masseagers.
20. Portable low speed food grinding machine.
21. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance connectors.
22. Appliance-connectors and appliance inlets (non-reversible three pin type) Appliance inlets.
23. Thermostats for with Electric Water Heaters.
24. Catridge typo heating elements (non-embeded type).
25. Resistance Wires, tapes and strips for heating elements
26. Solid embeded type electric heating elements.
27. Mineral filled sheathed heating elements.
28. Thermostats for general purpose electric ovens.
29. Mica insulated heating elements.
30. 2 Amps. switches for domestic and similar purposes.
31. Electric portable lamp stands and brackets.
32. Three pin plugs and socket-outlets.
33. Three pin plugs made of resilient materials.
34. Bayonet lampholders.
35. Electric instantaneous water heaters.
36. Single walled baking oven.

SCHEDULE II

(See Annexure I)

LEVELS OF CONTROLS

(Tests restricted to recognised standards as applicable to the products)

Sl. No.	Particulars of Inspection/Test	Requirements	Sample Size	Lot Size	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	RAW MATERIAL & BOUGHT OUT COMPONENTS				
	(a) Visual Inspection (including workmanship and finish).	As per Standard Specification.	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(b) Diamensions	-do-	-do-	Each lot	
	(i) Critical				
	(ii) Others				
	(c) Electrical tests for components	-do-	-do-	-do-	
	(d) Any other requirements	-do-	-do-	-do-	
(2)	ROUTINE TESTS Depending upon the applicability and any other test as given in the relevant standard specification following routine tests will be carried out on each appliance produced in the manufacturing unit.				
	(a) Visual examination and inspection	As per standard Specification	Each Appliance		
	(b) Protection against electric shock	-do-	-do-		
	(c) High Voltage Test (Flash Test)	-do-	-do-		
	(d) Insulation resistance test (dry)	-do-	-do-		
	(e) Earthing connection	-do-	-do-		
	ACCEPTANCE TESTS Followig acceptance tests shall be carried out on the appliance mentioned hereunder; depending upon the applicability				
	(1) Electric Immersion Water Heaters	As per Standard Specification	To be fixed on the basis of recorded investigation.		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Input				
	(iv) Temperature Limit				
	(v) Moisture resistance.				
	(2) Storage type automatic electric water heaters	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Pressure test				
	(iii) Actual capacity				
	(iv) Temperature rise				
	(v) Input				
	(vi) Standing loss				
	(vii) Deviation of dial calibration.				
	(3) Switches for domestic and similar purposes	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Moisture resistance				
	(iii) Contact resistance and temperature rise				
	(iv) Overvoltage and over-current capacity				
	(v) Eudurance				
	(vi) Switches for ac inductive circuits				
	(vii) Mechanical strength				
	(viii) Maximum pull				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(4) Electric Irons	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current (hot)				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Temperature rise				
	(vi) Heating-up time				
	(vii) Measurement of soleplate temperature				
	(5) Electric Stoves	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Temperature Limit				
	(vi) Thermal efficiency.				
	(6) Electric Hot Plates	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Temperature limit				
	(vi) Thermal efficiency				
	(7) Domestic Electric Food-Mixers (Liquidizers and Grinders)	-do-	-do-		
	(i) Input				
	(ii) Electrical insulation and Leakage current at operating Temperature.				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Insulation resistance and electric strength				
	(v) Operational tests				
	(vi) Temperature Withstand test for bowl.				
	(8) Electric Toasters	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Moisture resistance				
	(iv) Input				
	(v) Toasting test				
	(vi) Temperature Limit				
	(9) Electric Kettels and Jugs for Household and similar use.	-do-	-do-		
	(i) Electrical insulation at operating temperature, leakage current (hot).				
	(ii) Moisture resistance				
	(iii) Input				
	(iv) Time to boil rated capacity				
	(v) Temperature-rise.				
	(10) Electric Coffee Percolaters (Non-regulator type).	-do-	-do-		
	(i) High voltage				
	(ii) Leakage current				
	(iii) Input				
	(iv) Temperature limit				
	(v) Moisture resistance				
	(vi) Thermal efficiency				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(11)	Domestic Electric Clothes Washing Machine (non-automatic). (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature rise (vi) Performance	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation		
(12)	Electric Radiators (i) High voltage (ii) Moisture resistance (iii) Input (iv) Temperature-limit (v) Performance (vi) Leakage current	-do-	-do-		
(13)	Electric Water Boilers (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Temperature limit (v) Moisture resistance	-do-	-do-		
(14)	Mains Operated Electric Hair Dryers (i) Temperature rise (ii) Leakage current (iii) High voltage (iv) Moisture resistance (v) Input (vi) Insulation resistance (hot) (vii) Abnormal operation (viii) Performance of thermostats and thermal cutouts. (ix) Starting (x) Performance (xi) Endurance	-do-	-do-		
(15)	Domestic electric cooking ovens (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Uniformity of temperature (v) Temperature rise	-do-	-do-		
(16)	Mains-operated Electric Shavers (i) High Voltage (ii) Leakage current (iii) Operation at over and under Voltage. (iv) Moisture resistance (v) Temperature limit	-do-	-do-		
(17)	Steam Irons (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Temperature Limit	-do-	-do-		
(18)	Flexible Electric Heating Pads for Domestic Use. (i) Strain relief (ii) Dielectric strength (iii) Insulation resistance (iv) Input (v) Surface temperature (vi) Moisture resistance (vii) Waterproofness (applicable to Waterproof pads only).	-do-	-do-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(19)	Portable, hand-hold mains-operated electric massagers. (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Operation at overvoltage and undervoltage. (iv) Moisture resistance (v) Temperature limit (vi) Performance (vii) Opration under overload (viii) Abnormal operation (ix) Input (x) Starting	To be standard specification	To be fixed on the basis of recered investigation		
(20)	Portable Low speed Food Grinding Machine. (i) Fish (ii) Spillage (for wet grinder) (iii) Temperature withstand (for plastic and glass hoppers only). (iv) Leakage current (v) High voltage (vi) Moisture resistance (vii) Input (viii) Temperature-rise (ix) Operation and performance	-do-	-do-		
(21)	Appliance-connectors and Appliance Inlets (Non-reversible three pin type) Appliance Connectors. (i) Guaging of dimensions (ii) High voltage (iii) Effectiveness of contacts (iv) Withdrawal pull (v) Moisture resistance (vi) Temperature limit (vii) Breaking capacity.	-do-	-do-		
(22)	Appliance-connectors and appliance Inlet (non-reversible three pin type) Appliance Inlets. (i) Guaging of dimensions (ii) High voltage (iii) Moisture resistance	-do-	-do-		
(23)	Termostate for use wih Electric Water Heaters (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Temperature limit (v) Thermal characteristics	-do-	-do-		
(24)	Cartridge type heating elements, (non-embeded type) (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance (iv) Input	-do-	-do-		
(25)	Resistance Wires, tapes and strips for heating elements (i) Physical condition (ii) Physical dimensions (iii) Maximum working temperature (iv) Tensile properties (v) Resistance (vi) Uniformity of resistance (vii) Wrapping (viii) Endurance	-do-	-do-		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(26)	Solid embeded type electric heating elements. (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Moisture resistance	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation		
(27)	Mineral filled sheathed heating elements (i) Leakage current (ii) High voltage (iii) Moisture resistance (iv) Input (v) Insulation resistance (vi) Hydrostatic pressure.	-do-	-do-		
(28)	Thermostats for general purpose electric ovens (i) Leakage current (ii) High voltage (iii) Moisture resistance (iv) Calibration accuracy and differential (v) Range	-do-	-do-		
(29)	Mica insulated heating elements (i) Leakage current (ii) High voltage (iii) Moisture resistance	-do-	-do-		
(30)	2 Amps. switches for domestic and similar purposes (i) High voltage (ii) Moisture resistance (iii) Contact resistance and temperature-rise (iv) Overvoltage and overcurrent capacity (v) Endurance (vi) Mechanical Strength (vii) Ac Inductive Circuits	-do-	-do-		
(31)	Electric portable lamp Stands and brackets (i) Operational test (ii) High voltage (iii) Leakage current (iv) Temperature limit (v) Moisture resistance (vi) Test for switches	-do-	-do-		
(32)	Three pin plugs and socket-outlets (i) Interchangeability (ii) High voltage (iii) Moisture resistance (iv) Temperature-rise (v) Breaking capacity (vi) Insulation resistances (vii) Mechanical strength (viii) Effectiveness of contact (ix) Endurance (for shutters only) (x) Withdrawal pull.	-do-	-do-		
(33)	Three pin plugs made of resilient materials (i) Interchangeability (ii) Insulation resistance (iii) High voltage (iv) Moisture resistance (v) Temperature rise (vi) Breaking capacity	-do-	-do-		

1	2	3	4	5	6
	(vii) Mechanical strength (viii)Effectiveness of contact	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation		
(34)	Bayonet lampholders (i) Gauge test (ii) Insulation resistance (iii) High voltage (iii) High voltage (iv) Tension test (v) Plunger depression test (vi) Cord-grip				
(35)	Electric instantaneous water heaters (I) Pressure withstand (ii) Temperature rise (iii) Input (iv) Leakage current (iv) High voltage (iv) Operation of flow switch (vii) Outlet Water temperature	-do-	-do-		
(36)	Single walled baking oven (i) High voltage (ii) Leakage current (iii) Input (iv) Uniformity of temperature (v) Temperature rise	-do-	-do-		
	4. TYPE TESTS Depending upon the applicability of the tests as given in the relevant standard specifications, following type tests will be carried out—				
	(i) Fire resisting properties (ii) Ageing test for Fubber (iii) Resistance to tracking (iv) Mechanical hazards (v) Stability (vi) Test for multiple supply cables and cord grip (vii) Cord guard and relative displacement between parts (viii) Screw and connections (ix) Terminals (x) Mechanical strength (xi) Resistance to rusting (xii) Test for finish (xiii) Temperature rise (xiv) Electrical insulation at operating temperature, leakage current (hot) (xv) Moisture resistance (xvi) Insulation resistance, leakage current (cold) and electric strength (xvii) Input (xviii) Spillage (xix) Abnormal operation (xx) Creepage distances and clearances (xxi) Performance of thermostats and thermal cut-outs (xxii) Operation under overload conditions and test for overload protective device (xxiii) Starting of motor-operated appliances. (xxiv) Endurance	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation with a minimum of two samples.		As and when the type of raw material is changed viz. heating element etc., two samples shall be tested for all the type tests and they shall pass before production of applicance of made out of new material is commenced.

[No. 6(5)/82- EI&EP]

आदेश

का० आ० 1145.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है कि उच्चताप सह ईंटों को निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन रखा जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं तथा उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को भेज दिया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त उप नियम के अनुसरण में और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 2516 तारीख 22 अगस्त, 1966 को अधिक्रांत करते हुए, उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है, जिनके उनसे, प्रभावित होने की संभावना है।

2. सूचना दी जाती है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रस्तावों के बारे में कोई आक्षेप या सुझाव देना चाहता है तो वह उसे इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद्, प्रगति टावर (11वीं मंजिल) 26, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

(1) यह अधिसूचित करना कि इस आदेश से संलग्न उपाबंध-1 में उल्लिखित उच्चताप सह ईंट निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन होगी;

(2) (क) राष्ट्रीय और अन्तरर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानकों को मान्यता देना।

(ख) उच्चताप सह ईंटों के लिए निर्यात संविदा में तय पाए गए विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा यथा घोषित विनिर्देशों को उक्त उच्चताप सह ईंटो के लिए मानक विनिर्देशों के रूप में मान्यता देना, परन्तु यह तब तक कि वे उक्त (क) से निम्न न हों।

टिप्पण :—(1) जब निर्यात संविदा, ब्यौरे वार तकनीकी अपेक्षाओं को उपवर्णित नहीं करती है या वह केवल नमूनों पर आधारित है तो, निर्यातकर्ता लिखित विनिर्देश देगा।

(2) परीक्षणों की पद्धति राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगी

(3) इस आदेश से संलग्न उपाबंध 11 में उपवर्णित उच्चताप ईंटों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1983 के प्रारूप के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में विनिर्दिष्ट करना जिसे निर्यात से पूर्व ऐसी उच्चताप सह ईंटों को लागू किया जाएगा।

(4) ऐसा उच्चताप सह ईंटों के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के उपक्रम में निर्यात को तब तक प्रतिषिद्ध करना जब तक कि उसके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र न हो कि उच्चताप सह ईंटें क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण से संबंधित शर्तों को पूरा करती है तथा निर्यात योग्य है।

3. इस आदेश की कोई भी बात प्रभावी क्षेत्राओं को भूमि, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा उच्चताप सह ईंटों के ऐसे सदभाविक नमूनों के निर्यात को लागू नहीं होगी जिनका पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1000 रु० से अधिक न हो।

4. इस आदेश में उच्चताप सह ईंटों से अभिप्रेत है। इस आदेश के उपाबंध-1 में उल्लिखित किसी भी आकार की कोई उच्चताप सह ईंट।

उपाबंध-1

इस आदेश में, "उच्चताप सह ईंटों" से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है :—

1. अग्निसह मिट्टी की उच्चतापसह ईंटें
2. आधारी उच्चतापसह ईंटें
3. सिलिका उच्चतापसह ईंटें
4. अम्ल प्रतिरोधी उच्चतापसह ईंटें
5. सिलिमेनाइट ईंटें
6. उच्च एल्युमिना ईंटें
7. रोधी ईंटें

उपाबंध-2

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 के अधीन बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का प्रारूप।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) न नियमों का संक्षिप्त नाम उच्चतापसह ईंटों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1983 है।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो :—

(क) "अधिनियम" निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है;

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन स्थापित अभिकरणों में से कोई एक अभिप्रेत है—

(ग) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद् अभिप्रेत है;

(घ) उच्चतापसह ईंटों से निम्नलिखित में से कोई अभिप्रेत है :—

1. अग्निसह मिट्टी की उच्चतापसह ईंटें
2. आधारी उच्चतापसह ईंटें
3. सिलिका उच्चतापसह ईंटें
4. अम्ल प्रतिरोधी उच्चतापसह ईंटें
5. सिलिमेनाइट उच्चतापसह ईंटें
6. उच्च एल्युमिन ईंटें
7. रोधी ईंटें

3. निरीक्षण का आधार : निर्यात के लिए उच्चतापसह ईंटों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि उच्चतापसह ईंटें अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के, अर्थात् (क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों और निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानकों के या (ख) निर्यात संविदा में तय पाए गए विनिर्देशों के रूप में निर्यातकर्ता द्वारा घोषित विनिर्देशों के, परन्तु यह तब तक कि वे (क) से निम्न न हों, अनुरूप है;

(1) यह सुनिश्चित करने के कि उत्पादों का विनिर्माण, निरीक्षण की प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण प्रणाली के अधीन आने वाले एककों की बाबत, इस अधिसूचना के परिशिष्ट-क में यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके किया गया है।

(2) निरीक्षण की परेषणावार प्रणाली के अधीन आने वाले एककों की बाबत इन नियमों के परिशिष्ट-ख में विनिर्दिष्ट रीति से किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर

4. निरीक्षण की प्रक्रिया : (1) उच्चतापसह ईंटों के परेषण का निर्यात करने का आशयित निर्यातकर्ता अधिकरण को निर्यात संविदा या आदेश की एक प्रति के साथ संविदात्मक विनिर्देशों का ब्यौरा देते हुए लिखित रूप में सूचना देगा ताकि अभिकरण नियम 3 के उपबंधों के अनुसार निरीक्षण कर सकें।

(2) परिशिष्ट-क में यथा अधिकथित यथोचित प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित उच्चतापसह ईंटों के निर्यात के लिए और इस प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा गठित विशेषज्ञों के पैनल द्वारा यह निर्णय करने पर कि विनिर्माण एककों के पास यथोचित प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण ट्रिलें हैं, निर्यातकर्ता उप नियम (1) में उल्लिखित सूचना के साथ यह भी घोषणा करेगा कि निर्यात के लिए आशयित उच्चतापसह ईंटों का परेषण परिशिष्ट-क में यथा अधिकथित यथोचित क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके विनिर्मित किया गया है और परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निर्यातकर्ता निर्यात किए जाने वाले परेषण पर लगाए जाने वाले पहचान चिह्न अभिकरण को देगा।

(4) उपरोक्त उप नियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना विनिर्माता के परिसर से परेषण के भेजे जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दी जाएगी जबकि उप-नियम (2) के अधीन घोषणा, सहित सूचना के मामले में विनिर्माता के परिसर से परेषण को भेजे जाने से कम से कम तीन दिन पूर्व दी जाएगी।

(5) उप-नियम (1) के अधीन सूचना और उपनियम (2) के अधीन अधीन घोषणा यदि कोई हो, प्राप्त होने पर—

(क) (i) अभिकरण, अपना यह समाधान हो जाने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान विनिर्माता ने परिशिष्ट क में यथा अधिकथित यथोचित क्वालिटी नियंत्रणों का प्रयोग और इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए इस संबंध में परिषद् या अभिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों, यदि कोई हो, का पालन किया था, तीन दिन के भीतर यह घोषणा करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा कि उच्चतापसह ईंटों का परेषण निर्यात योग्य है।

(ii) ऐसे मामले में जहां विनिर्माता निर्यातकर्ता नहीं है, तथापि परेषण का प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन किया जाएगा और ऐसा सत्यापन तथा/या निरीक्षण, यदि आवश्यक हो, अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए लिए किया जाएगा कि उपरोक्त शर्तों का पालन किया गया है।

(iii) किन्तु अभिकरण निर्यात के लिए अभिप्रेत परेषणों में से कुछ परेषणों की स्थल पर जांच करेगा और विनिर्माण एककों द्वारा अपनाई गई प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण ट्रिलों की प्रयोज्यता के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए नियमित अन्तरालों पर एककों का निरीक्षण भी करेगा।

(iv) यदि यह पाया जाता है कि विनिर्माण एकक, विनिर्माण के किसी भी प्रक्रम पर अपेक्षित क्वालिटी नियंत्रण उपायों को नहीं अपना रहा है या परिषद् या अभिकरण की सिफारिशों का पालन नहीं कर रहा है, तो यह घोषित किया जाएगा कि एकक के पास यथोचित प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण ट्रिलें नहीं है और ऐसे मामलों में, यदि एकक ऐसा चाहे तो, वह प्रक्रियात्मक क्वालिटी नियंत्रण ट्रिलों की पर्याप्तता के अनुरक्षण का निर्णय करने के लिए फिर से आवेदन करेगा।

(ख) ऐसे मामले में जहां निर्यातकर्ता के उप-नियम (2) के अधीन यह घोषित नहीं किया है कि परिशिष्ट-क में यथा अधिकथित यथोचित क्वालिटी नियंत्रण का प्रयोग किया गया था वहां परिशिष्ट-ख में यथा अधिकथित किए गए निरीक्षण और परिक्षण के आधार पर जहां यह समाधान हो जाने पर कि उच्चतापसह ईंटों का परेषण इस प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है, ऐसा निरीक्षण किए जाने के सात दिन के भीतर यह घोषित करते हुए प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उच्चतापसह ईंटों का परेषण निर्यात योग्य है,

परन्तु यहां अभिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहां, वह निर्यातकर्ता को यह घोषित करने वाला प्रमाणपत्र की उच्चतापसह ईंटों का परेषण निर्यात योग्य है, सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर जारी करने से इंकार कर देगा और कारणों सहित ऐसे इंकार की संसूचना निर्यातकर्ता को देगा।

(ग) (i) ऐसे मामलों में जहां विनिर्माता उपनियम (5) (क) के अधीन निर्यातकर्ता नहीं है या परेषण का उपनियम (5) (ख) के अधीन निरीक्षण किया गया है वहां, अभिकरण निरीक्षण की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् परेषण के पैकेजों को ऐसी रीति में सीलबंद करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि सीलबंद पैकेजों में फेरबदल नहीं की जा सकती है।

(ii) परेषण की अस्वीकृति की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो परेषण को अभिकरण द्वारा सीलबंद नहीं किया जा सकेगा। किंतु, ऐसे मामलों में निर्यातकर्ता अस्वीकृत के विरुद्ध कोई अपील करने का हकदार नहीं होगा।

5. निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के अधीन प्रत्येक निरीक्षण का सो

(क) ऐसे उत्पाद के विनिर्माता के परिसरों पर किया जाएगा या

(ख) ऐसे परिसरों पर किया जाएगा जहां निर्यातकर्ता ने निरीक्षण के लिए माल प्रस्तुत किया है, परन्तु यह तब तक कि वहां इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान हों।

6. निरीक्षण फीस : प्रत्येक परेषण के लिए कम से कम 75 रु के अधीन रहते हुए, इन नियमों के अधीन ऐसे परेषण के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के प्रत्येक 100 रु के लिए 75 पैसे की दर से फीस निरीक्षण फीस के रूप में संदत्त की जाएगी।

7. अपील—(i) नियम (4) के उप नियम (5) के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाणपत्र जारी करने से इंकार किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने के दस दिन के भीतर ऐसे विशेषज्ञों के पैनल को, जिसमें कम से कम तीन किन्तु सात से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया जा सकेगा। अपील कर सकेगा।

(2) विशेषज्ञों के पैनल में कुल सदस्यता के कम से कम दो तिहाई सदस्य अशासकीय होंगे।

(3) विशेषज्ञों के पैनल की गणपूर्ति तीन होगी।

(4) अपील, उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी।

परिशिष्ट-क

क्वालिटी नियंत्रण

उच्चतापसह ईंटों का क्वालिटी नियंत्रण विनिर्माता द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में यथा उपवर्णित संक्रम-स्तरों सहित नीचे यथाअधिकथित उत्पादन के विनिर्माण परिरक्षण और पैकिंग के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा।

(i) क्रय और कच्ची सामग्री नियंत्रण :—

(क) प्रयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री के गुण धर्म सम्मिलित करते हुए क्रय विनिर्देश विनिर्माता द्वारा अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) स्वीकृत परेषणों के साथ क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की पुष्टि करते हुए या तो प्रदायकर्ता का परिक्षण तथा निरीक्षण प्रमाण पत्र होगा जिस दशा में नैमित्तिक जांच किसी विशिष्ट प्रदायकर्ता के लिए श्रेत्रा द्वारा 10 परेषणों में से कम से कम एक बार

पूर्वोक्त परीक्षण या निरीक्षण प्रमाण पत्रों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए की जाएगी या क्रय की गई सामग्री का या तो कारखाने के भीतर प्रयोगशाला में या बाहर के किसी प्रयोगशाला या परीक्षण गृह में नियमित रूप से परीक्षण तथा निरीक्षण किया जाएगा।

(ग) किए जाने वाले निरीक्षण या परीक्षण के लिए नमूना अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत सामग्री को पृथक् करने और अस्वीकृत सामग्री का निपटान करने के लिए व्यवस्थित पद्धति अपनाई जाएगी।

(ङ) पूर्वोक्त नियंत्रणों की बाबत यथोचित अभिलेख विनिर्माता द्वारा नियमित और व्यवस्थित रूप से बनाए रखे जाएंगे।

(ii) प्रक्रिया नियंत्रण

(क) विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों के लिए विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) प्रक्रिया विनिर्देशों में यथा अधिकथित प्रक्रिया के नियंत्रण के लिए उपस्कर और उपकरण की सुविधाएं पर्याप्त होंगी।

(ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों के सत्यापन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माता द्वारा पर्याप्त अभिलेख बनाए रखे जाएंगे।

टिप्पण :—भा. मा. : 1528 (भाग-VII)—1974 के प्रतिनिर्देश से विनिर्माण प्रक्रिया के नेमी नियंत्रण के लिए सिफारिश की गई है।

(iii) उत्पाद नियंत्रण

(क) विनिर्माता के पास यह जांच करने के लिए कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है या तो अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच अन्यथा विद्यमान परीक्षण सुविधाएं तक होंगी।

(ख) किए जाने वाले परीक्षण और निरीक्षण के लिए नमूना अभिलिखित अन्वेषणों पर आधारित होगा।

(ग) नमूने और किए जाने वाले परीक्षण की बाबत यथोचित अभिलेख नियमित और व्यवस्थित रूप से बनाए रखे जाएंगे।

(घ) परिकल्पित उत्पादों की जांच करने के लिए नियंत्रणों के न्यूनतम स्तर अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे

(vi) परिरक्षण नियंत्रण

उत्पाद के भंडारकरण और अभिग्रहन दोनों के दौरान अच्छी तरह से परिरक्षित किया जाएगा।

(v) पैकिंग नियंत्रण

पैकिंग विनिर्देशों उत्पादों की पैकिंग के लिए अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट नियंत्रणों को पूरा करने की दृष्टि से अधिकथित किए जाएंगे।

अनुसूची

उत्पादों के लिए नियंत्रण स्तर

[परिशिष्ट—क का उप पैरा (iii) देखिए]

क्रम संख्या	लक्षण	अपेक्षाएं	नमूनों की सं०	आवृत्ति	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	दृश्य और विमाएं	मानक विनिर्देश के अनुसार	100 %	—	—
2.	उत्तापमिति शंकु समान (पी०सी०ई०)	मानक विनिर्देश के अनुसार	एक नमूना	प्रत्येक बैच से	—
3.	भार के अधीन उच्च तापतासह (आर०यू० एल०)	मानक विनिर्देश के अनुसार	एक नमूना	प्रत्येक बैच से	—
4.	समखण्डन प्रतिरोध	मानक विनिर्देश के अनुसार	ईंटों को पकड़ने के लिए एक पैनल फ्रेम वर्क	12-14 महीने में एक बार	—
5.	शीत बलन सामर्थ	मानक विनिर्देश के अनुसार	12 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए प्रतिदिन 12 नमूने	—
6.	मापांक भंजन	मानक विनिर्देश के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए महीने में एक बार	—
7.	पुनःतापन के बाद स्थायी परिवर्तन	मानक विनिर्देश के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए पंद्रह दिन में एक बार	—
8.	दृश्यमान स्थमयता	मानक विनिर्देश के अनुसार	12 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए प्रतिदिन 12 नमूने	—
9.	वास्तविक विनिर्दिष्ट गुरुत्व तथा वास्तविक घनत्व	मानक विनिर्देश के अनुसार	3 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए प्रतिदिन 12 नमूने	—
10.	आप्रतअर्ल्वस्तु तथा शोषक	मानक विनिर्देशों के अनुसार	5 नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए प्रतिदिन 5 नमूने	—
11.	रासायनिक विश्लेषण	मानक विनिर्देशों के अनुसार	संयुक्त नमूने	प्रत्येक क्वालिटी के लिए सप्ताह में एक बार	—

1.0 उपरोक्त निरीक्षण के अतिरिक्त अंतिम निरीक्षण, नीचे दी गई सारणी-1 में विनिर्दिष्ट रूप में नमूना मापमान अपना कर, निम्नानुसार लाट को परिभाषित करके उच्चतापसह ईंटों की पैकिंग के समय किया जाएगा।

"किसी भी परेषण में, (यथास्थिति) उसी प्रकार के उच्चतापसह ईंटों की सभी या 22,000 संख्याओं को एक लाट गठित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाएगा"

सारणी-I

लाट का आकार	नमूना आकार	निम्नलिखित के लिए त्रुटि-पूर्ण अनुज्ञेय संख्या	
		साधारण अपेक्षाएं	आकार की सहायता
1	2	3	4
500 तक	30	5	1
501 से 800	40	6	1
801 से 1300	55	8	2
1301 से 3200	75	10	2
3201 से 8000	115	14	3
8001 से 22000	150	18	4

टिप्पण :—अन्य 22000 से अनधिक उपयुक्त 22000 संख्याओं से पृथक लाट बनेगा।

1.1 उपरोक्त सारणी-I में दिए गए नमूना आकार केवल त्रुटिपूर्ण परीक्षणों से संबंधित है अर्थात् त्रुटिपूर्ण अनुज्ञेय संख्या निकालने के लिए न कि भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए।

1.2 भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए नमूनों की संख्या के ब्यौरे सारणी-II में दिए गए हैं और ये नमूने सारणी-I के अनुसार लॉट में से पहले एकत्रित किए गए नमूनों में से निकाले जाएंगे।

सारणी-II

क्र०सं०	लक्षण	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	अपेक्षित उच्चतापसह ईंटें	टिप्पणियां
1.	उत्तापमिति शंकु समान	2	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईंटों के भाग में से 1 कि०ग्रा० सामग्री	जहां-जहां लागू हों
2.	भार के अधीन उच्चतापसह	1	1	जहां-जहां लागू हो
3.	समत्खंडन प्रतिरोध	12 या 14 ईंटों का एक पैनल	14	जहां-जहां लागू हो
4.	क्रीप वलन सामर्थ्य	5	5	जहां-जहां लागू हो
5.	मापांक भंजन	5	5	जहां-जहां लागू हो
6.	पुनःतापन के बाद स्थायी परिवर्तन	5	5	जहां-जहां लागू हो
7.	दृश्यमान रंध्रमयता	5	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गई ईंटों के 5 या भाग	जहां-जहां लागू हो
8.	वास्तविक विनिर्दिष्ट गुरुत्व तथा वास्तविक —घनत्व	3	अन्य परीक्षणों से छोड़ी ईंटों के 3 या भाग	जहां-जहां लागू हो
9.	प्रपुंज घनत्व	5	5	जहां-जहां लागू हो
10.	रासायनिक विश्लेषण	—	अन्य परीक्षण से छोड़ी गई ईंटों के भागों में से संयुक्त नमूना	जहां-जहां लागू हो

(2) पैकिंग के लिए नियंत्रण स्तर
[उपबंध-II का उप-पैरा (iii) (V) देखिए)]

1. पैकिंग

1.1 पैकेज पर्याप्त सामर्थ्य के होंगे जिससे कि अभिवहन के दौरान उठाई-धराई को सहन कर सकें और उच्चतापसह ईंटों को इस प्रकार पैक किया जाएगा जिससे कि टूट फूट/नुकसान आदि से बचा जाए।

2. चिह्नन :—

2.1 उच्चतापसह ईंटों से युक्त पैकेजों को निम्नलिखित से चिह्नित किया जाएगा :—

(क) सामग्री का नाम और परिमाण

(ख) विनिर्माता का नाम और व्यापार चिह्न, यदि को हो।

परिशिष्ट-ख

परेषणवार निरीक्षण

1. उच्चतापसह ईंटों का परेषण निरीक्षण और परीक्षण के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए होगा कि वह अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है।

2. नमूना मापमान से संबंधित संविदात्मक विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में, निम्नलिखित रूप में एक लॉट को परिभाषित करके नीचे दी गई सारणी-I और II में अधिकथित लागू होंगे: "किसी भी परेषण में यथास्थिति उसी प्रकार के उच्चतापसह ईंटों की सभी या 22,000 संख्याओं को एक लॉट गठित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाएगा"।

सारणी-I

लॉट आकार	नमूना आकार	निम्नलिखित के लिए त्रुटि-पूर्ण अनुज्ञेय संख्या	
		साधारण अपेक्षाएं	आकार की सहायता
500 तक	30	5	1
501 से 800	40	6	1
801 से 1300	55	8	2
1301 से 3200	75	10	2
3201 से 8000	115	14	3
8001 से 22000	150	18	4

टिप्पण : अन्य 22000 से अनधिक उपर्युक्त 22000 संख्याओं से एक पृथक् लॉट बनेगा।

1.1 उपरोक्त सारणी-I में दिए गए नमूना आकार केवल त्रुटिपूर्ण परीक्षणों से संबंधित है अर्थात् त्रुटि पूर्ण अनुज्ञेय संख्या निकालने के लिए है न कि भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए।

1.2 भौतिक और रासायनिक परीक्षणों के लिए नमूनों की संख्या के ब्यौरे सारणी-II में दिए गए हैं और ये नमूने तथा सारणी-I के अनुसार लॉट में से पहले एकत्रित किए गए नमूनों में से निकाले जाएंगे।

सारणी-II

क्र०सं०	लक्षण	परीक्षण किए जाने वाले नमूनों की संख्या	अपेक्षित उच्चतापसह ईंटें	टिप्पणियां
1.	उत्तापमिति शंकु समान	2	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गयी ईंटों के भागों में से एक कि०ग्रा० सामग्री	जहां-जहां लागू हों
2.	भार के अधीन उच्चतापसह	1	1	जहां-जहां लागू हो
3.	समुत्खंडन प्रतिरोध	12 या 14 ईंटों का एक पैनल	14	जहां-जहां लागू हों
4.	शीत दलन सामर्थ्य	5	5	जहां-जहां लागू हों
5.	मापांक भंजन	5	5	जहां-जहां लागू हों
6.	पुनःतापन के बाद स्थायी परिवर्तन	5	5	जहां-जहां लागू हों
7.	दृश्यमान रंध्रमयता	5	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गयी ईंटों के या 5 भाग	जहां-जहां लागू हों
8.	वास्तविक विनिर्दिष्ट गुरुत्व और वास्तविक घनत्व	3 या भाग	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गयी ईंटों को 5 या भाग	जहां-जहां लागू हों
9.	थपुंज घनत्व	5	5	जहां-जहां लागू हों
10.	रासायनिक विश्लेषण	—	अन्य परीक्षणों से छोड़ी गयी ईंटों के भागों में से एक संयुक्त नमूना	जहां-जहां लागू हों

3. अनुरूपता के लिए मापदंड से संबंधित संविदात्मक विनिर्देशों में विनिर्दिष्ट अनुबंध के अभाव में वही होगा जो सुसंगत भारतीय मानक विनिर्दिष्ट में अधिकथित है।

[फाइल सं० 6/16/83-ई आई एंड ई पी०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

ORDER

S.O. 1145.—Whereas in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government is of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of the Export Trade of India that Refractory Bricks should be subject to quality control and inspection prior to export ;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 ;

Now, therefore, in pursuance of the said sub-rule and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. 2516 dated the 22nd August, 1966, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the persons likely to be affected thereby.

2. Notice is hereby given that any person who desires to make any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within forty-five days of the date of publication of this Order in the Official Gazette to the Export Inspection Council, Pragati Tower, (11th floor), 26, Rajendra Place, New Delhi-110008.

Proposals.

(1) To notify that Refractory Bricks mentioned in Annexure-I appended to this Order shall be subject to quality control and inspection prior to export ;

(2) To recognise—

(a) National and International Standards and Standards of other bodies recognised by Export Inspection Council.

(b) The specifications as declared by the exporter to be the agreed specifications in the export contract for the Refractory Bricks as the standard specifications for the said refractory bricks provided the same are not below (a) above.

Notes : (i) When the export contract, does not indicate detailed technical requirements or is based only on samples, the exporter shall furnish a written specification ;

(ii) Methods of tests will be as per National Standards ;

(3) To specify the type of quality control and inspection in accordance with the draft Export of Refractory Bricks (Quality Control and Inspection) Rules, 1983, set out in Annexure-II appended to this Order as the type of quality control and inspection which would be applied to such refractory bricks prior to export ;

(4) To prohibit the export, in the course of international trade of such refractory bricks unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the agencies established by the Central Government under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the Refractory Bricks satisfy the conditions relating to quality control and inspection, and are export-worthy.

3. Nothing in this order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of Refractory Bricks not exceeding Rs. 1000 in F.O.B. value to the prospective buyers.

4. In this Order 'Refractory Bricks' shall mean any of the refractory bricks of any shape mentioned in Annexure-I to this order.

ANNEXURE-I

In this order 'Refractory Bricks' means any of the following :—

1. Fireclay Refractory Bricks
2. Basic Refractory Bricks
3. Silica Refractory Bricks
4. Acid Resisting Refractory Bricks
5. Sillimanite Bricks
6. High Alumina Bricks
7. Insulating Bricks.

ANNEXURE-II

Draft rules proposed to be made under section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

1. Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Refractory Bricks (Quality Control and Inspection) Rules, 1983.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) ;

(b) "Agency" means any one of the agencies established under section 7 of the Act ;

(c) "Council" means Export Inspection Council established under section 3 of the Act ;

(d) Refractory Bricks means any of the following :—

1. Fireclay Refractory Bricks ;

2. Basic Refractory Bricks ;

3. Silica Refractory Bricks ;

4. Acid Resisting Refractory Bricks ;

5. Sillimanite Refractory Bricks ;

6. High Alumina Bricks ;

7. Insulating Bricks.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Refractory Bricks for export shall be carried out with a view to ensuring that the Refractory Bricks conform to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act, that is to say (a) the National and International Standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council or (b) the specifictions declared by the exporter to be the agreed specifications in the export contract provided the same are not below (a).

(i) By ensuring that the products have been manufactured by exercising necessary inprocess quality control as specified in Appendix-A to this notification, in respect of units coming under inprocess quality control system of inspection.

(ii) On the basis of inspection and testing carried out in the manner specified in Appendix-B to these rules in respect of units coming under consignment wise system of inspection.

4. Procedure of Inspection.—(1) An exporter intending to export a consignment of Refractory Bricks shall give an intimation in writing to the agency furnishing therein details of the contractual specification alongwith a copy of the Export Contract or Order to enable the agency to carry out inspection in accordance with the provisions of rule 3.

(2) For export of Refractory Bricks manufactured by exercising adequate inprocess quality control as laid down in Appendix-A and the manufacturing unit adjudged as having adequate inprocess quality control drills by a panel of Experts constituted by the Council for this purpose, the Exporter shall also furnish alongwith the intimation mentioned in sub-rule (1) declaration that the consignment of Refractory Bricks intended for export has been manufactured by exercising adequate quality control as laid down in Appendix-A and that the consignment conforms to the standards specifications recognised for the purpose.

(3) The exporter shall furnish to the agency the identification marks applied to the consignment to be exported.

(4) Every intimation under sub-rule (1) above shall be given not less than seven days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises, while in the case of intimation alongwith declaration under sub-rule (2) shall be given not less than three days prior to the despatch of the consignment from the manufacturers' premises.

(5) On receipt of the intimation under sub-rule (1) and the decalaration, if any, under sub-rule (2) the agency—

(a) (i) on satisfying itself that during the process of manufacture, the manufacturer had exercised adequate quality controls as laid down in Appendix-A and followed the instructions, if any, issued by the Council or Agency in this regard to manufacture the product to conform to the standard specifications recognised for the purpose shall with three days issue a certificate declaring the consignment of Refractory Bricks as exportworthy.

(ii) In case where the manufacturer is not the exporter, however, the consignment shall be physically verified and such verification and or inspection if necessary shall be carried out by the Agency to ensure that the above conditions are complied with.

(iii) The Agency shall however carry out the spot-check of some of the consignments meant for export and also visit the manufacturing unit at regular intervals to verify the maintenance of the adequacy of inprocess quality control drills adopted by the unit.

(iv) If the manufacturing unit is found not adopting the required quality control measures at any stage of manufacture or does not comply with the recommendations of the Council or Agency, the unit shall be decalared as not having adequate inprocess quality control drills and in such cases, the unit if so desires shall apply afresh for adjudgement of the maintenance of adequacy of inprocess quality control drills.

(b) In case where the exporter had not declared under sub-rule (2) that adequate quality control as laid down in Appendix-A had been exercised, on satisfying itself that the consignment of Refractory Bricks conforms to the standard specifications recognised for the purpose, on the basis of inspection and testing carried out as laid down in Appendix-B, shall within seven days of carrying out such inspection issued a certificate declaring the consignment of Refractory Bricks as exportworthy ;

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days refuse to issue a certificate to the exporter declaring the consignment of Refractory Bricks as exportworthy and shall communicate such refusal to the exporter alongwith the reasons.

(c) (i) In case where the manufacturer is not the exporter under sub-rule 5(a) or consignment is inspected under sub-rule (5) (b), the Agency shall, immediately after completion of the inspection, seal the packages in the consignment in the manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(ii) In case of rejection of the consignment, if the exporter so desires the consignment may not be sealed by the Agency but in such casess, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

5. Place of Inspection.—Every inspection under these rules shall be carried out either (a) at the premises of the manufacturer of such product, or (b) at the premises at which the goods are offered by the exporter for inspection provided adequate facilities for the purpose exist therein.

6. Inspection Fee.—Subject to a minimum of Rs. 75 for each consignment, a fee at the rate of 75 paise for every Rs. 100 of FOB value of such consignment shall be paid as inspection fee under these rules.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under sub-rule (5) of rule 4 may, within ten days of the receipt of communication of such refusal by him, prefer an appeal to a panel of experts consisting of not less than three but not more than seven persons as may be constituted by the Central Government.

(2) The panel of experts shall consist of at least two-thirds of non-officials of the total membership.

(3) The quorum for the panel of experts shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

APPENDIX A

Quality Control

The quality control of Refractory Bricks shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, preservation and packing of the products as laid down below, together with the levels of controls as set out in the Schedule appended hereto.

(i) Purchase and raw materials control :—

(a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of raw materials to be used.

(b) Either the accepted consignment shall be accompaned by a suppliers' test and inspection certificate corroborating the requirements of the purchase specifications, in which case occasional checks shall be conducted at least once in 10 consignments by the purchaser for a particular supplier to verify the correctness of the aforesaid test or inspection certificate or the purchased material shall be regularly tested and inspected either in the laboratory within the factory or in an outside laboratory or test house.

(c) The sampling for inspection or test to be carried out shall be based on the recorded investigations.

(d) After the inspection or test is carried out, systematic method shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials and for disposal of the rejected materials.

(e) Adequate records in respect of the aforesaid controls shall be regularly and systematically maintained by the manufacturer.

(ii) Process Control :—

(a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturer for different stages of manufacturer.

(b) Equipment and instrumentation facilities shall be adequate to control the process as laid down in the process specifications.

(c) Adequate records shall be maintained by the manufacturer to ensure the possibility of verifying the controls exercised during the process of manufacture.

Note.—For routine control over the manufacturing process, reference to IS : 1528 (Part VII)—1974 is recommended.

(iii) Product Control :—

(a) The manufacturer shall have either his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to check up whether the product conform to specifications recognised under section 6 of the Act.

(b) Sampling for test and inspection to be carried out shall be based on the recorded investigation.

(c) Adequate records in respect of sampling and test carried out shall be regularly and systematically maintained.

(d) The minimum levels of controls to check the finished products shall be as specified in the Schedule.

(iv) Preservation Control :—

The product shall be well preserved both during the storage and transit.

(v) Packing Control :—

Packing specifications shall be laid down with a view to satisfying the controls as mentioned in the Schedule for packing of the products.

SCHEDULE

LEVEL OF CONTROL FOR PRODUCTS

(See sub-paragraph (iii) of Appendix-A)

Sl. No.	Characteristics	Requirements	No. of Samples	Frequency	Remarks
1.	Visual and Dimensions	As per standard specification	100%	—	—
2.	Pyrometric Cone equivalent (PCE)	-do-	One Sample	From each Batch	—
3.	Refractoriness under load (RUL)	-do-	-do-	-do-	—
4.	Spalling Resistance	-do-	A panel frame work for holding 12-14 bricks	Once a month	
5.	Cold crushing strength	-do-	12 Samples	12 Samples per day for each quality	—
6.	Modulus of rupture	-do-	5 Samples	Once a month for each quality	—
7.	Permanent changeafter reheating	-do-	5 Samples	Once every fortnight for each quality	—
8.	Apparent porosity	-do-	12 Samples	12 Samples per day for each quality	—
9.	True specific gravity and True density	-do-	3 Samples	-do-	True Specific gravity for magnesite bricks and mortar only.
10.	Moisture content and drying	-do-	5 Samples	5 Samples per day for each quality	—
11.	Chemical Analysis	-do-	A composite sample	Once a week for each quality	—

1.0 Apart from the above inspection, final inspection should be carried out at the time of packing of refractory bricks, by adopting the scale of sampling as specified in Table-I given below, by defining a lot as follows :—

"In any consignment, all or 22,000 numbers of refractories of the same type (as the case may be) shall be grouped together to constitute a lot."

TABLE—I

Lot Size	Sample size	Permissible number Defectives for	
		General Requirements	Tolerance on size
1	2	3	4
Upto 500	30	5	1
501 to 800	40	6	1
801 to 1300	55	8	2
1301 to 3200	75	10	2
3201 to 8000	115	14	3
8001 to 22000	150	18	4

Note :—Above 22000 numbers not exceeding another 22000 wil form a separate lot.

1.1 The sample sizes given in above Table-I relate to non-destructive tests only, that is, for finding the permissible number of defectives and not for physical and chemical tests.

1.2 The details of the number of samples for physical and chemical tests are given in Table-II and these samples shall be drawn from the samples already collected from the lot in accordance with Table-I.

TABLE—II

Sl. No.	Characteristics	No. of Samples to be tested	Refractories required	Remarks
1.	Pyrometric Cone equivalent	2	1 Kg. material from portions of the bricks left over from other tests.	Wherever applicable.
2.	Refractoriness under load	1	1	-do-
3.	Spalling resistance	A panel of 12 or 14 bricks	14	-do-
4.	Cold Crushing strenght	5	5	-do-
5.	Modulus of rupture	5	5	-do-
6.	Permanent change after reheating	5	5	-do-
7.	Apparent porosity	5	5 or portions of bricks left over from other tests.	-do-
8.	True specific gravity and true density	3	3 or portions of bricks left over from other tests.	-do-
9.	Bulk density	5	5	-do-
10.	Chemical Analysis	..	A composite sample from portions of bricks left over from other tests.	-do-

(2) LEVELS OF CONTROL FOR PACKING
(See sub-paragraph (iii) (v) of Annexture-II)

1. Packing :

1.1 The packages shall have sufficient strength of withstand handling during transit and the refractory bricks shall be packed so as to avoid breakage/damage etc.

2. Marking :

2.1 Packages containing refractory bricks shall be marked with the following :

(a) Name and quantity of the material

(b) Name of the manufacturer and trade mark, if any.

APPENDIX B

Consignmentwise Inspection

1. The consignment of refractory bricks shall be subjected to inspection and tested to ensure conformity of the same to the standard specifications recognised under section 6 of the Act.

2. In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards scale of sampling the same laid down in Table-I and II given below shall become applicable, by defining a lot as follows :—

"In any consignment, all or 22,000 numbers of refractories of the same type (as the case may be) shall be grouped together to constitute a lot."

TABLE—I

Lot Size	Sample Size	Permissible Number of Defectives for	
		General Requirements	Tolerance on size
1	2	3	4
Upto 500	30	5	1
501 to 800	40	6	1

1	2	3	4
801 to 1300	55	8	2
1301 to 3200	75	10	2
3201 to 8000	115	14	3
8001 to 22000	150	18	4

NOTE.—Above 22000 number not exceeding another 22,000 will form a separate lot.

1.1 The sample sizes given in above Table-I relate to non-destructive tests only, that is, for finding the permissible number of defectives and not for physical and chemical tests.

1.2 The details of the number of samples for physical and chemical tests are given in Table II and these samples shall be drawn from the samples already collected from the lot in accordance with Table-I.

TABLE II

Sl. No.	Characteristic	No. of samples to be tested	Refractories required	Remarks
1.	Pyrometric cone equivalent	2	1 kg material from portions of the bricks left over from other tests.	Wherever applicable
2.	Refractoriness under load.	1	1	,,
3.	Spalling resistance	A panel of 12 or 14 bricks.	14	,,
4.	Cold crushing strength	5	5	,,
5.	Modulus of rupture	5	5	,,
6.	Permanent change after re-heating	5	5	,,
7.	Apparent porosity	5	5 or portions of bricks left over from other tests.	,,
8.	True specific gravity and true density	3	3 or portions of bricks left over from other tests.	,,
9.	Bulk Density	5	5	,,
10.	Chemical analysis	—	A composite sample from portions of bricks left over from other tests.	,,

3. In the absence of specific stipulation in the contractual specifications as regards criteria for confrmity, the same shall be as laid down in relevant Indian Standard Specification.

[F.No. 6/15/83-EI&EP]
C.B. KUKRETI,
Jt. Director.

मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात का कार्यालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1984

का० आ० 1146.—सर्वश्री हिन्दुस्तान फटिलाइजर कार्पोरेशन (नामरूप यूनिट) मधुबन, 55 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19 की पुनः निर्यात आधार पर संलग्न सूची के अनुसार इरेक्शन टूल्स के आयात के लिए 2,00,000/ (मात्र दो लाख रुपए) का सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० आई०/ जे०/3051452 दिनांक 8-6-83 प्रदान किया गया था ।

फर्म ने उपर्युक्त लाइसेंस के सीमा शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि प्रति के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट अस्थानस्थ हो गया है। आगे यह भी बताया है कि सीमा शुल्क निकासी परमिट किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं था जिससे कि सीमा शुल्क निकासी परमिट के मूल्य को बिल्कुल भी उपयोग नहीं लाया गया था।

2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पब्लिक दिल्ली के सम्मुख स्टाम्प कागज पर विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है ।

तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० आई०/ जे०/ 3051452 दिनांक 8-6-83 फर्म से अस्थानस्थ हो गया है। यथा संशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपखंड 9 (सी सी) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री हिन्दुस्तान फटिलाजर कार्पोरेशन, नई दिल्ली-19 को जारी किए गए मूल सीमा शुल्क निकासी परमिट सं० आई०/जे०/ 3051452 दिनांक 8-6-83 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

3. पार्टी को एक अनुलिपि सीमा शुल्क निकासी परमिट अलग से जारी किया जा रहा है।

[सं० सी० जी 2/पी एण्ड सी/19/83-84/1417]
पॉल बेक,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1984

S.O. 1146.—M/s. Hindustan Fertilizer Corporation (Namrup Unit) Madhuban, 55-Nehru Place, New Delhi-19 were granted an C.C.P. No. 1/J/3051452 dated 8-6-83 for Rs. 2,00,000 (Rupees two lakhs only) for import of Erection Tools as per list attached on re-exported basis.

The firm has applied for issue of duplicate copy of CCP of the above mentioned licence on the ground that the original CCP has been misplaced. It has further been stated that the CCP was not registered with any Customs Authority and as such the value of CCP has not been utilized at all.

2. In support of their contention, the licensee has filed an affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original CCP No. I/J/3051452 dated 8-6-83 has been misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import Control Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said original CCP No. I/J/3051452 dated 8-6-83 issued to M/s. Hindustan Fertilizers Corporation New Delhi-19 is hereby cancelled.

3. A duplicate CCP is being issued to the party separately.

[No. CGII/P&C/19/83-84/1417]

PAUL BECK, Dy. Chief Controller of Import and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports.

(सी० जी III अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1984

का० आ० 1147—सर्वश्री डनफोस (इंडिया) लिमिटेड, बी-20-21 इन्डस्ट्रियल एरिया साइट नं० 3, मेरठ रोड़ गाजियाबाद (यू० पी०) को निशुल्क विदेशी मुद्रा विनियम के अंतर्गत पूंजीगत माल के आयात के लिए 16,24,400 रुपए (मात्र सोलह लाख चौबीस हजार और चार सौ रुपए) का आयात लाइसेंस संख्या पी०/सी०जी०/सी०जी०/2085890 दिनांक 14-7-82 प्रदान किया गया था।

फर्म ने अब उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क/मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रतियों की अनुलिपि के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि लाइसेंस संख्या पी०/सी० जी०/2085890 दिनांक 14-7-82 की सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रतियां खो गई/अस्थानस्थ हो गई हैं। आगे यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी भी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं करवाया गया था और उसको बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लाया गया था।

अपने दावे के समर्थन में लाइसेंस धारी ने पब्लिक नोटरी, दिल्ली के सम्मुख विधिवत साक्ष्यांकित स्टाम्प कागज पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस संख्या पी/सी जी/2085890 दिनांक 14-7-82 की मूल मुद्रा विनिमय/सीमा शुल्क प्रति फर्म से खो गई/अस्थानस्थ हो गई है। अतः संशोधित आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 दिनांक 7-12-1955 के उपबंध 9 (सी०सी०) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री डनफोस (इंडिया), लिमिटेड, गाजियाबाद को जारी किए गए लाइसेंस सं० पी०/सी० जी०/2085890 दिनांक 14-7-82 की उक्त मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

पार्टी को उक्त लाइसेंस की अनुलिपि सीमा शुल्क/मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतियां अलग से जारी की जा रही हैं।

[सिमिल सं० सी० जी० III/993/81/15]

एम० एल० भार्गव, उप मुख्य नियंत्रक

(C. G. III Section)

ORDER

New Delhi, the 24th March, 1984

S.O. 1147.—M/s. Danfoss (India) Ltd., B, 20-21, Indutrias Area, Site No. 3, Meerut Road, Ghaziabad (U.P.) were granted an Import Licence No. P/CG/2085890 dated 14-7-82 for Rs. 16,24,400 (Rupees sixteen lakhs twety four thousand and four hundred only) for import of Capital Goods under Free Foreign Exchange.

The firm has now applied for issue of Duplicate Copies of Customs/Exchange Control copies of the above mentioned licence on the ground that the Customs/Exchange Control Copies of the licence No. P/CG/2085890 dated 14-7-82 have been lost/misplaced. It has been stated further that the captioned licence was not registered with any Customs Authority and as such the licence has not been utilized at all.

In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary Public, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange/Customs copy of Import Licence No. P/CG/2085890 dated 14-7-82 has been lost/misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred under sub-clause 9(cc) of the Import (Control) Order, 1955 dated 7-12-1955 as amended the said Exchange Control Purposes Copy and Customs Purposes Copy of the licence No. P/CG/2085890 dated 14-7-82 issued to M/s. Danfoss (India) Ltd., Ghaziabad is hereby cancelled.

A duplicate Customs/Exchange Control Purposes copies of the said licence are being issued to the party separately.

[File No. CG. III/993/81/15]

M. L. BHARGAVA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports.

संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात का कार्यालय

बंगलौर, 11 नवम्बर, 1983

रद्द करने का आदेश

का० आ० 1148 सर्वश्री सवी इन्टरप्राइजेज, 205 आकिपेट मेन रोड, बंगलौर-560053 को 1983-84 की आयात और निर्यात नीति जिल्द I के परिशिष्ट 5 में आने वाली मदों के आयात के लिये 9,48,530 रु० का आयात लाइसेंस संख्या पी/एस/1941482 दिनांक 29-4-1983 प्रदान किया गया था। उन्होंने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल लाइसेंस किसी सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराये और बिल्कुल भी उपयोग में लाये बिना ही खो गया है। अपनी प्रार्थना के समर्थन में आवेदक ने नोटरी बंगलौर शहर के सम्मुख विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ पत्र दाखिल किया है।

मैं संतुष्ट हूं कि 9,48,530 रु० के लाइसेंस सं० पी/एस/1941482 दिनांक 29-4-1983 की दोनों, सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई/अस्थानस्थ हो गई है और आवेदन फर्म को उपर्युक्त आयात लाइसेंस की एक अनुलिपि सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की जाये।

उपर्युक्त लाइसेंस की मूल सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति एतद् द्वारा रद्द की जाती है।

[सं० आई टी सी /एस एस आई/आदो/6 एएम-84/बेंग]

अ० तुकाराम

उप मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports.

Bangalore, the 11th November, 1983

CANCELLATION ORDER

Sub : Cancellation of Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of Import Licence No. P/S/1941482 dated 29-4-1983 for Rs. 9,48,530 issued in favour of M/s. Savi Enterprises, 205-Akkipet Main Road, Bangalore-53.

S.O. 1148.—M/s. Savi Enterprises 205, Akaapet Main Road, Bangalore-560053. have been granted an import licence

No. P.S. 1941482 dated 29-4-1983 for Rs. 9,48,530 for import of items figuring in Appendix-5 of Import and Export Policy Vol. I 1983-84. They have requested for issued of duplicate copy of Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence on the ground that the orignnal licence has been lost without having been registered with any customs authority and not utilised at all. In support of their request, the applicant have filed an Affidavit duly sworn before the Notary, Bangalore City.

I am satisfied that both the Customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the licence No. P.S./1941482 dated 29-4-1983 for Rs. 9,48,530 have been lost misplaced and that a duplicate customs purpose copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence may be issued to the applicant firm.

The original Customs Purposes copy and Exchange Control Purpose copy of the said licence is hereby cancelled.

[No. ITC|SSI|AUTO|6|AM.84|Bang.]

A. THUKKARAM, Dy. Chief Controller of Imports and Exports for Joint Chief Controller of Imports and Exports.

मद्रास, 6 मार्च, 1984

आदेश संख्या 13, दिनांक 2-3-1984

का०आ० 1149.—सर्वश्री टिन इंडस्ट्रीज, 21, मानिक चेट्टी स्ट्रीट, सूलै, मद्रास-7 को रुपये 1,53,914- तक अप्रैल, मार्च, 1983 नीति पुस्तक के परिशिष्ट-7, क्रम संख्या 1 में दर्शाई गयी टिन प्लेट वेस्ट का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०एस/1936603/सी/एक्स एक्स/85/एम/82 दिनांक 21-10-1982 जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिए इसलिए आवेदन किया है कि उपर्युक्त लाइसेंस किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी से पंजीकृत करवाये बिना, और बिल्कुल उपयोग में लाये बिना खो दी गयी है।

अपने दावे के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट है कि लाइसेंस संख्या पी/एस/1936603/सी/एक्स एक्स/85/एम/82 दिनांक 21-10-82 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति खो दी गयी है और आदेश देता है कि आवेदन को उपर्युक्त लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति जारी किया जाय। लाइसेंस की सीमा शुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की मूल प्रति एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

रुपये 1,53,914 की सीमाशुल्क प्रयोजनार्थ प्रति की अनुलिपि प्रति संख्या डी/2464832 दिनांक 2-3-84 अलग जारी की जाती है।

[संख्या आई एण्ड एस/61/एएम 83 एयू-3]

सी०जी० फेरनान्डज़,
उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Madras, the 6th March, 1984

ORDER NO. 13 Dated, 2nd March, 1984

S.O. 1149.—M/s. Chellam Tin Industries, 21, Manicka Chetty Street Choolai, Madras-7, were granted a licence No. P/S/1936603/C/XX/85/M|82 dated 21-10-1983 for Rs. 153914 for the import of Tin Plate Waste Waste figuring in Sl. No. 1 of Appendix 7 of AM-83 Policy Book. They have requested to issue a duplicate copy of Customs Purposes Copy of the above said licence which has been lost by them. Further it has been stated by them that the licence has not been registered with any Customs Authorities and utilised at all.

In support of their contention the applicant has filed an affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Customs Purpose copy of licence No. P/S/1936603/C/XX|85|M/82 dated 21-10-82 has been lost and directs that a duplicate copy of the said Customs Purpose Copy of licence should be issued to them. The original Customs purposes copy of licence is hereby cancelled.

A duplicate Customs Purpose copy of licence No. D/2464832 dated 2-3-84 for Rs. 153914 has been issued separately.

[F. No. I&S/61/AM. 83/AU. III]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller of Imports and Exports

उप मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

निरस्त आदेश

जयपुर, 19 फरवरी, 1983

का०आ० 1150.—सर्वश्री तोषनीवाल इन्स्ट्रूमेन्ट्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कैटचरी रोड, अजमेर को एक आयात लाइसेंस सं०पी०/एस०/1866306/सी/एक्स-एक्स 81 दिनांक 19-11-81 वास्ते 24300/- रु० मात्र, अपेन्डिक्स-5 में लिखित अनुमेय मदों के आयात हेतु अप्रैल-मार्च-82 की आयात नीति के अन्तर्गत पी.एच. मीटर्स तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक इंस्ट्रूमेंट्स के उत्पादन हेतु जारी किया गया था।

आवेदक फर्म ने इस कथन के समर्थन में अब एक शपथ-पत्र आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1981-82 के पैरा 352 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें कहा गया है कि उसके लाइसेंस सं० पी/एस/1866306 दिनांक 19-11-81 वास्ते 24300/- रु० की मूल कस्टम कापी दिल्ली कस्टम पर पंजीकृत होने तथा 20127/- रु० तक आंशिक रूप से उपयोग करने के पश्चात् खो गई है।

मैं संतुष्ट हूं कि उक्त आयात लाइसेंस की मूल कस्टम हेतु कापी खो गई है।

अतः आयात व्यापार नियंत्रण आदेश 1955 दि० 7-12-55 (यथा संशोधित) की धारा 9 (सी सी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उपरोक्त लाइसेंस सं० पी/एस/1866306 दि० 2-11-81 की मूल कस्टम हेतु कापी को निरस्त करने का आदेश देता हूं।

आवेदक की प्रार्थना पर अब आयात-निर्यात की कार्यविधि पुस्तिका 1981-82 के पैरा 351—354 के अनुसार उक्त लाइसेंस सं० पी/एस/1866306 दि० 19-11-81 वास्ते 4173/- रु० मात्र की कस्टम कापी की अनुलिपि (डुप्लीकेट कापी) जारी करने पर विचार किया जाएगा।

[सं० एम० एस० आई०/आटो/87/ए एम/82 से II डी सी सी आई एण्ड ई राजस्थान]

एस० के० दत्ता, उप मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

(Office of the Deputy Chief Controller of Imports and Exports)

CANCELLATION ORDER

Jaipur, the 19th February, 1983

S.O. 1150.—M/s. Toshniwal Instrumnets Mfg. Pvt Ltd Katchery Road, Ajmer, were granted Import licence No. P|S|1866306|C/XX/81 dated 19-11-81 for Rs. 24,300 only for import of permissible items as per appendix 5 of policy book of AM-82 required for the manufacture of P.H. Meters and other electronic insrtuments.

The applicant has filed an affidaivt as required under Para 352 of Hand Book of Import Export Procedure 1981-82, wherein they have stated that original Custom Purposes copy of licence No. P/S/1866306 dated 19-11-81 for Rs. 24,300 only for AM-82 period has been misplaced/lost after having been registered with customs House Delhi and utilised partly for Rs. 20,127 only.

I am satisfied that the original Custom Purpose Copy of the said licence have been lost/misplaced.

In exercise of the powers conferred on me under section 9(cc) of Import Trade Control Order 1955 dated 7th December, 55 as amended upto date, the Custom Purpose Copy of licence No. P/S/1866306 dated 19-11-81 for Rs. 24,300 only is hereby cancelled.

The applicant is now being issued duplicate Custom Purpose Copy of Import licence No. P/S/1366306 dated 19-11-81 for the C.I. value of Rs. 24,300 according with the proportion of para 351 to 354 of Hand Book of Import Export procedure 1981-82 to cover import for the balance un-utilised amount of Rs. 4,173 only.

[F. No. SSI/Auto/87/AM-82/Sec. I|DCC1&E|RAJ|6215]

S. K. DATTA, Dy. Chief Controller of Imports and Exports for Jt Chief Controller of Imports & Exports

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

शुद्धिपत्र

का०आ० 1151.—दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित इस मंत्रालय की दिनांक 21 नवम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या का०आ० 902(अ) को रद्द समझा जाए।

[सं० वी०-16011/1/83-एम.ई.(पी०जी०)]

पी० पी०-चौहान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 23rd March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1151.—This Ministry's Notification No. S.O 942(E), dated the 21st November, 1983, published in the Gazette of India Extraordinary dated the 6th December, 1983, may be treated as cancelled.

[No. V-16011/1/83-ME (PG)]

P. P. CHAUHAN, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1984

का० आ० 1152.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि असम प्रदेश में डिब्रूगढ़ जिलान्तर्गत डिगबोई से तिनसुकिया तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईप लाईन इंडियन आयल कार्पोरेशन (आसाम आयल डिवीजन) द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए लिखित आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, श्री जुगल चन्द्र ओरा, मैनेजर (कर्मचारी सेवाएं), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आसाम आयल डिवीजन) डिगबोई-786171, को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधिव्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

डिब्रूगढ़ जिलान्तर्गत इंडियन आयल कारपोरेशन आसाम आयल डिवीजन डिगबोई के न्यूटैक फार्म से इंडियन आयल कारपोरेशन आसाम आयल डिवीजन के तिन सुकिया टर्मिनल डिपों तक पैट्रोलियम उत्पाद-परिवहन के लिए पाइप लाइन बिछाना।

क्रम	रेवेन्यू ग्राम	मौजा	नं० पट्टा	दाँग नं०	क्षेत्रफल बी०के०यू	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7
1.	डिगबोई टाउन	माकुम	पी०पी० 13	423	0-0-19	
			पी०पी० 12	421	0-0-6	
			पी०पी० 12	422	0-2-4	
			पी पी० 11	414	0-0-15	
			पी०पी० 126	134	0-0-6	
			पी०पी० 121	133	0-0-5	
			पी०पी० 11	413	0-0-9	
			पी०पी० 121	132	0-0-3	
			पी०पी० 121	131	0-0-3	
			पी०पी० 194	412	0-0-13	
			पी०पी० 121	128	0-0-6	
			पी०पी० 597	388	0-1-9	
			पी०पी० 121	127	0-0-9	
			पी०पी० 121	125	0-1-1	
			पी०पी० 121	67	0-0-1	
			पी०पी० 121	65	0-2-10	
			पी०पी० 121	386	0-0-7	

1	2	3	4	5	6	7
1.	बिषबीई टाउन—(जारी)		पी०पी० 121	385	0-0-10	
			पी०पी० 2	26	0-1-7	
			पी०पी० 292	27	0-1-0	
			पी० पी० 2	24	0-1-0	
			पी०पी० 292	25	0-1-6	
			पी०पी० 2	28	0-1-7	
			पीपी० 356	23	0-3-15	
			पी०पी० 291	19	0-4-7	
			कुल क्षेत्रफल		5-1-18	
2.	बरकिल गांव नं० 2	माकुम	पी०पी० 94	362	0-2-19	
			पी०पी० 76	349	1-0-0	
			पी०पी० 68	316	1-1-11	
			पी०पी० 134	315	1-3-9	
			पी०पी० 107	286	1-0-2	
			पी०पी० 86	225	0-0-2	
			पी०पी० 22	224	0-4-5	
			पी०पी० 112	220	0-4-18	
			पी०पी० 22	194	0-1-4	
			पी०पी० 17	195	0-3-2	
			पी०पी० 129	197	1-0-8	
			पी०पी० 18	166	2-0-0	
			पी०पी० 49	127	1-4-12	
			पी०पी० 72	128	1-1-5	
			कुल क्षेत्रफल		14-3-3	
3	बरकिल गांव नं० 3	माकुम	पी०पी० 10	489	0-1-18	
			पी पी० 26	483	1-2-18	
			पी० पी० 12	482	0-0-15	
			पी०पी० 28	488	0-4-5	
			वार्षिक	411	1-3-0	
				412	—	
			पी०पी० 50	410	1-0-18	
			पी०पी० 53	368	0-3-0	
			पी० पी० 42	367	0-0-3	
			वार्षिक	343	0-2-10	
			पी०पी० 50	344	3-0-3	
			वार्षिक	342	0-4-0	
			वार्षिक	303	0-4-2	
			वार्षिक	302	0-1-2	
			पी०पी० 2	301	0-3-10	

1	2	3	4	5	5	7
बरकिल गांव नं० 3—(जारी)			पी०पी० 2	300	0-2-8	
			पी०पी० 45	275	0-2-0	
			पी०पी० 3	280	0-1-5	
			पी०पी० 3	279	0-1-7	
			—	278	0-2-17	
			पी०पी० 3	282	0-0-2	
			वार्षिक	283	0-3-0	
			वार्षिक	285	0-1-4	
			पी०पी० 34	287	1-2-15	
			पी० पी० 34	288	0-0-13	
			वार्षिक	284	0-1-4	
			कुल क्षेत्रफल		14-0-19	
4. आउगढ़ी गांव		टिपलिंग	पी पी 84	445	0-3-3	
			वार्षिक	447	0-0-18	
			वार्षिक	444	0-2-0	
			वार्षिक	448	0-2-6	
			वार्षिक	452	0-1-5	
			वार्षिक	453	1-1-15	
			पी०पी० 44	443	0-3-17	
			पी०पी० 73	441	0-0-10	
			—	455	0-4-5	
			वार्षिक	456	0-3-1	
			—	457	2-0-6	
			पी०पी० 34	488	0-0-3	
			पी०पी० 45	487	2-1-7	
			पी०पी० 11	495	0-4-5	
			पी० पी० 57	494	1-4-11	
			कुल क्षेत्रफल		12-3-12	
5. ओपर मामोरनी गांव		टिपलिंग	पी० पी० 1	83	2-0-6	
			पी०पी० 93	84	0-1-2	
			पी०पी० 93	85	0-2-16	
			—	147	0-2-17	
			पी०पी० 144	145	0-4-10	
			—	146	0-0-8	
			—	144	0-1-7	
			वार्षिक	143	0-2-1	
			पी०पी० 150	94	0-2-14	
			वार्षिक	95	0-2-0	

क्रम सं०	रैवेन्यू ग्राम	मौजा	पट्टा नं०	दाग नं०	क्षेत्रफल वा०क०लू०	कैफियत
5. ओपर मामोरनी गाव—(जारी)			—	96	0-1-5	
			—	97	0-4-19	
			पी० पी० 89	72	0-2-8	
			पी० पी० 116	71	0-2-7	
			पी०पी० 116	70	0-2-8	
			पी० पी० 136	105	1-0-7	
			पी०पी० 136	106	0-0-12	
			वार्षिक	107	0-3-7	
			वार्षिक	108	0-3-0	
			वार्षिक	109	0-1-5	
			पी० पी० 42	110	0-1-15	
			वार्षिक	120	0-1-15	
			वार्षिक	121	0-1-7	
			वार्षिक	117	0-0-17	
			पी० पी० 82	607	0-0-2	
			कुल क्षेत्रफल		12-2-15	
6. ममोरनी भाग-II		टिपलिंग	पी०पी० 158	920	0-1-18	
			पी०पी० 149	919	0-2-16	
			पी०पी० 192	918	1-2-0	
			वार्षिक	927	0-3-5	
			पी०पी० 238	928	1-1-17	
			पी०पी० 237	915	0-1-5	
			पी०पी० 26	914	2-3-7	
			पी०पी० 116	886	0-0-10	
			पी०पी० 225	887	0-4-1	
			वार्षिक	888	0-1-17	
			वार्षिक	889	0-2-0	
			पी०पी० 198	809	0-4-18	
			पी०पी० 160	810	1-0-13	
			पी० पी० 159	812	0-4-18	
			पी०पी० 21	822	3-1-15	
			वार्षिक	823	0-3-0	
			पी०पी० 435	827	1-3-3	
			पी०पी० 187	828	1-0-5	
			वार्षिक	829	0-4-7	
			पी०पी 107	672	1-0-17	
			पी०पी० 11	673	0-0-10	
			पी०पी 37	671	1-4-14	
			कुल क्षेत्रफल		22-3-16	
7. ममोरनी भाग-I		टिपलिंग	वार्षिक	421	1-0-15	
			वार्षिक	423	1-0-14	
			वार्षिक	450	0-4-5	

1	2	3	4	5	6	7
	ममोरनो भाग-I—(जारी)		—	449	0-4-5	
			पी०पी० 22	430	0-2-10	
			पी०पी० 106	446	0-1-8	
			पी०पी० 216	445	0-3-7	
			वार्षिक	434	0-3-11	
			पी०पी० 72	435	0-0-2	
			वार्षिक	433	0-0-16	
			वार्षिक	387	0-0-13	
			वार्षिक	896	0-3-4	
			वार्षिक	395	0-1-8	
			—	391	0-0-2	
			वार्षिक	392	0-3-15	
			वार्षिक	393	0-3-16	
			वार्षिक	475	0-0-2	
			—	387	0-0-10	
			—	477	1-1-0	
			वार्षिक	386	0-0-2	
			वार्षिक	385	0-1-12	
			पी०पी० 231	384	0-0-4	
				कुल क्षेत्रफल	10-3-3	
8.	आंगुड़ी गांव	टिर्पसिंग	—	19	0-1-0	
			—	18	0-1-10	
			—	17	1-0-0	
			—	16	0-2-6	
			—	13	0-0-10	
			वार्षिक	4	0-0-6	
			वार्षिक	2	0-4-3	
				कुल क्षेत्रफल	2-4-15	
9.	जम्मू एस ए नं० 33 1916-17 का (गुटीमाड़ी) इटावोली सीड गार्डेन	टिर्पलिंग	टी०पी० नं० 1	17	1-2-0	
			पी०पी० नं० 1	41	1-2-16	
			टी०पी० नं० 1	21	0-4-4	
			टी०पी० नं० 1	13	0-1-10	
			टी०पी० नं० 1	24	2-0-19	
			पी०पी० नं० 1	25	1-2-11	
			पी०पी० नं० 26	26	1-2-5	
			टी०पी० नं० 1	28	1-0-9	
				कुल क्षेत्रफल	10-1-14	
10.	रोकरवाड़ी	टिर्पसिंग	पी०पी० 2	140	0-0-12	
			पी०पी० 28	142	1-2-16	
			पी०पी० 40	137	0-0-2	
			—	123	0-0-15	
			पी०पी० 1	124	1-4-10	
			पी०पी० 15	125	1-0-3	
			पी०पी० 5	128	0-0-12	

1	2	3	4	5	6	7
			—	98	2-3-5	
			पी०पी० 1	101	0-1-0	
			पी० पी० 21	93	1-0-7	
			—	92	0-4-0	
				कुल क्षेत्रफल	9-3-2	
11.	लंकाशी चायबागान	टिपलिंग	ग्रान्ट नं० 307/329 एन एल आर	14	0-0-12	
12.	ढिंगराई हुबेरा नं० 1	टिपलिंग	पी पी 35	125	0-3-2	
			पी पी 42	122	0-4-10	
			पी पी 16	118	0-3-19	
			—	116	0-3-19	
			—	115	0-0-2	
			—	114	1-2-3	
			—	112	2-1-4	
			—	96	0-3-3	
			पी पी 3	88	0-3-15	
			पी पी 13	87	1-1-18	
			पी पी 5	86	2-3-17	
			पी पी 16	76	0-0-6	
			पी पी 54	75	1-3-13	
			पी पी 41	74	0-0-8	
			पी पी 15	70	0-1-3	
			पी पी 52	71	0-4-16	
			पी पी 53	72	0-1-0	
			पी पी 48	65	1-2-4	
			पी पी 43	63	0-0-4	
			पी पी 32	39	3-2-10	
			पी पी 1	35	1-2-17	
			कुल क्षेत्रफल		22-0-13	
13.	टेंगापानी गांव	टिपलिंग	पी पी 45	11	1-3-0	
			—	10	0-3-9	
			वार्षिक	8	0-3-9	
			पी पी 45	7	0-3-8	
			पी पी 4	2	1-0-2	
			पी पी 69	1	0-0-4	
			कुल क्षेत्रफल		4-3-12	
14.	टेंगापानी चायबागान	टिपलिंग	316 एन एल आर नं० 1	21	5-2-6	
			—	21	0-3-19	
			—	20	1-1-15	
			—	18	1-3-15	
			—	10	0-1-10	
			—	23	0-0-5	
			—	28	1-1-13	
			—	30	3-0-3	
			—	29	2-3-6	
			—	32	0-0-3	
			—	31	0-2-13	

1	2	3	4	5	6	7
14.	टेंगापानी चायबागान—जारी	टियलिंग	—	38	0-0-5	
			—	15	1-1-13	
			—	3	1-0-8	
			—	11	2-0-16	
			—	34	3-1-16	
			कुल क्षेत्रफल		25-1-6	
15.	हुबदा गांव नं० 2	टिपलिंग	—	76	—	
			—	491	0-3-13	
			वार्षिक	75	0-3-7	
			—	477	0-0-2	
			—	448	1-1-13	
			वार्षिक	80	0-2-6	
			वार्षिक	148	1-1-12	
			—	456	0-1-10	
			वार्षिक	81	0-2-2	
			वार्षिक	82	0-2-2	
			वार्षिक	110	0-0-4	
			वार्षिक	109	0-4-3	
			—	134	0-0-10	
			वार्षिक	108	0-4-7	
			पीपी 13	107	0-0-5	
			वार्षिक	86	0-1-8	
			पीपी 6	88	0-1-8	
			वार्षिक	87	1-1-1	
			पीपी 62	61	1-0-4	
			वार्षिक	85	0-0-4	
			पीपी 99	50	0-1-11	
			पीपी 61	51	0-3-0	
			पीपी 38	25	0-4-4	
			पीपी 60	26	0-1-9	
			वार्षिक	24	0-3-7	
			पीपी 19	13	0-4-11	
			पीपी 60	10	0-0-3	
			—	5	1-2-10	
			—	6	—	
			वार्षिक	4	0-4-18	
			कुल क्षेत्रफल		16-2-14	
16.	हुबेरा गांव नं० 1	टिपलिंग	पीपी 28	1	0-1-5	
17.	हुबेरा गांव नं० 3	टिपलिंग	वार्षिक	23	1-0-15	
			—	19	0-2-6	
			कुल क्षेत्रफल		1-3-1	
18.	लोहारी बंगाली गांव	तिनसुकिया	वार्षिक	391	0-1-9	
			वार्षिक	370	0-4-8	
			पीपी 1	366	0-2-3	
			वार्षिक	368	0-2-18	
			पीपी 114	367	0-3-4	
			पीपी 76	365	0-1-13	
			पीपी 71	363	1-2-6	
			पीपी 76	341	1-0-11	
			पीपी 72	333	1-0-13	

क्रम सं०	रैवेन्यू ग्राम	मौजा	पट्टा नं०	दाग नं०	क्षेत्रफल	कैफियत
18.	लोहरी बंगाली गांव—जारी	तिनसुकिया	पी पी 63	289	0-4-8	
			वार्षिक	335	0-1-18	
			वार्षिक	336	0-3-11	
			वार्षिक	337	0-3-3	
			वार्षिक	114	0-0-18	
			पी पी 118	112	1-1-9	
			पी पी 60	111	1-0-8	
			—	121	—	
			पी पी 92	109	1-2-10	
			पी पी 33	107	1-1-0	
			पी पी 33	122	0-4-0	
			—	126	0-0-13	
			—	129	0-0-5	
			पी पी 4	106	0-3-13	
			पी पी 37	105	1-4-0	
			पी पी 4	130	0-0-11	
			पी पी 97	96	1-0-0	
			वार्षिक	135	1-0-13	
			वार्षिक	133	0-2-12	
			कुल क्षेत्रफल		21-0-12	
19.	लोहारी नेपाली गांव	तिनसुकिया	वार्षिक	156	1-2-3	
			पी पी 52	157	1-0-13	
			वार्षिक	158	0-0-18	
			वार्षिक	159	0-4-9	
			पी पी 34	150	0-3-8	
			पी पी 2	164	0-1-0	
			पी पी 29	165	0-1-0	
			वार्षिक	163	0-2-0	
			वार्षिक	167	0-0-10	
			वार्षिक	168	0-3-7	
			वार्षिक	170	1-0-6	
			वार्षिक	171	0-3-2	
			—	211	0-0-2	
			पी पी 3	218	9-1-19	
			पीपी 15	197	1-2-2	
			पी पी 8	190	2-1-6	
				कुल क्षेत्रफल	20-3-5	
20.	पाखरीजान गांव	तिनसुकिया	पी पी 7	111	1-3-11	
			वार्षिक	178	0-1-4	
			वार्षिक	179	0-0-2	
			पी पी 25	176	0-0-2	
			पी पी 26	175	1-2-16	
			पी पी 57	173	1-2-18	
			पी पी 56	174	0-4-3	
			पी पी 41	172	0-0-6	
			पी पी 40	186	0-2-12	
			पी पी 40	187	0-2-18	
			पी पी 71	189	2-0-13	
			पी पी 55	191	1-3-7	
			पी पी 24	192	1-1-17	

क्रम सं०	रैवेन्यू ग्राम	मौजा	पट्टा नं०	दाग नं०	क्षेत्रफल	कैफियत
20.	पाथरीजान गांव	तिनसुकिया	पी पी 20	243	1-2-15	
			पी पी 20	244	0-1-1	
			पी पी 8	242	0-3-8	
			पी पी 8	241	0-0-6	
			पी पी 6	240	1-0-2	
			पी पी 35	227	1-1-5	
			पी पी 35	276	0-2-15	
			पी पी 35	274	0-4-7	
			पी पी 35	273	0-3-10	
			पी पी 35	272	0-3-12	
			पी पी 35	271	0-4-0	
			पी पी 76	224	0-0-6	
			वार्षिक	217	1-2-6	
			—	223	—	
			—	219	—	
			पी पी 27	218	0-2-12	
			पी पी 27	213	0-0-5	
			वार्षिक	215	0-3-5	
			वार्षिक	216	0-0-8	
			कुल क्षेत्रफल		23-2-12	
21.	भपरिया पथार नं० 2	तिनसुकिया	पी पी 2	12	1-2-0	
			—	11	3-2-9	
			कुल क्षेत्रफल		4-4-9	
22.	परिवा पथार नं० 1	तिनसुकिया	पी पी 1	66	0-2-7	
			पी पी 1	65	1-2-13	
			पी पी 1	86	0-1-10	
			पी पी 1	87	1-3-2	
			पी पी 1	88	0-1-0	
			पी पी 1	63	0-1-3	
			पी पी 1	62	2-3-0	
			पी पी 1	64	1-0-5	
			पी पी 1	60	0-0-5	
			—	89	—	
			—	91	—	
			—	101	—	
			—	102	—	
			—	108	—	
			पी पी 17	109	0-0-10	
			पी पी 17	117	0-0-10	
			पी पी 1	118	0-2-15	
			पी पी 3	119	0-1-0	
			पी पी 1	59	2-2-5	
			पी पी 1	58	0-0-4	
			पी पी 1	47	3-0-2	
			पी पी 6	46	0-4-0	
			पी पी 3	45	1-0-0	
			पी पी 20	28	1-0-0	
			पी पी 1	7	0-4-2	
			पी पी 2	48	1-1-15	

क्रम सं०	रैवेन्यू ग्राम	मौजा	पट्टा नं०	दाग नं०	क्षेत्रफल बी०क०लू०	कैफियत
22.	परिया पथार नं० 1—जारी	तिनसुकिया	पी पी 41	6	0–0–15	
			पी पी 16	3	4–1–17	
			कुल क्षेत्रफल		24–0–0	
23.	तिनसुकिया टाउन	तिनसुकिया	पी पी 226	406	0–1–9	
			पी पी 97	407	0–0–3	
			—	417	—	
			पी पी 1078	3502	0–0–5	
			कुल क्षेत्रफल		0–1–17	

[सं० O-12016/5/84-प्रौद]

पी०के० राजगोपालन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 26th March, 1984

S.O. 1152.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that a Petroleum Product Pipeline from the New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) situated in Digboi Town to the Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) in Tinsukia Town, within the Dibrugarh District be laid by Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division).

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the Right of User in the land described in the schedule annexed hereto.

Now, in exercise of the powers conferred by Sub-Section 1 of Section 3 of the Petroleum and Mineral Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act 1962 (Act 50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein.

Provided that any person interested in the said land may within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the said pipeline on the land, mentioned in the Schedule hereto, to the Competent Authority, namely Shri Jugal Chandra Borah, Manager (Employee Services), IOC Ltd. (AOD), Digboi, 786171 in writing.

And every person making such objection shall also state specifically whether he/she wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE

Laying of petroleum product pipeline from New Tank Farm of Indian Oil Corporation Limited (Assam Oil Division) at DIGBOI to Tinsukia Terminal Depot of Indian Oil Corporation Limied (Assam Oil Division) at TINSUKIA within Dibrugarh District.

Sl. No.	Revenue Village	Mouza	Patta No.	Dag No.	Area B	K	L	Remark
1	2	3	4	5	6			7
1.	Digboi Town	Makum	PP 13	423	0	0	19	
			PP 12	421	0	0	6	
			PP 12	422	0	2	4	
			PP 11	414	0	0	15	
			PP 121	134	0	0	6	
			PP 121	133	0	0	5	
			PP 11	413	0	0	9	
			PP 121	132	0	0	3	
			PP 121	131	0	0	3	
			PP 194	412	0	0	13	
			PP 121	128	0	0	6	
			PP 597	388	0	1	9	
			PP 121	127	0	0	9	
			PP 121	125	0	1	1	
			PP 121	67	0	0	1	
			PP 121	65	0	2	10	
			PP 121	386	0	0	7	
			PP 121	385	0	0	10	
			PP 2	26	0	1	7	
			PP 292	27	0	1	0	
			PP 2	24	0	1	0	
			PP 292	25	0	1	6	
			PP 2	28	0	1	7	
			PP 356	23	0	3	15	
			PP 291	19	0	4	7	
		Total Area			5	1	18	
2.	No. 2 Borbil Gaon	Makum	PP 94	362	0	2	19	
			PP 76	349	1	0	0	
			PP 68	316	1	1	11	
			PP 134	315	1	3	9	
			PP 107	286	1	0	2	
			PP 86	225	0	0	2	
			PP 22	224	0	4	5	
			PP 112	220	0	4	18	
			PP 22	194	0	1	4	
			PP 17	195	0	3	2	
			PP 129	197	1	0	8	
			PP 18	166	2	0	6	
			PP 49	127	1	4	12	
			PP 72	128	1	1	5	
		Total Area			14	3	3	
3.	No. 3 Borbil Gaon	Makum	PP 10	489	0	1	18	
			PP 26	483	1	2	18	
			PP 12	482	0	0	15	
			PP 28	488	0	4	5	
			Annual	411	1	3	0	
				412		..		
			PP 50	410	1	0	18	

1	2	3	4	5	6			7
3.	No. 3 Borbil Gaon —Contd.	Makum	PP 53	368	0	3	0	
			PP 42	367	0	0	3	
			Annual	343	0	2	10	
			PP50	344	0	0	3	
			Annual	342	0	4	0	
			Annual	303	0	4	2	
			Annual	302	0	1	2	
			PP 2	301	0	3	10	
			PP 2	300	0	2	8	
			PP 45	275	0	2	0	
			PP 3	280	0	1	5	
			PP 3	279	0	1	7	
			..	278	0	2	17	
			PP 3	282	0	0	2	
			Annual	283	0	3	0	
			Annual	285	0	1	4	
			PP 34	287	1	2	15	
			PP 34	288	0	0	13	
			Annual	284	0	1	4	
			Total Area =		14	0	19	
4.	Ouguri Gaon	Tipling	PP 84	445	0	3	3	
			Annual	447	0	0	18	
			Annual	444	0	2	0	
			Annual	448	0	2	6	
			Annual	452	0	1	5	
			Annual	453	1	1	15	
			PP 44	443	0	3	17	
			PP 73	441	0	0	10	
			..	455	0	4	5	
			Annual	456	0	3	1	
			..	457	2	0	6	
			PP 34	488	0	0	3	
			PP 45	487	2	1	7	
			PP 11	495	0	4	5	
			PP 57	494	1	4	11	
			Total Area =		12	3	12	
5.	Opar Mamoroni Gaon	Tipling	PP 1	83	2	0	6	
			PP 93	84	0	1	2	
			PP 93	85	0	2	16	
			..	147	0	2	17	
			PP 144	145	0	4	10	
			—	146	0	0	8	
			—	144	0	1	7	
			Annual	143	0	2	1	
			PP 150	94	0	2	14	
			Annual	95	0	2	0	
			—	96	0	1	5	
			—	97	0	4	19	
			PP 89	72	0	2	8	
			PP 116	71	0	2	7	
			PP 116	70	0	2	8	
			PP 136	105	1	0	7	
			PP 136	106	0	0	12	
			Annual	107	0	3	7	
			Annual	108	0	3	0	
			Annual	109	0	1	5	
			PP 42	110	0	1	15	
			Annual	120	0	1	15	
			Annual	121	0	1	7	

1	2	3	4	5	6			7
5.	Opar Mamoroni Gaon	Tipling	Annual	117	0	0	17	
			PP 82	607	0	0	2	
			Total Area		12	2	15	
6.	Mamoroni Part II	Tipling	PP 158	920	0	1	18	
			PP 149	919	0	2	16	
			PP 192	918	1	2	0	
			Annual	927	0	3	5	
			PP 238	928	1	1	17	
			PP 237	915	0	1	5	
			PP 26	914	2	3	7	
			PP 116	886	0	0	10	
			PP 225	887	0	4	1	
			Annual	888	0	1	17	
			Annual	889	0	2	0	
			PP 198	809	0	4	18	
			PP 160	810	1	0	13	
			PP 159	812	0	4	18	
			PP 21	822	3	1	15	
			Annual	823	0	3	0	
			PP 135	827	1	1	3	
			PP 187	828	1	0	5	
			Annual	829	0	4	7	
			PP 107	672	1	0	17	
			PP 11	673	0	0	10	
			PP 37	671	1	4	14	
			Total Area =		22	3	16	
7.	Mamoroni Part I	Tipling	Annual	421	1	0	15	
			Annual	423	1	0	14	
			Annual	450	0	4	5	
			—	449	0	4	5	
			PP 22	430	0	2	10	
			PP 106	446	0	1	9	
			PP 216	445	0	3	7	
			Annual	434	0	3	11	
			PP 72	435	0	0	2	
			Annual	433	0	0	16	
			Annual	397	0	0	13	
			Annual	396	0	3	4	
			Annual	395	0	1	9	
			—	391	0	0	2	
			Annual	392	0	3	15	
			Annual	393	0	3	16	
			Annual	475	0	0	2	
			—	387	0	0	10	
			—	477	1	1	0	
			Annual	386	0	0	2	
			Annual	385	0	1	12	
			PP 231	384	0	0	4	
			Total Area =		10	3	3	
8.	Ouguri Gaon	Tipling	—	19	0	1	0	
			—	18	0	1	10	
			—	17	1	0	0	
			—	16	0	2	6	
			—	13	0	0	10	
			Annual	4	0	0	6	
			Annual	2	0	4	3	
			Total Area —		2	4	15	

1	2	3	4	5	6	7
9. WLA No. 33 of 1916-17 (Gutibari) Itakhuli Seed Garden	Tipling	TP No. 1	17	1	2	0
		PP No. 1	41	1	2	16
		TP No. 1	21	0	4	4
		TP No. 1	13	0	1	10
		TP No. 1	24	2	0	19
		PP No. 1	25	1	2	11
		PP No. 26	26	1	2	5
		TP No. 1	28	1	0	9
		Total Area =		10	1	14
10. Robarbari	Tipling	PP 2	140	0	0	12
		PP 28	142	1	2	16
		PP 40	137	0	0	2
		—	123	0	0	15
		PP 1	124	1	4	10
		PP 15	125	1	0	3
		PP 5	128	0	0	12
		—	98	2	3	5
		PP 1	101	0	1	0
		PP 21	93	1	0	7
		—	92	0	4	0
		Total Area =		9	3	2
11. Lankashi T.E.	Tipling	Grant No. 307/329 NLR	14	0	0	12
12. Tingrai Haveda No. 1	Tipling	PP 35	125	0	3	2
		PP 42	122	0	4	10
		PP 16	118	0	3	19
		—	116	0	3	19
		—	115	0	0	2
		—	114	1	2	3
		—	112	2	1	4
		—	96	0	3	3
		PP 3	88	0	3	15
		PP 13	87	1	1	18
		PP 5	86	2	3	17
		PP 16	76	0	0	6
		PP 54	75	1	3	13
		PP 41	74	0	0	8
		PP 15	70	0	1	3
		PP 52	71	0	4	16
		PP 53	72	0	1	0
		PP 48	65	1	2	4
		PP 43	63	0	0	4
		PP 32	39	3	2	10
		PP 1	35	1	2	17
		Total Area =		22	0	13
13. Tengapani Gaon	Tipling	PP 45	11	1	3	0
		—	10	0	3	9
		Annual	8	0	3	9
		PP 45	7	0	3	8
		PP 4	2	1	0	2
		PP 69	1	0	0	4
		Total Area =		4	3	12
14. Tengapani T.E.	Tipling	316 NLR No. 1	21	5	2	6
		-do-	21	0	3	19
		-do-	20	1	1	15
		-do-	18	1	3	15
		-do-	10	0	1	10
		-do-	23	0	0	5
		-do-	28	1	1	13
		-do-	30	3	0	3
		-do-	29	2	3	6
		-do-	32	0	0	3
		-do-	31	0	2	13
		-do-	38	0	0	5
		-do-	15	1	1	13
		-do-	3	1	0	8
		-do-	11	2	0	16
		-do-	34	3	1	16
		Total Area =		25	1	6
15. No.2 Haveda Gaon	Tipling	—	76		—	
		—	491	0	3	13
		Annual	75	0	3	7
		—	477	0	0	2
		—	448	1	1	13
		Annual	80	0	2	6
		Annual	148	1	1	12
		—	456	0	1	10
		Annual	81	0	2	2
		Annual	82	0	2	2
		Annual	110	0	0	4
		—	109	0	4	3
		Annual	134	0	0	10
		Annual	108	0	4	7
		PP 13	107	0	0	5
		Annual	86	0	1	8
		PP 6	88	0	1	8
		Annual	87	1	1	1
		PP 62	61	1	0	4
		Annual	85	0	0	4
		PP 99	50	0	1	11
		PP 61	51	0	3	0
		PP 38	25	0	4	4
		PP 60	26	0	1	9
		Annual	24	0	3	7
		PP 19	13	0	4	11
		PP 60	10	0	0	3
		—	5	1	2	10
		—	6		—	
		Annual	4	0	4	18
		Total Area =		16	2	14
16. No. 1 Haveda Gaon	Tipling	PP 28	1	0	1	5
17. No. 3 Haveda Gaon	Tipling	Annual	23	1	0	15
		—	19	0	2	6
				1	3	1

1	2	3	4	5	6	7
18. Lohari Bongali Gaon	Tinsukia	Annual	391	0	1	9
		Annual	370	0	4	8
		PP 1	366	0	2	3
		Annual	368	0	2	18
		PP 114	367	0	3	4
		PP 76	365	0	1	13
		PP 71	363	1	2	6
		PP 76	341	1	0	11
		PP 72	333	1	0	13
		PP 63	289	0	4	8
		Annual	335	0	1	18
		Annual	336	0	3	11
		Annual	337	0	3	3
		Annual	114	0	0	18
		PP 118	112	1	1	9
		PP 60	111	1	0	8
		—	121		—	
		PP 92	109	1	2	10
		PP 33	107	1	1	0
		PP 33	122	0	4	0
		—	126	0	0	13
		—	129	0	0	5
		PP 4	106	0	3	13
		PP 37	105	1	4	0
		PP 4	130	0	0	11
		PP 97	96	1	0	0
		Annual	135	1	0	13
		Annual	133	0	2	12
		Total Area=		21	0	17
19. Lohari Nepali Gaon	Tinsukia	Annual	156	1	2	3
		PP 52	157	1	0	13
		Annual	158	0	0	18
		Annual	159	0	4	9
		PP 34	160	0	3	8
		PP 2	164	0	1	0
		PP 29	165	0	1	0
		Annual	163	0	2	0
		Annual	167	0	0	10
		Annual	168	0	3	7
		Annual	170	1	0	6
		Annual	171	0	3	2
		—	211	0	0	2
		TP 3	218	9	1	19
		PP 15	197	1	2	2
		PP 8	190	2	1	6
		Total Area=		20	3	5
20. Pakharijan Gaon	Tinsukia	TP 7	111	1	3	11
		Annual	178	0	1	4
		Annual	179	0	0	2
		PP 25	176	0	0	2
		PP 26	175	1	2	16
		PP 55	173	1	2	18
		PP 56	174	0	4	3
		PP 41	172	0	0	6
		PP 40	186	0	2	12
		PP 40	187	0	2	18
		PP 71	189	2	0	13
		PP 55	191	1	3	7
		PP 24	192	1	1	17
		PP 20	243	1	2	15
		PP 20	244	0	1	1
		PP 8	242	0	3	8
		PP 8	241	0	0	6
		PP 6	240	1	0	2
		PP 35	227	1	1	5
		PP 35	276	0	2	15
		PP 35	274	0	4	7
		PP 35	273	0	3	10
		PP 35	272	0	3	12
		PP 35	271	0	4	0
		PP 76	224	0	0	6
		Annual	217	1	2	6
		—	223		—	
		—	219		—	
		PP 27	218	0	2	12
		PP 27	213	0	0	5
		Annual	215	0	3	5
		Annual	216	0	0	8
		Total Area=		23	2	12
21. No. 2 Patia Pathar	Tinsukia	PP 2	12	1	2	0
		—	11	3	2	9
		Total Area=		4	4	9
22. No. 1 Patia Pathar	Tinsukia	PP 1	66	0	2	7
		PP 1	65	1	2	13
		TP 1	86	1	0	10
		TP 1	87	1	3	2
		TP 1	88	0	1	0
		TP 1	63	0	1	3
		TP 1	62	2	2	0
		TP 1	64	1	0	5
		TP 1	60	0	0	5
		—	89		—	
		—	91		—	
		—	101		—	
		—	102		—	
		—	108		—	
		PP 17	109	0	0	10
		PP 17	117	0	0	10
		TP 1	118	0	2	15
		PP -	119	0	1	0
		TP 1	59	2	2	5
		TP 1	58	0	0	4
		TP 1	47	3	0	2
		TP 6	46	0	4	0
		TP 3	45	1	0	0
		PP 20	28	1	0	0
		TP 1	7	0	4	2
		PP 2	48	1	1	15
		PP 41	6	0	0	15
		PP 16	3	4	1	17
		Total Area=		24	0	0
23. Tinsukia Town	Tinsukia	PP 226	406	0	1	9
		PP 97	407	0	0	3
		—	417		—	
		PP 1078	3502	0	0	5
		Total Area=		0	1	17

[No. O-12016/5/85-Prod]

P.K. RAJAGOPALAN, Desk Officer.

(Department of Coal)

New Delhi, the 22nd March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1153.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1362 dated the 17th March, 1982 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 3rd April, 1982,—

At page—1546

in line 41 and 42 :—

for '85'

read '85.00'

in line 48

for 'and meets a'

read 'and meets at'

[No. 19/19/82-CL]

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 22 मार्च 1984

का० आ० 1154—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है;

अतः केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक (क्षेत्र अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

2. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेंट्रल कोल फील्ड्स लि० (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में या जिला मजिस्ट्रेट, धेनकानल (उड़ीसा) कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०, दरभंगा हाउस, रांची को भेजेंगे।

अनुसूची

उत्कल ब्लाक तालचेर कोयला क्षेत्र उड़ीसा

रेखाचित्र राजस्व 24/83 तारीख 12-8-1983

(इससे पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है)

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	थाना	थाना सं०	जिला सं०	क्षेत्र एकड़ों में	टिप्पणियां
1.	कोपाला	छेंदीपाड़ाड	छेंदीपाड़ा	115	धेनकानल	118.10	भाग
2.	कुंडाझारी	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	121	धेनकालन	57.00	भाग
3.	नंदीछोड़	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	122	धेनकानल	650.00	भाग
4.	सिमिलिसाई	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	123	धेनकानल	320.00	भाग
5.	चक्रधारपुर	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	124	धेनकानल	130.00	भाग
6.	कुडापालपासी	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	125	धेनकानल	437.80	सम्पूर्ण
7.	सेंधापाल	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	126	धेनकानल	428.00	भाग
8.	गोलागाडिया	छेंदीपाड़ा	छेंदीपाड़ा	53	धेनकानल	1025.59	सम्पूर्ण
9.	कोंसीधिया	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	63	धेनकानल	574.89	सम्पूर्ण
10.	छोटाबेरेनी	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	64	धेनकानल	458.47	भाग
11.	रामशरन	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	61	धेनकानल	2329.86	सम्पूर्ण
12.	कनकरई	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	65	धेनकानल	564.25	भाग
13.	मारलीब्राह्मणी	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	68	धेनकानल	664.37	संपूर्ण
14.	निसा	छेंदीपाड़ा	सारपाड़ा	69	धेनकानल	335.90	भाग
15.	बाराकेराजंग जंगल	अंगुल	सारपाड़ा	60	धेनकानल	156.00	भाग
16.	जयपुर डी.पी.एफ.				धेनकानल	870.00	भाग
17.	दुर्गापुर आर०एफ०				धेनकानल	3890.00	भाग
18.	मुरादा हरिहरपुर	तालचेर	कोलियरी	55	धेनकालन	307.20	भाग
19.	कुमुंडा	तालचेर	कोलियरी	55	धेनकानल	199.48	भाग

कुल क्षेत्र : 13,216,97 एकड़ (लगभग)

या : 8348,64 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, कोसाला, नन्दीछोड़, कुंडाझारी जंगल और दुर्गापुर आरक्षित वन से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग-घ रेखाएं, दुर्गापुर आरक्षित वन तथा बाराकेराजंग जंगल ग्रामों से होकर जाती हैं तब गांव बाराकेराजंग जंगल की भाग उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, कलियाकता और निसा ग्राम की भाग उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और तब गांव निसा से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचित गोपाल प्रसाद ब्लाक की भाग सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

छ–ब–छ रेखाएं निसा ग्राम (सड़क की पूर्वी सीमा) से होकर जाती है तब माली ब्राह्मणी ग्राम की भाग उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और तब कनकराई छोटा बेरेनी ग्रामों (भाग नदी सीमा के साथ-साथ) से होकर जाती है (जो कोयला धारक क्षेत्र) (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1959 की धारा 4(1) के अधीन अधिसूचित गोपाल प्रसाद ब्लाक की भाग सम्मिलित सीमा है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ–क रेखा, मरादाहरिहरपुर, जयपुर डी.पी.एफ., सेंधापाल, चक्रधरपुर, सिमिलसाही और कोसला ग्रामों से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/56/83–सी०एल०]

S.O. 1154 Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Area (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Central Coal fields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or in the office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in Sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification.

Schedule Utkal Block Talcher Coalfield (Orissa).
Drg. Rev/24/83 Dated 12-8-83
(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Tehsil	P.S.	P.S. No.	District	Area in acres	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kosala	Chhendipada	Chhendipada	115	Dhenkanal	118.10	Part
2.	Kundajhari Jungal.	,,	,,	121	,,	57.00	,,
3.	Nandichhod	,,	,,	122	,,	650.00	,,
4.	Similishahi	,,	,,	123	,,	320.06	,,
5.	Chakradharpur	,,	,,	124	,,	130.00	,,
6.	Kudapalpasi	,,	,,	125	,,	437.80	Full
7.	Sendhapal	,,	,,	126	,,	428.00	Part
8.	Golagadia	,,	,,	53	,,	1025.59	Full
9.	Kaunsidhipa	,,	Sarpada	63	,,	574.89	,,
10.	Chhotabereni	,,	,,	64	,,	458.47	Part
11.	Raijharan	,,	,,	61	,,	2329.86	Full
12.	Kankarei	,,	,,	65	,,	564.25	Part
13.	Malibrahmani	,,	,,	68	,,	664.37	Full
14.	Nisa	,,	,,	69	,,	335.90	Part
15.	Barakerajang jungle	Angul	,,	60	,,	156.00	,,
16.	Jaipur D.P.F.				,,	570.00	,,
17.	Durgapur R.F.				,,	3890.00	,,
18.	Maradahariharpur	Talcher	Colliery	55	,,	307.20	,,
19.	Kumunda	,,	,,	,,	,,	199.48	,,

Total area—13, 216.97 acres (approximately or—5,348.64 hectares (approximately)

Boundary description :

A-B line passes through villages Kosala, Nandichhod, Kundajhari Jungal and Durgapur reserve forest and meets at point 'B';

B-C-D lines pass through villages Durgapur reserve forest and Barakerajang Jungle, then passes along part Northern boundary of village Barakerajang Jungle and meets at point 'D';

D-E line passes along part northern boundary of village Kaliakata and Nisa and through Village Nisa (which) forms part common boundary of Gopal Prasad Block notified u/s 4 (I) of the C.B.A. (A and D) Act and meets at point 'E'.

E-F-G lines pass through village Nisa (eastern boundary of Road) then part along northern boundary of village Malibrahmani), then passes through villages Kankarei, Chhotabereni (along part river buondary), then passes through villages Kumunda and Maradahariharpur [which forms part common boundary of Gopalprasad block notified u/s 4(1) of the C.B.A. (A and D) Act, 1957) and meets at point 'G'.

G-A line passes through villages Maradahariharpur, Jaipur D.P.F., Sendhapal, Chakradharpur, Similisahi and Kosala and meets at starting point 'A'.

[No. 19/56/83-CL]

नई दिल्ली, 23 मार्च, 1984

का०आ० 1155 —केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3631 ता० 11 अक्तूबर, 1982 के राजपत्र, भाग 2 खंड 3, उपखंड (ii) ता० 23 अक्तूबर, 1982 में प्रकाशित की गई थी। द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने और उड़ीसा सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 1472 एकड़ (लगभग) या 505.69 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अपेक्षा करती है कि उक्त अनुसूची में वर्णित 1472 एकड़ (लगभग) या 595.69 हैक्टर (लगभग) माप की भूमि का अर्जन किया जाता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण जिला मजिस्ट्रेट, धेनकानल (उड़ीसा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1-काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता-700 001 के कार्यालय में या सेन्ट्रल कोल फील्ड्स, लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची, (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

अनन्त बेरिनी ब्लाक तालचेर कोयला क्षेत्र जिला धेनकानल उड़ीसा

रेखांक संख्या राजस्व/11/83

तारीख 7-2-1983

(जिसमें अर्जित की गई भूमि दर्शित की गई है)

सभी अधिकार :

क्रम सं०	ग्राम	थाना	उपखंड	ग्राम सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1.	नकईपासी	कोयला खान	तालचेर	32	धेनकानल	86.45	भाग
2.	दसरथीपुर	तालचेर	तालचेर	69	धेनकानल	40.06	पूर्ण
3.	पदमावतीपुर	कोयला खान	तालचेर	37	धेनकानल	298.50	भाग
4.	रकास	तालचेर	तालचेर	59	धेनकानल	121.50	भाग
5.	अनन्त बेरिनी	कोयला खान	तालचेर	2	धेनकानल	506.18	पूर्ण
6.	परिक्षपुर	कोयला खान	तालचेर	38	धेनकानल	53.05	पूर्ण
7.	लक्ष्मणपुर	कोयलाखान	तालचेर	135	धेनकानल	191.79	भाग
8.	बैदेरबर	कोयलाखान	तालचेर	51	धेनकानल	174.47	भाग
			कुल क्षेत्र	1472.00 एकड़ (लगभग)			
			या	595.69 हैक्टर (लगभग)			

ग्राम नकईपासी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

91 (भाग), 92 (भाग), 93 (भाग), 94 (भाग), 95 से 105, 106 (भाग), 107 (भाग), 114 (भाग), 115 (भाग), 119 (भाग), 120, 121, 122 (भाग), 123 (भाग), 124 (भाग), 126 (भाग), 127 (भाग), 2061, 2062 (भाग), और 2063 (भाग).

ग्राम दसरथीपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 से 41 तक.

ग्राम पदमावतीपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

48 (भाग), 49 से 56, 57 (भाग), 58 (भाग), 59 से 62, 63 (भाग), 64 (भाग), 65 से 71, 72 (भाग), 93 (भाग), 106 (भाग), 107 से 659, 660 (भाग), 661 (भाग), 662 (भाग), 663 से 667, 668 (भाग), 669 से 673, 675 से 688 690, 691 (भाग), 692 (भाग), 695 से 716.

ग्राम रकास में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

363 (भाग), 377, 378, 379 (भाग), 380, 391, 382 (भाग), 383 से 453, 454 (भाग), 455, 456, 457 (भाग), 460 (भाग), 461 (भाग), 462 से 467, 516 (भाग), 517 से 530, 531 (भाग,) 532, 533 (भाग), 534, 535 (भाग), 551 (भाग), 599 (भाग), 600 (भाग), 601 (भाग), 612 (भाग), 613, 614, 615, 616 (भाग), 617 (भाग), 618 (भाग), 622 (भाग), 623 (भाग), 624 (भाग), 625 (भाग), 626 से 668, 669 (भाग), 671, 672 और 673.

ग्राम अनन्त बेरिनी में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 से 1176

ग्राम परिक्षपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 से 79

ग्राम लक्ष्मणपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 से 34, 35(भाग), 36, 37, 38, 39, 40 (भाग), 41 से 56, 57 (भाग), 58, 59, 60 (भाग), 61 (भाग), 67 (भाग), 68 (भाग), 69 (भाग), 76 (भाग), 77 (भाग), 83 (भाग), 85, 86, 95 (भाग), 96 (भाग), 97 (भाग), 98, 99 (भाग), 100 से 227, 228 (भाग), 231 से 273, 274 (भाग), 275 और 276.

ग्राम बैदेस्वर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक :

1 से 321 तक.

सीमा वर्णन :

क–ख	रेखा ग्राम नकईपासा में प्लाट संख्यांक 126, 124, 123, 122, 94, 93, 92, 2063, 91 और 2062 से होकर जाती है फिर ग्राम पदमावतीपुर में प्लाट संख्यांक 93, 691, 660, 692, 668, 106, 661, 72, 663, 48, 57, 58, 63, 64 से होकर ग्राम रकास में प्लाट संख्यांक 382, 379 से होकर फिर प्लाट संख्यांक 376 और 375 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्यांक 363, 457, 454, 461, 460, 516, 531, 533, 535, 551, 612, 616, 617, 618, 625, 624, 623, 622, 601, 599, 600, 599 और 669 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।
ख–ग	रेखा ग्राम रकास और मधुपुर (अल्हाद नगर), रकास और दामोदरपुर (अल्हाद पुर), अनन्त बेरिनी और दामोदरपुर (अल्हाद नगर), जगबल पुर और दामोदरपुर (अल्हाद पुर), लक्ष्मणपुर और नखलपुर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित दामोदर ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "ग" पर मिलती है।
ग–घ	रेखा ग्राम लक्ष्मणपुर और नखलपुर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।
घ–ङ–च–छ	रेखाएं ग्राम लक्ष्मणपुर में प्लाट संख्यांक 274, 57, 60, 61, 40 से होकर प्लाट संख्यांक 41 की भागतः पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती हैं, प्लाट संख्यांक 40, 35, 67, 68, 69, 76,77, 95, 96, 97, 99 से होकर प्लाट संख्यांक 86 और 95 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ प्लाट संख्यांक 83 और 228 से होकर प्लाट संख्यांक 231 की भागतः उत्तरी सीमा के साथ-साथ, फिर ग्राम लक्ष्मणपुर और भरतपुर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1) के अधीन अर्जित भरतपुर ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिन्दु "छ" पर मिलती है।
छ–ज–झ	रेखाएं ग्राम लक्ष्मणपुर और बालन्दा, लक्ष्मणपुर और बड़ा सिंगदा की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "झ" पर मिलती है।
झ–ञ–ट–ठ–ड	रेखाएं ग्राम लक्ष्मणपुर और जामू बहाली, बैदेस्वर और जामू बहाली पवित्रपुर और जामू बहाली पवित्रपुर दानरा, अनन्त बेरिनी और दानरी, पदमावतीपुर और दानरा, दसरथीपुर और दानरा की सम्मिलित सीमाग्राम नकईपासा और दानरा की भागतः सीमा के साथ साथ जाती है [जो कोयला अधिनियम की धारा 9(1)] के अधीन अर्जित नंदिरा ब्लाक (पश्चिमी नालन्दा) की सम्मिलित सीमा बनाती है और बिन्दु "ड" पर मिलती है।
ड–क	रेखा ग्राम नकईपासी में प्लाट संख्यांक 91, 106, 107, 114, 116, 119, 127 और 126 से होकर जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[सं० 19/10/83-सी०एल०ए]

समय सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd March, 1984

S.O. 1155 .—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy/(Department of Coal) No. S.O 3661 dated the 11th October, 1982 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 23rd October, 1982 under sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification:

And whereas the competent authority, in pursuance of section 8 of the said Act, has made his report to the Central Governmen

And whereas the Central Government, after considering the report aforesaid and, after consulting the Government of Orissa, is satisfied that the lands measuring 1472.00 acres (approximately) or 595.60 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 9 of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands measuring 1472.00 acres (approximately) or 595.69 hectares (approximately) described in the said Schedule are hereby acquired.

2. The plans of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta 700001 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

SCHEDULE

Ananta Berini Block Talcher Coalfield Distt. Dhenkanal Orissa

Drg. No Rev/11/83
Dated : 7-2-1983
(Showing lands acquired)

All Rights

Sl. No.	Village	P.S.	Sub-Division	Village No.	District	Area	Remarks
1.	Nakaipasi	Colliery	Talcher	32	Dhankanal	86.45	Part
2.	Dasarathipur	Talcher	,,	69	,,	40.06	Full
3.	Padamabatipur	Colliery	,,	37	,,	298.50	Part
4.	Rakas	Talcher	,,	59	,,	121.50	Part
5.	Ananta Berini	Colliery	,,	2	,,	506.18	Full
6.	Pabitrapur	,,	,,	38	,,	53.05	Full
7.	Lachhmanpur	,,	,,	135	,,	191.79	Part
8.	Baideswar	,,	,,	51	,,	174.47	Full
		Total area :—	1472.00 acres (approximately)				
		or	595.69 hectares (approximately)				

Plot numbers acquired in village Nakaipasi :—

91(Part), 92(Part), 93(Part), 95(Part), 95 to 105, 106(Part), 107(Part), 114(Part), 115(Part), 119(Part), 120, 121, 122(Part), 123 (Part), 124 (Part,) 126(Part), 127(Part), 2061, 2062(Part), and 2063(Part).

Plot numbers acquired in village Dasarathipur:—1 to 41.

Plot numbers acquired in village Padmabatipur:—48(Part), 49 to 56, 57 (Part), 58 (Part), 59 t o 62, 63 (Part), 64 (Part), 65 to 71, 72 (Part), 93 (Part), 106 (Part), 107 to 659, 660 (Part), 661 (Part), 662 (Part), 663 to 667, 668 (Part), 669 to 673 , 675 to 688, 690, 691 (Part), 692 (Part), 695 to 716.

Plot numbers acquired in village Rakas:—363 (Part), 377, 378, 379 (Part), 380, 381, 382 (Part), 383 to 453, 454 (Part), 455, 456, 457 (Part), 460 (Part), 461 (Part), 462 to 467, 516 (Part), 517 to 530, 531 (Part), 532, 533 (Part), 534, 535 (Part), 551 (Part), 599 (Part), 600 (Part), 601 (Part), 612 (Part), 613, 614, 615, 616 (Part), 617 (Part), 618 (Part), 622 (Part), 623 (Part), 624 (Part), 625 (Part), 626 to 668, 669 (Part), 671, 672 & 678.

Plot numbers acquired in village Ananta Berini :—1 to 1176.

Plot numbers acquired in village Pabitrapur:—1 to 79.

Plot numbers acquired in village Lachhmanpur:— 1 to 34, 35 (Part), 46, 38, 39, 40 (Part), 41 to 56, 57 (Part), 58, 59, 60 (Part), 61 (Part), 67 (Part), 68 (Part), 69 (Part), 76 (Part), 77 (Part), 83 (Part), 85, 86, 95 (Part), 96 (Part), 97 (Part), 98, 99 (Part), 100 to 227, 228 (Part), 231 to 273, 274 (Part), 275 and 276.

Plot numbers acquired in village Baideswar:—1 to 321.

Boundary description:—

A-B	Line passes through plot numbers 126, 124, 123, 122, 94, 93, 92, 2063, 91 & 2062 in village Nakaipasi, then through plot numbers 93, 691, 660, 692, 668, 106, 661, 72, 662, 48, 57, 58, 63, 64 in village Padmabatipur through plot numbers 382, 379, then along the southern boundary of plot numbers 376 & 375, through plot numbers 353, 457, 454, 461, 460, 516, 531, 533, 535, 551, 612, 616, 617, 618, 625, 624, 623, 622, 601, 599, 600, 599 and 669 in village Rakas and meets at point 'B'.
B-C	line passes along the part common boundary of village Rakas and Madhupur (Alhadnagar) Rakas and Damodarpur (Alhadnagar), Ananta Bereni and Damodarpur (Alhadnagar) Lachhmanpur and Damoderpur (Alhadnagar), Lachhmanpur and Nakhatrapur (which forms common boundary of Damodarpur Block u/s 9(1) of the Coal Act) and meets at point 'C'.
C-D	line passes along the part common boundary of village Lachhmanpur and Nakhatrapur and meets at point 'D'.
D-E-F-G	Lines pass through plot numbers 274, 57, 60, 61, 40, along part eastern boundary of plot number 41, through plot numbers 40, 35, 67, 68, 69, 76, 77, 95, 96, 97, 99 along eastern boundary of plot numbers 86 and 95 through plot numbers 83 and 228, along part northern boundary of plot number 231 in village Lachhmanpur, then along the part common boundary of villages Lachhmanpur and Bharatpur (which forms common boundary of Bharatpur Block u/s 9(1) of Coal Act) and meets at point 'G'.
G.H.I	linse pass along the common boundary of villages Lachhmanpur and Balanda, Lachhmanpur and Badasingada and meets at point 'I'.
I.J.K.L.M	Lines pass along the common boundary of Lachhmanpur and Jambubahali, Baideswar and Jambubahali, Pabitrapur and Jambubahali, Pabitrapur and Danra, Ananta Bereni and Danara, Padmabatipur and Danra, Dasarathipur and part Danra, part common boundary of villages Nakaipasi and Danra (which forms common boundary of Nandira Block (West Balanda) acquired u/s 9 (1) of Coal Act) and meets at point 'M'.

M-A line passes through plot numbers 91, 106, 107, 114, 115, 119, 127 and 126 in village Nakipasi and meets at strating point 'A'.

[No. 19/10/83-CL]

SAMAY SINGH, Under Secy.

का० आ० 1156 :—मिश्रित हींग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1982 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० 965, तारीख 12 नवम्बर, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग-III खंड 3, उपखंड (1), तारीख 4 दिसम्बर, 1982 के पृष्ठ 2714 से 2718 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशनी तारीख से पैंतीलीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 9 दिसम्बर, 1982 को उपलब्ध करा दी गई थीं,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत जनता से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम लागू होना और प्रारम्भ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मिश्रित हींग श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1984 है।

(2) ये भारत में उत्पादित मिश्रित हींग को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित हो—

(1) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है।

(2) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(3) "प्राधिकृत पैकर" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति का निकाय अभिप्रेत है जिसे मिश्रित हींग के संबंध में साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1937 के नियम 3 के अधीन प्राधिकरण प्रमाणपत्र दिया गया है,

3. श्रेणी अभिधान—मिश्रित हींग की क्वालिटी उपदर्शित करने वाला श्रेणी अभिधान वह होगा, जो अनुसूची I के स्तम्भ 1 में उपवर्णित है।

4. क्वालिटी की परिभाषा—मिश्रित हींग की क्वालिटी वह होगी जो प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने अनुसूची I के स्तम्भ 2 से 6 में उपवर्णित है।

5. श्रेणी अभिधान चिन्हन (1) श्रेणी अभिधान चिह्न, कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्रदाय किया गया एक ऐसा लेबल होगा जिसमें श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा और ऐसा डिजाइन बना होगा जिसमें भारत की रूपरेखा मानचित्र एगमार्क शब्द और "Produce of India" तथा "भारतीय उत्पाद" शब्दों सहित उगते हुए सूर्य का चित्र होगा, जो अनुसूची II में उपवर्णित डिजाइन के सदृश होगा।

(2) प्लास्टिक या टिन के आधान पर प्रयुक्त किया जाने वाला श्रेणी अभिधान चिन्ह एक चिपकाया जाने वाला लेबिल या ऐसा ढक्कन होगा जिस पर वह वस्तु और श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा।

(3) बी-ट्विल जूट के थैलों पर प्रयुक्त किया जाने वाला श्रेणी अभिधान चिह्न एक आयताकार बाँधा जाने वाला लेबल होगा जिस पर वह वस्तु तथा श्रेणी अभिधान विनिर्दिष्ट होगा।

6. पैक करने की पद्धति—मिश्रित हींग को मजबूत, स्वच्छ शुष्क प्लास्टिक आधान या प्लास्टिक टिन के आधान या पालीथिन के अस्तर वाले बी० ट्विल जूट के थैलों या पालीथिन के थैले या किसी ऐसे अन्य आधान में, जो कृषि विपणन सलाहकार समय-समय पर अनुमोदित करें, पैक किया जाएगा। आधानों में पैक की गई मिश्रित हींग का शुद्ध भार 5 ग्राम, 10 ग्राम 15 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 कि०ग्रा० और तत्पश्चात् एक एक कि०ग्रा० के गुणकों में होगा।

(2) आधान को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से बंद और सीलबन्द किया जाएगा।

(3) प्रत्येक पैकेज में एक ही श्रेणी अभिधान की मिश्रित हींग होगी।

7. चिन्हांकन पद्धति— (1) श्रेणी अभिधान चिह्न कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अनुमोदित रीति से प्रत्येक आधान पर मजबूती से चिपकाया जाएगा।

(2) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त प्रत्येक ऐसे आधार पर, जिस पर चिपकाया जाने वाला या बाँधा जाने वाला लेबल या ऐसा ढक्कन होगा जिस पर श्रेणी अभिधान चिन्ह मुद्रित हो,

निम्नलिखित विशिष्टयाँ भी स्पष्टत: और अमिट रूप से दी जाएंगी, अर्थात्:—

(क) वस्तु का नाम,

(ख) लाट का क्रम संख्यांक,

(ग) पैक करने का नाम,

(घ) पैक करने का स्थान,

(ङ) पैकर का नाम,

(च) शुद्ध भार, और

(छ) कोई अन्य विशिष्टि जो कृषि विपणन सलाहकार विनिर्दिष्ट करे

(3) प्रत्येक आधान पर वस्तु की विक्रय कीमत स्पष्ट रूप से उपदर्शित की जाएगी।

(4) प्रत्येक आधान पर मिश्रण में प्रयुक्त खाने योग्य स्टार्च या खाने योग्य अनाज का आटा भी उपदर्शित होगा।

(5) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार से पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् और उसके द्वारा अनुमोदित रीति से आधान पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न अंकित करेगा परन्तु यह तब जबकि प्राइवेट व्यापार चिह्न इन नियमों के अनुसार आधान पर चिपकाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा मिश्रित हींग की उपदर्शित क्वालिटी या श्रेणी से भिन्न क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित न करे—

अनुसूची—1

(नियम 3 और 4 देखिए)

मिश्रित हींग (बधिनी हींग) के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी की परिभाषा				
	विशेष अपेक्षाएं				साधारण अपेक्षाएं
	कुल राख* भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	विलयित एच सी एल में अविलेय* राख, भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	अल्कोहली* निष्कर्ष (90 प्रतिशत अल्कोहल सहित) (न्यूनतम)	आर्द्रता भार के अनुसार प्रतिशत (अधिकतम)	
1	2	3	4	5	6
अतिविशेष	6.0	1.0	10.0	12.0	मिश्रित हींग (बधिनी हींग) :
विशेष	8.0	1.25	8.0	12.0	(1) हींग की एक या अधिक किस्मों (ईरानी या पठानी या दोनों) और खाने योग्य स्टार्च या खाने योग्य अनाज के आटों के साथ अरबी गोंद को मिलाकर बनाई जायेगी।
मानक	10.0	1.50	5.0	12.0	(2) कोलोफोनी राल, गालबानम राल* अमोनिया राल किसी अन्य बाह्य राल, तारकोल विरंजकों तथा खनिज वर्णकों तथा किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त होगी।
					(3) कीड़ों और फंफूदी के आक्रमण, कृतंक संक्रमण और बाह्य दुर्गन्ध से मुक्त होगी।

*हींग के लिये समय समय पर यथा संशोधित जांच की भारतीय मानक पद्धतियों का, जो भा०मा० 7807-1975 में प्रकाशित की गई थी, जांच के लिये अनुपालन किया जायेगा।

अनुसूची II

नियम 5 देखें

श्रेणी अभिधान चिह्न का डिजाइन

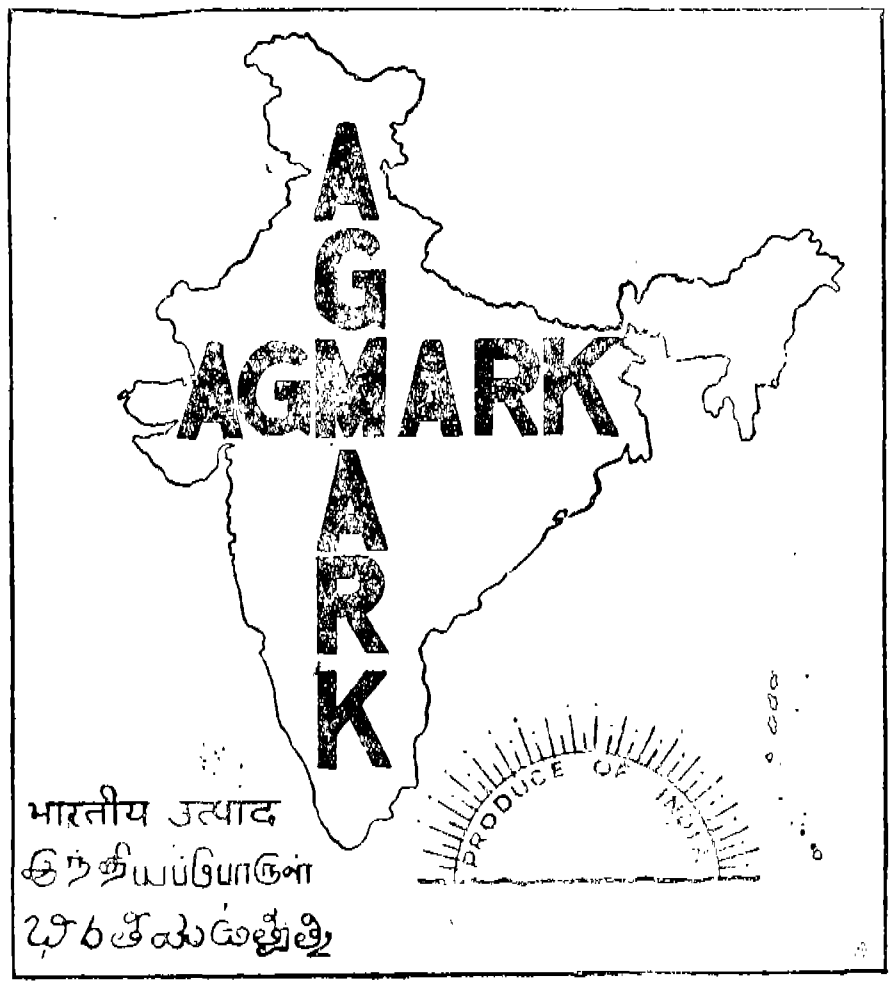

[सं० 11-2/81एम I]

[बी० के० बजाज, अवर सचिव]

S.O. 1156.—Whereas a draft of Compounded Asafoetida Grading and Marking Rules, 1982 was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 2714 to 2718 of the Gazette of India, Part II. Section 3, Sub-section (i), dated the 4th December, 1982 with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development at G.S.R. 965, dated the 12th November, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 9th December, 1982;

And whereas comments/suggestions received from the public in respect of the said draft have been cossidered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules :—

RULES

1. Short title, application and commencementn.—(1) These rules may be called the Compounded Asafoetida Grading and Marking Rules, 1984.

(2) They shall apply to compounded asafoetida produced in India.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(1) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(2) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(3) "Authorised packer" means a person or a body of persons who have been issued a Certificate of Authorisation under rule 3 of the General Grading and Marking Rules, 1937 in relation to compounded asafoetida.

3. Grade designation.—The grade designation to indicate the quality of the compounded asafoetida shall be as set out in column 1 of Schedule I.

4. Definition of quality.—The quality of the compounded asafoetida shall be as set out in columns 2 to 6 of Schedule I against each grade designation.

5. Grade designation mark.—(1) The grade designation mark shall consist of a label supplied by the Agricultural Marketing Adviser specifying the grade designation and bearing the design consisting of an outline map of India with the word "AGMARK" and the figure of the rising sun with the words "Produce of India" and "भारतीय उत्पाद" resembling the mark as set out in Schedule II.

(2) The grade designation mark to be used on plastic container or tin container shall consist of a paste-on label or lid specifying the commodity and grade designation.

(3) The grade desigation mark to be used on B-twill jute bags shall consist of a rectangular tie-on label specifying the commodity and grade designation.

6. Method of packing.—(1) Compounded asafoetida shall packed in sound, clean, dry plastic cotnainer or lacquered tin container or B-twill jute bags with polythene lining or polythene bag or any other container as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser from time to time. The net weight of the compounded asafoetida packed in a container shall be 5 gms, 10 gms, 15 gms, 20 gms, 25 gms, 50 gms, 100 gms, 200 gms, 500 gms, and 1 kg. and thereafter in multiples of 1 kg.

(2) The container shall be securely closed and sealed in such a manner as may be approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) Each package shall contain compounded asafoetida of the same grade designation.

7. Method of marking.—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to each container in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) In addition to the grade designation, every container bearing a paste-on label, tie-on label or lid printed with grade designation mark shall be clearly and indelibly marked with following particulars, namely :—

(a) name of the commodity,

(b) serial number of lot,

(c) month of packing,

(d) place of packing,

(e) name of the packer,

(f) net weight, and

(g) any other particular as may be specified by the Agricultural Marketing Adviser,

(g) any other particular as may be specified by the dicated on each container.

(4) Every container shall also indicate the approximate composition of edible starch or edible cereal flour used in compounding.

(5) An authorised packer may, after obtaining the prior approval of, and in a manner approved by the Agriculturl Marketing Adviser, mark his private trade mark on a container provided that the private trade mark does not represent quality of grade of compounded asafoetida different from the indicated by the grade designation mark affixed to the container in accordance with these rules.

SCHEDULE—I

(See rules 3 and 4)

Grade designations and definition of quality of compounded asafoetida (Bandhani Hing)

Grade designations	Definition of quality				
	Special requirements				General requirements
	Total ash* per cent by weight per cent (maximum)	*Ash insoluble in dilute HCL by weight (maximum)	*Alcoholic extract with 90 per cent of alcohol (maximum)	*Moisture per cent by weight (maximum)	
1 2	3	4	5	6	7
Extra Special	6.0	1.00	10.0	12.0	Compounded Asafoetida (Bandhani Hing)
Special	8.0	1.25	8.0	12.0	shall :
Standard	10.0	1.50	3.0	12.0	(1) be made by blending one or more varieties of asafoetida (Irani or

	pathani hing or both) and gum arabic with edible starches or edible cereal flour;
(2)	be free from *colophony resin, *galbanum resin, *ammonicacum resin, *any other foreign resin, coaltar dyes and mineral pigments and any other foreign matter;
(3)	be free from insect and fungus attack, rodent contamination and foreign odour.

*Indian Standard methods of test for asafoetida published in IS : 7807 1975, as amended from time to time shall be followed for testing.

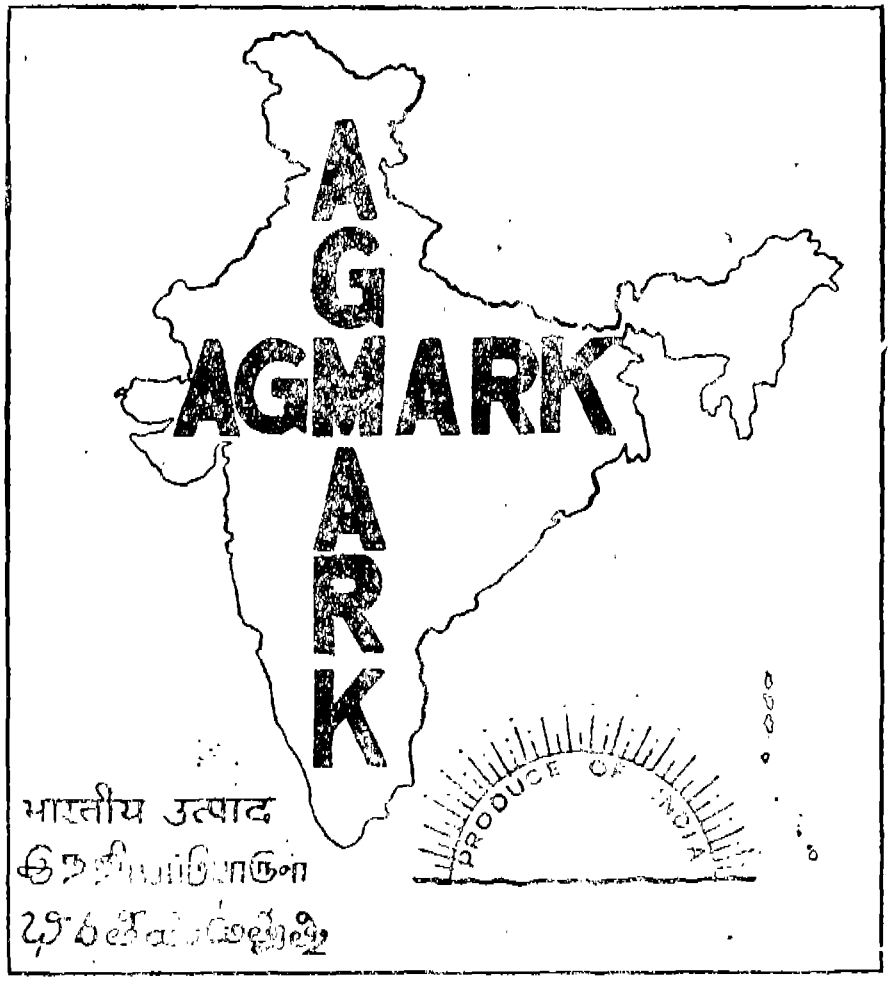

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1984

का०आ 1157.—जीरा बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1983 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० 1863 तारीख 31-3-1983 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 16-4-1983 के पृष्ठ 1837 और 1840 पर प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा उस तारीख से जिसको उस राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराई गई थी पैंतालीस दिन की समाप्ति से पहले, उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 2 मई, 1983 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केन्द्रीय सरकार को, उक्त प्रारूप की बाबत जनता से कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम जीरा बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन (संशोधन) नियम, 1984 है।

2. जीरा बीज, श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1969 में

(1) अनुसूची ii के स्तम्भ 6 में, "1.5", "3.0", "4.0" और "5.0" अंकों के स्थान पर क्रमशः "3.0", "6.0", "8.0" और "10.0" अंक रखे जाएंगे।

टिप्पण : (1) मूल नियम, अर्थात् जीरा बीज श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 1969 जिससे 1964 का नियम निरसित किया गया था, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (4) तारीख 25-10-69 में का०आ० 4302 के रूप में प्रकाशित किए गए थे।

(2) उक्त नियमों का पहले संशोधन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 25-12-1979 में पृष्ठ संख्या 3515 का० आ० 4011 के रूप में प्रकाशित किया गया था।

[सं० एफ० 10-3/82-एम० आई०]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1157.—Whereas the draft of the Cumin Seeds Grading and Marking (Amendment) Rules, 1983, was published as required by the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at page numbers 1939 and 1840 of Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16-4-1983, with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development S.O. 1863 dated 31-3-1983, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of fortyfive days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification is published, are made available to the public ;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on 2-5-1983 ;

And whereas no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said draft rules by the Central Government ;

Now, thertfore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. These rules may be called the Cumin Seeds Grading and Marking (Amendment) Rules, 1984.

2. In the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969—

(1) in Schedule II, column 6 for the figures "1.5", "3.0", "4.0" and "5.0" shall respectively be substituted the figures "3.0", "6.0", "8.0" and "10.0".

Note.—1. The Principal rules, i.e. Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1969 repealing the Cumin Seeds Grading and Marking Rules, 1964 were published at page numbers 4625—4629 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 25-10-1969 as S.O. 4302.

2. The first amendment to the said rules were published at page number 3515 of the Gazette of India, Part II, Stction 3, Sub-section (ii), dated 15-12-1979 as S.O. 4011.

[No. F. 10—3/82-M.I.]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1984

का० आ० 1158.—कड़े बालों का श्रेणीकरण और चिन्हन (संशोधन) नियम, 1983 का एक प्रारूप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०आ० सं० 1805, तारीख 17 अप्रैल, 1983 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 9 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 1784 से 1789 पर प्रकाशित किया गया था। इसके द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 अप्रैल, 1983 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप के संबंध में कोई टीका-टिप्पणी या सुझाव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कड़े बालों का श्रेणीकरण और चिन्हन (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कड़े बालों का श्रेणीकरण और चिन्हन नियम, 1969 में—

(1) और नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :—

"(2) ये शूकर शावकों, बधिया शूकरों और नर शूकरों से अभिप्राप्त कड़े बालों और ऐसे कड़े बालों को उनके ऊपर के छोर पर या नीचे के छोर पर काटकर अभिप्राप्त करे हुए कड़े बालों को, जिनका भारत में उत्पादन होता है, लागू होंगे।"

(2) नियम 2 में,—

(क) उपनियम (1) में "अनुसूची एक से लेकर अनुसूची 9 तक" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 1 से 9क" शब्द अंक अक्षर रखे जायेंगे :

(ख) उपनियम (2) में "अनुसूची 10 और अनुसूची 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर "अनुसूची 10 से 11क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे।

(3) नियम 3 में "अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 9 तक" और "अनुसूची 10 और अनुसूची 11" शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः "अनुसूची 1 से 9क" और "अनुसूची 10 से 11क" शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे :

(4) नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(11) कड़े बालों का प्रकार, उदाहरणार्थ मुलायम या कड़ा/आधा कड़ा या अधिक कड़ा अथवा इन तीनों प्रकारों में से कोई कटे हुए कड़े बाल जो नीचे के छोर पर या ऊपर के छोर पर काटे गये हों ;"

(5) अनुसूची 9 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 9क

कटे हुए कड़े बालों का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी की परिभाषा

(नियम 2 और 3 देखें)

श्रेणी अभिधान (लम्बाई)	विशेष लक्षण		साधारण लक्षण
	रंग	प्रकार	
1	2	3	4
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है*	सफेद	ऊपर के छोर वाले अधिक कड़े कटे हुए कड़े बाल नीचे के छोर वाले अधिक कड़े कटे हुए कड़े बाल	1. ऊपर के छोर वाले कड़े बाल, कड़े बालों के नीचे के छोर को काटकर अभिप्राप्त किये जायेंगे जो 57 मि०मी० और उससे अधिक के श्रेणी अभिधान के अनुरूप हैं जैसा कि अनुसूची 1 से 9 में विहित है।
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है*	—यथोक्त—		
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है।*	सफेद	ऊपर छोर वाले कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल	2. नीचे के छोर वाले कड़े बाल कड़े बालों के ऊपर के छोर को काटकर अभिप्राप्त किये जायेंगे जो 57 मि०मी० और उससे
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है।	—यथोक्त—	नीचे के छोर वाले कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल	अधिक के किसी श्रेणी अभिधान के अनुरूप है जैसा कि अनुसूची 1 से 9 में विहित है।
—यथोक्त—	—यथोक्त—	ऊपर के छोर वाले मुलायम कटे हुए कड़े बाल	3. प्रत्येक प्रकार के कटे हुए कड़े बालों को पृथक पृथक पैक किया जायेगा।
—यथोक्त—	—यथोक्त—	नीचे के छोर वाले मुलायम कटे हुए कड़े बाल	
—यथोक्त—	—यथोक्त—	ऊपर के छोर वाले अधिक कड़े कटे हुए कड़े बाल	4. कटे हुए कड़े बालों को अभिप्राप्त करने के लिये कड़े बालों को काटने की सम्पूर्ण संक्रिया विपणन और निरीक्षण निदेशालय के किसी अधिकारी के पर्यवेक्षण में की जाएगी।
	—यथोक्त—	नीचे के छोर वाले अधिक कड़े कटे हुए कड़े बाल	
—यथोक्त—	—यथोक्त—	ऊपर के छोर वाले कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल	5. कड़े बालों की गांठों के नीचे के/ऊपर के छोर विपरीत या उसी दिशा से हो सकते हैं।
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है	काले —यथोक्त—	नीचे के छोर वाले कटे हुए कड़े/आधे कड़े बाल ऊपर के छोर मुलायम कटे हुए कड़े बाल।	6. सभी कटे हुए कड़े बालों पर ठोस ड्रैसिंग होगी और उनके वही अर्थ होंगे जो अनुसूची 1 से 9 में उनके हैं सिवाय इस के कि कटे हुए कड़े बालों की लम्बाई जो
वह लम्बाई जो फर्म आदेश में विनिर्दिष्ट है	—यथोक्त—	नीचे के छोर वाले मुलायम कटे हुए कड़े बाल।	अनुसूची 1 से 9 में दिये गये किसी श्रेणी अभिधान के लगभग हैं, लम्बाई में सह्यता सीमा को निश्चित करने के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट श्रेणी अभिधान लम्बाई (जिन्हें "सिरे" कहा गया है) समझी जायेगी।
—यथोक्त—	भूरा	ऊपर के छोर वाले अधिक कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल	7. रंग सह्यता सीमायें वही होंगी जो उन कड़े बालों के विहित है जिनमें कटे हुए कड़े बाल अभिप्राप्त किए गये हैं।
—यथोक्त—	भूरा	नीचे के छोर वाले अधिक कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल।	
—यथोक्त—	—यथोक्त—	ऊपर के छोर वाले कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल।	
—यथोक्त—	—यथोक्त—	नीचे के छोर वाले कड़े/आधे कड़े कटे हुए कड़े बाल।	

*फर्म आदेश से अभिप्रेत है कि संविदाकृत माल का सम्पूर्ण मूल्य भारत में प्रत्यप्रतिष्ठित अप्रतिहस्तांतरणी प्रत्यय पत्र खोलकर अग्रिम रूप से अभिप्राप्त कर लिया गया है जो लदान की रसीद द्वारा समर्थित पोतपरिवहन बिल के उपस्थापित किये जाने पर भुनाया जा सकता है या किसी अन्य रूप में प्रत्याभूत है।

(6) अनुसूची 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्—

"अनुसूची 10क"

[नियम 2(2) और 3 देखें]

विशेष श्रेणी कटे हुए कड़े बाल

कटे हुए कड़े बालों के लिये अनुसूची 10-क में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त विशेष श्रेणी कटे हुए कड़े बाल निम्नलिखित अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेंगे, अर्थात् :—

1. (1) ऊपर के छोर वाले विशेष श्रेणी कटे हुए कड़े बाल, 57 मि०मी० लम्बाई और उससे अधिक के ऐसे विशेष श्रेणी कटे कड़े बालों को नीचे के छोर पर काटकर अभिप्राप्त किया जायेगा जो अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हों।

(2) नीचे के छोर वाले विशेष श्रेणी कटे हुए कड़े बाल 57 मि०मी० लम्बाई और उससे अधिक के ऐसे विशेष श्रेणी कटे हुये कड़े बालों को ऊपर के छोर पर काटकर अभिप्राप्त किये जायेंगे जो अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

2. रंग स्वच्छता सीमा वही होगी जो उन कड़े बालों के लिये विहित है जिनसे कटे हुये कड़े बाल अभिप्राप्त किये गये हैं ;

(7) अनुसूची 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

अनुसूची 11क

[नियम 2(2) और 3 देखें]

चयन श्रेणी कर्तन कड़े बाल विशेष श्रेणी कटे हुए कड़े बालों के लिये अनुसूची 10-क में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त, चयन श्रेणी कटे हुए कड़े बाल लीखों (बधिया शूकरों के जूओं द्वारा छोड़े गए अण्ड समूटकों) से मुक्त होंगे और कर्तन कड़े बालों की गांठों में प्रति गांठ 10 सन्निमित बाल से अधिक नहीं होंगे और वे वही होंगे जो चयन श्रेणी कड़े बालों से अभिप्राप्त किये गये हैं।

टिप्पण :—(1) मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 16-8-1969 में का०आ०सं० 3245 तारीख 5-8-1969 के रूप में प्रकाशित किये गये थे ।

(2) इन नियमों का प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 16-8-1969 में का०आ०सं० 3484 तारीख 30-7-73 के रूप में प्रकाशित किया गया था ।

[सं०एफ० 10-6(82)-एम०-I]
बी०के० बजाज, अवर सचिव

New Delhi, the 24th March, 1984

S.O.1158.—Whereas a draft of the Bristles Grading and Marking (Amendment) Rules, 1983 was published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) at pages 1784 to 1789 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 9th April, 1983 with the notification of the Government of India in the Ministry of Rural Development S.O. No. 1805 dated the 17th March, 1983 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of forty five days from the date of publication in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said gazette were made available to the publication the 18th April, 1983;

And whereas no comments or suggestions have been received from the public in respect of the said draft by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section of 3 the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Bristles Grading and Marking (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bristles Grading and Marking Rules, 1969,—

(1) in rule 1, in sub-rule (2), for the words "and boars and" the words "and boars and to cut bristles obtained from such bristles by cutting either flag ends or root ends, which are" shall be substituted;

(2) in rule 2—

(a) in sub-rule (1), for the words and figures "Schedules I to IX", the words, figures and letter; "Schedules I to IX-A" shall be substituted;

(b) in sub-rule (2), for the words and figures, "Schedules X and XI" the words, figures and letter, "Schedules X to XIA" shall be substituted;

(3) in rule 3, for the words and figures "Schedules I to IX" and "Schedules X and XI", the words, figures and letter, "Schedules I to IX-A" and "Schedules X to XI-A" shall, respectively, be substituted;

(4) for clause (ii) of sub-rule (2) of rule 5, the following clause shall be substituted, namely :

"(ii) Type of bristles, i.e.....soft or stiff/semi-stiff or extra stiff or cut bristles of any of these three types with either flag ends cut or root ends cut";

(5) after Schedule IX, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE—IX—A"

Grade designations and definition of quality of cut bristles.

(See rules 2 and 3)

Grade Designation (Length)	Special Characteristics		General Characteristics
	Colour	Type	
1	2	3	4
Length as specified in the firm order*	White	Extra stiff cut bristles with flag ends.	1. Cut bristles with flag bends shall be obtained by cutting root ends of bristles conforming to any grade designation from 57 mm and above as prescribed in Schedules I to IX.
Length as specified in the firm order*	-do-	Extra stiff cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Stiff/semi-stiff cut bristles with flag ends.	2. Cut bristles with root ends shall be obtained by cutting flag ends of bristles conforming to any grade designation from 57 mm and above as prescribed in Schedules I to IX.
Length as specified in the firm order*	-do-	Stiff/semi-stiff cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with flag ends.	3. Cut bristles of each type shall be packed separately.
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	Black	Extra stiff cut bristles with flag ends.	4. The entire operation of cutting the bristles for obtaining the cut bristles shall be carried out under the supervision of an officer of the Directorate of Marketing and Inspection.
Length as specified in the firm order*	-do-	Extra stiff cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Stiff /Semi-stiff cut bristles with flag ends	5. Bundles of bristles can have root flag ends and cut ends in opposite or same direction.
Length as specified in the firm order*	Black	Stiff/semi-stiff cut bristles with flag ends	6. All cut bristles shall be solid dressed and shall have the same meaning as given in the foot note to Schedules I to IX except that the length of the cut bristles nearer to any grade/designation length given in Schedules I to IX shall be taken as specified grade designation length (called 'tops') for the purpose of ascertaining tolerance limits in length.
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with flage ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	Grey	Extra-stiff cut bristles with flag ends.	7. Colour tolerance limits shall be the same as that prescribed for bristles from which cut bristles have been obtained.
Length as specified in the firm order*	-do-	Extra-stiff cut bristles with root end.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Stiff/Semi-stiff cut bristles with flag ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Stiff/Semi-stiff cut bristles with root ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with flag ends.	
Length as specified in the firm order*	-do-	Soft cut bristles with root ends.	

*"Firm Order" means that the entire value of goods contracted for should have been obtained in advance by opening a cent percent irrevocable letter of credit in India which is encashable on the production of a shipping bill supported by receipt of shipment or guaranteed in any other way.

(6) After Schedule X, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE X-A

[See Rules 2(2) and 3]

Special Grade Cut Bristles.

In addition to the requirements specified for cut bristles in Schedule IX-A, Special grade cut bristles shall satisfy the following requirements, namely :

1. (i) Special Grade cut Bristles with flag ends shall be obtained by cutting root ends of Special Grades of Bristles of lengths 57 mm and above conforming to requirements specified in Schedule X;

(ii) Special Grade Cut Bristles with root ends shall be obtained by cutting flag ends of Special Grades of Bristles of lengths 57 mm and above conforming to requirements specified in Schedule X.

2. Colour tolerance limits shall be the same as that prescribed for bristles from which cut bristles have been obtained."

(7) After Schedule XI, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE XI-A

[See rules 2(2) and 3]

Select Grade Cut Bristles.

In addition to the requirements specified for Special Grade Cut Bristles in Schedule X-A, Select Grade Cut Bristles shall be free from nits (egg capsules left by hoglice) and bundles of cut bristles shall not contain more than 10 infested hairs per bundle and shall be those obtained only from Select Grades of Bristles".

NOTE (1) Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 16-8-1969 vide S.O. No. 3245, dated 5-8-1969.

(2) First amendment to these rules was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 15-12-1973 vide S.O. No. 3484, dated 30-7-1973.

[No. F. 10-6(82)/M-I]

B.K. BAJAJ, Under Secy.

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1984

का० आ० 1159.—अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 (1971 का 43) की धारा 3 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण में वर्तमान मुख्य अभियन्ता श्री एच०एस० भाटिया को उसी संगठन में, उनके द्वारा उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 नवम्बर, 1985 तक पूर्णकालिक सदस्य (इंजीनियरिंग) नियुक्त करती है।

[एवी० 24012/2/83-ए०ए०-एफ०-II]

आर० एन० भार्गव, अवर सचिव

MINISTRY OF TOURISM AND CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th March, 1984

S.O. 1159.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the International Airports Authority Act, 1971 (43 of 1971), the Central Government hereby appoints Shri H. S. Bhatia presently Chief Engineer in the International Airports Authority of India as a whole-time Member (Engineering) in the same organisation with effect from the date of his assuming charge of the higher post upto 2nd November, 1985.

[AV-24012/2/83-AA-F. II]

R. N. BHARGAVA, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1984

का० आ० 1160.—चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(1) और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 8 के उप नियम (1) और (2) के साथ पठित नियम 7 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि निम्नलिखित व्यक्ति 1-4-1984 से केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बम्बई सलाहकार पैनल के सदस्य नहीं रहेंगे :—

1. श्रीमती हेलानी (कु० एम० भट्ट)
2. श्रीमती उमा दा कुन्हा
3. श्रीमती मृनालिनी देसाई
4. श्रीमती के० पी० हरमालकर
5. श्रीमती कनलोलिनी हजारत
6. श्रीमती रेखा विपिन खखड़
7. श्रीमती प्रणयिनी मुन्शी
8. श्रीमती पन्ना रेजी
9. श्रीमती शान्ता सेहल्के
10. श्रीमती सरोजनी वैद्य
11. श्रीमती विजया मेहता
12. श्री हरीश मनोट
13. श्री वी०याई० गाडगिल
14. श्री जगमोहन
15. श्री फादर रिचर्ड रोन स्मिथ
16. डा० एस० डी० मिश्र
17. डा० (श्रीमती) आर० ककड़
18. श्री सुधीर वी० नान्दगांवकर
19. श्री बद्री नारायण
20. श्री सी० एल० प्रभात
21. प्रो० ए० जी० मीरचन्दानी
22. श्री एम० के० वर्मा..
23. श्री राम सहाय एम० पांडेय
24. बेगम सुरैया सैयद
25. श्री नरायण राव एस० छगन
26. डा० (कु०) लेखा पाठक
27. डा० (श्रीमती) इन्दुमति बिशनोई
28. बेगम नीलुफर बी० कपाडिया
29. श्री सुरेश शर्मा
30. श्री आर० सी० अग्रवाल
31. श्रीमती सुधा जोशी
32. श्री जयन्त अनन्त खेर
33. श्रीमती सुधा गोयल
34. श्री मोहन पजाबी
35. श्री मोरेश्वर वी० वनमाली
36. डा० चन्द्र कान्त एस० काम्बली
37. श्री डी० एन० देसाई
38. श्री जी० वी० कामथ
39. श्री वी०जी० महादेवकर
40. डा० ए० यू० शेख
41. श्री आर० पी० देसाई
42. श्री आई० एच० मदमसी

[फाइल संख्या 811/2/83-एफ(सी)]

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1160.—In exercise of the powers conferred by section 5(1) of the Cinematograph Act 1952 and sub-rule (3) of rule 7 read with sub-rules (1) and (2) of rule 8 of the

Cinematograph (Certification) Rules 1983, the Central Government hereby directs that the following persons will cease to be members of the Bombay Advisory Panel of the Board of Film Certification with effect from 1st April 1984.

1. Smt. Hola (nee Kum. S. Bhatt)
2. Smt. Uma da Cunda
3. Smt. Mrinalini Desai
4. Smt. K. P. Harmalkar
5. Smt. Kallolini Hazarat
6. Smt. Rokha Vipin Khakhar
7. Smt. Pranayini Munshi
8. Smt. Panna Raiji
9. Smt. Shanta Sohlko
10. Smt. Sarojini Vaidya
11. Smt. Vijaya Mehta
12. Shri Harish Bhanot
13. Shri V. Y. Gadgil
14. Shri Jagmohan
15. Father Richard Lane-Smith
16. Dr. S. D. Mishra
17. Dr. (Mrs.) R. Kakkar
18. Shri Sudhir V. Nandgaonkar
19. Shri Badri Narayan
20. Shri C. L. Prabhat
21. Prof. A. G. Mirchandani
22. Shri M. K. Verma
23. Shri Ramsahai S. Pandey
24. Begum Surgiya Syed
25. Shri Narayanrao S. Chavan
26. Dr. (Kumari) Lekha Pathak
27. Dr. (Smt.) Indumati Bishnoi
28. Begum Nilufar B. Kapadia
29. Shri Suresh Sharma
30. Shri R. C. Agarwal
31. Smt. Sudha Joshi
32. Shri Jayant Anant Kher
33. Smt. Sudha Goyal
34. Shri Mohan Punjabi
35. Shri Moreshwar B. Vanmali
36. Dr. Chandrakant S. Kambli
37. Shri D. N. Desai
38. Shri G. V. Kamath
39. Shri B. G. Mahadeokar
40. Dr. A. U. Sheikh
41. Shri R. P. Desai
42. Shri I. H. Padamee.

[File No. 811/2/83-F(C)]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

का०आ० 1161.—चलचित्र अधिनियम, 1952(1952 का 37) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों (वीडियो फिल्मों को छोड़कर) के संबंध में फिल्म की एक प्रिंट/वीडियो कापी को जमा करने से संबंधित चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 के नियम 28 के उप नियम (1) के उपबंधों से 17-3-84 से 16-6-84 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट देती है कि आवेदक फिल्म की शूटिंग स्क्रिप्ट को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जमा करेगा।

[फाइल संख्या 806/21/83-एफ (सी)]

के० एस० वेंकटरामन, अवर सचिव

New Delhi, the 21st March, 1984

S.O. 1161.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby grants exemption from the provisions of sub-rule (1) of rule 28 of the Cinematograph (Certification) Rules 1983 relating to deposit of a print/video-copy of the film in respect of films (excluding video films) certified by the Central Board of Film Certification for the period 17-3-84 to 16-6-84 subject to the condition that the applicant shall deposit a shooting script of the film to the Central Board of Film Certification.

[File No. 806/21/83-F (C)]

K. S. VENKATARAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1162.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Coalfileds Ltd., and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

Reference No. 69 of 1982

In the matter of an Industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Coalfields Limited and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Adtary, Bihar Colliery Kamgar Union.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 5th March, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24011(9)/81-D.IV(B) dated the 16th July, 1982.

SCHEDULE

"Whether the transfers of S/Shri A. K. Banerjee, Operator, K. S. Yadav-Clerk Gr. II, K. K. Chatterjee Electrician, Narayan Gope, Operator, S. S. Gupta, Operator and B. N. Roy, LDC from Kothra Colliery Washery remains justified ? If not, to what remedy, if any, the workers are entitled ?"

After receiving notices the management and the concerned workmen filed their W.S. and rejoinders and also filed documents in support of their respective cases. During the hearing of the case a petition was filed on behalf of the concerned workmen on 28-2-84 stating that the subject matter of the present reference case No. 69 of 1982 is concerning the validity of the order of the transfer of the concerned workmen. After the order of their transfer the concerned workmen refused to carry out the transfer order and did not join the places where they were transferred. Thereafter the management issued chargesheet against the concerned workmen for violating transfer order and after holding an enquiry dismissed them from services for disobeying the order of transfer. The validity and the justification of the dismissal of the concerned workmen was the subject matter in another reference case No. 136/82. The said reference case No. 136/82 has already been disposed of by the Presiding Officer of the Central Government Industrial Tribunal (No. 2), Dhanbad by which an Award has been passed in favour of the workmen holding that the transfer order was illegal besides other matters. It is submitted on behalf of the workmen that as the subject matter of the present Reference

case No. 69 of 1982 has already been adjudicated upon in Reference No. 136 of 1982, the present reference has become infrustuous.

Shri R. S. Murthy, Advocate appearing on behalf of the employers also concedes that the matter in adjudication in Reference No, 69 of 1982 has been decided in Reference No. 136/82.

In view of the fact that the subject matter of Reference No. 69 of 1982 has already been adjudicated upon in Reference No. 136 of 1982 and the concerned workmen have got their relieves which they had sought for, now there is no necessity of giving a fresh adjudication on the same point which has been decided in favour of the concerned workmen. I hold therefore, that the concerned workmen have already obtained relief in Reference No. 136 of 1982 in respect of the matter which is involved in the present reference and as such the present reference has become infructuous and no order need to be passed for any relief.

This is my Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24011/9/81-D.IV (B)]

New Delhi, the 19th March, 1984

S.O. 1163.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bokaro Colliery of Central Coalfields Ltd., P.O. Bermo, Distt. Giridih and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. (2) AT DHANBAD

Reference No. 51 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bokaro Colliery of Central Coalfields Limited, P.O. Bermo, District Giridih and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 3rd March, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(4)/82-D.IV(B) dated the 11th May, 1982.

"Whether the action of the management of Bokaro Colliery of Central Coalfields Limited, Post Office Bermo, District Giridih in retiring Shri Kishun Satnami, Ex. Hookman with effect from 19-9-81 is justified? If not, to what relief is the workman entitled ?"

The case of the concerned workman is that his date of birth is 22-6-1926 and as such he is to retire in the year 1986. The management forcibly retired the concerned workman w.e.f. 19th September, 1981. The Deputy Chief Mining Engineer of Bokaro Colliery by the order dated 9-3-81 passed an order for retirement of the concerned workman alleging that he would attain the age of 60 years.

The case of the management on the other hand is that during the year 1979 the concerned workman desired that his age should be assessed by the age committee and his request was accepted by the committee as he was not subject to initial medical examination at the time of his appointment and his service sheet was also incomplete. The concerned workman appeared before the age committee on 19-9-79 and his age was assessed by the age committte as 58 years on that date. Subsequently an entry to this effect was made in the service sheet of the concerned workman and in token of having accepted the same, he affixed his L.T.I. against the said entry in the service sheet. As the concerned workman attained the age of superannuation on 19-1-81, he was retired from service from that date. A notice of superannuation had been given to the workman concerned in advance on 9-3-81 but he did not raise any objection to it.

When the case was fixed for hearing the concerned workman sent a petition dated 12-1-84 stating that he does not want to pursue the case after medical examination by the age committee as he was correctly assessed as 58 years of age on 9th September, 1979 and was properly and correctly retired from the service w.e.f. 19-9-81 by the management of Bokaro Colliery. He has further stated that he does not press any claim against Bokaro Colliery and as he is too old to do any work he is not in a position to work. Shri S. Bose representing the workman has submitted that in view of the said petition of the concerned workman he does not want to press the case and that the award may be given accordingly.

In view of the fact that the concerned workman accepts the assessment of age committee and submits that he was correctly retired from service w.e.f. 19-9-81. I hold that the action of the Management of Bokaro Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. in retiring the concerned workman Shri Kishun Satnami, Ex-Hookman w.e.f. 19-9-81 is justified. In view of the above findings and also in view of the fact that the workman concerned does not press any claim, the concerned workman is entitled to no relief.

This is my award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. L-24012(4)/82-D.IV (B)]

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1164.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Giridih Colliery of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) AT DHANBAD

Reference No. 22 of 1982

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Giridih Colliery of M/s. C. C. Ltd. and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri R. S. Murthy, Advocate.

On behalf of the workmen.—Shri J. N. Rana, Secretary, United Coal Workers Union, Giridih.

STATE : Bihar. INDUSTRY ; Coal.

Dhanbad, the 7th March, 1984

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-24012(21)/81-D.IV(B) dated the 1st March, 1982.

SCHEDULE

"Whether the action of the management in depriving S/Shri Bhim Tiwari, Ramu Gope and Barhan Gope of under-ground allowance by shifting them on surface duty to operate Russian Pumps w.e.f. 1-3-81 without 21 days notice as required under Section 9A of the Industrial Disputes Act, 1947, is justified & legal ? If not, to what relief are the workmen entitled ?"

The case of the management is that Giridih Colliery is a very old mine which was opened by East Indian Railway. Sometime in the sixties a decision was taken to close down the said mines altogether and with that end in view the workers were dispersed to other collieries of NCDC to which Giridih Colliery vested w.e.f. 1-10-56. The underground mines of Giridih Colliery were practically exhausted but due to political pressure NCDC was directed by the Government of India to continue mining operations irrespective of un-economical workings. Thereafter NCDC tried to exploit the upper seams although the quality of the coal was not marketable at that time. Subsequently with the growing need of the country even the said coal in the top seems also became marketable and open cast operations were taken up in hand. After the underground mines were virtually abandoned, persons engaged therein were transferred to other areas and some of the workers were brought to work on the surface on alternative or similar jobs. The three concerned workmen S/Shri Bhim Tiwari, Ramu Gope and Barnan Gope working underground as Pump Khalasies were given similar jobs and were asked to operate submersible pumps of Russian type w.e.f. 1-3-81 without changing their category and wages. All these 3 concerned workmen had gained experience of operating pumps underground and as such the similar jobs and were asked to operate submeresible upmps of jobs in a newly open cast project only with the difference that instead of operating conventional pumps underground, they were required to operate submersible pumps of Russian type. The concerned workmen and their unions demanded that since the concerned workmen operating pumps in underground were getting underground allowance, they should be given underground allowance even when they were brought to work on the surface. They asserted that alternative jobs given to the concerned workmen from underground to surface was in violation of Section 9A of the Industrial Disputes Act., 1947 and that in any case they should be given additional allowance. The management asserted that underground allowance was payable only when a workman actually works underground and it is the absolute discretion of the management to deploy a workman to its best advantage either on the surface or in the underground mines. Only when a workman works underground that he is entitled to get underground allowance and as soon as he is brought up to work on the surface of the mines he will not be entitled to the underground allowance which he was getting while working underground. The workmen are doing exactly the same job which they were doing underground and as such there was no change in the conditions of their service requiring any notice under Section 9A of the I.D. Act., 1947, before transferring them on the surface.

The case of the management, further, is that since the last 20 years the underground mining operations were drastically curtailed and after sometime the underground mining operations will have to be completely closed. The underground mines of upper Kurharbari incline, Kabribad incline and Dhobidi Mines are being worked in Giridih Colliery and underground pumps are in operations in these mines but the production of the upper Kurharbari incline is only 20 tonnes of coal per day, Kabribad incline has production of about 25 tonnes of coal per day and Dhobidi mines has production of only 10 tonnes of coal per day and these mines cannot be kept working on such a low coal production, but they are being worked solely for providing continued employment to existing workers even at a great loss. The workmen engaged in operations of pumps in these underground mines are not juniors to the concerned workmen.

The case of the concerned workmen is that they were doing the job of pump khalasi in underground mines of M/s. CCL Giridih Colliery for more than 10 years and were drawing underground allowance and other allowances. The management of CC. Ltd's Giridih Colliery is running underground mines at Kabribad incline, Upper Kurharbari incline and Dhobidi Project where underground pumps are in operations. Inspite of the fact that undergrcund mines are in operations in the above 3 mines, underground pumps are operated by unauthorised workmen and pump Khalasies junior to the concerned workmen but the concerned workmen have not been transferred to these underground mines for operating the pumps. The management has changed the service conditions of the concerned workmen from the roll of colliery manager Giridih to the roll of colliery Manager patch deposit scheme putting them at pecuniary loss without any proper notice w.e.f. 1-3-1981. For operating submersible pumps of Russian type the management should have trained such workmen who were willing to change their service conditions voluntarily. The management did not transfer the concerned workmen bonafidely and changed the service conditions involving recuniary loss of leave with wages, C.M.P.F. contributions etc. as per Section 9A of the I.D. Act, 1947 and the 4th Schedule of the Act. There was no exigency of work and the avenue of underground pump Khalasies job has not exhausted. The management changed the conditions of service of the concerned workmen unilaterally affecting adversely their service conditions. The workmen and their union made a demand from the management to restore the service conditions of the concerned workman but to no effect. An industrial dispute was raised before the A.L.C.(C), Hazaribagh ultimately resulting in failure of the conciliation proceedings. It has been prayed on behalf of the concerned workmen that the action of the management in depriving them of underground allowance by shifting them on surface due to operate Russian pumps w.e.f. 1-3-81 without 21 days notice as required under Section 9A of the I.D. Act, 1947 is illegal and unjustified and that the service conditions of the concerned workmen be restored as underground pump khalasies with retrospective effect and full benefit.

Two questions appear to be in dispute namely (a) Whether the action of the management in depriving the concerned workmen of underground allowance by shifting them on surface duty to operate Russian Pumps w.e.f. 1-3-81 without 21 days notice as required under Section 9A of the I.D. Act, 1947 is justified and (2) Whether the management was justified in transferring the concerned workmen from underground to the surface. So far the second dispute is concerned I think the reference does not cover it and as such this reference is confined for adjudication of only the dispute whether the action of the management in depriving the concerned workmen of underground allowance w.e.f. 1-3-81 without 21 days notice as required under Section 9A of the I.D. Act, 1947 is justified.

The management has examined one witness in support of the case. The workmen have not examined any witness. However, some documents have been exhibited on behalf of both the parties. MW-1 has stated that Giridih Colliery presently belonging to M/s. CCL was started about 100 years ago and previously it had underground mines producing premium coking coal. He has stated that when the reserve of premium coaking coal was exhausted, the management started incline mining in patches which are known as Kolinmaran, new incline, 17B incline, Dhobidi incline and Khandiha incline and that all these inclines are now closed. He has stated that thereafter open cast mining was started which produced low grade of coal. He has stated that the workmen are not employed specifically for underground mining or surface mining and some of the categories of workmen work both underground and on the surface mines and they are transferred from underground mines to surface mines and vice-versa and in case the workers are transferred from the surface to the underground they are allowed underground allowance and when an underground worker is transferred on surface mines, they are not allowed underground allowance as the underground alowance is not a condition of service. He has proved an Order Ext. M-1 dated 5-3-81 by which the three concerned workmen along with other were transferred and posted on the surface mines. He has further stated that vide Ext. W-1 the concerned workmen were transferred from upper Kurharbari inclined to patch deposit scheme and they were working as Pump Khalasies on the surface which used to supply water to the colony. In his cross-examination he has conceded that the under-

ground mining is presently being worked at Dhobidi Project and upper Kurharbari incline. He has also admitted that the concerned workmen were working underground. He has stated that the workmen working underground get one day E.L. in 16 day's of work but the workmen working on the surface get one day E.L. in 20 day's of work. He has also admitted that no notice under Section 9A of the I.D. Act was given to the concerned workmen on the transfer from the underground mines to the surface. He has accepted that there is difference of working conditions of workers working underground and on the surface. Thus, from his evidence it is clear that there is difference of working conditions of wokmen working underground and workmen woking on the surface.

It will be apparent from the facts stated in the W.S. and the evidence of MW-1 that there was difference of working conditions of the concerned workmen on the surface as compared with the working conditions while they were working underground. It will appear that they used to get underground allowance, more E.L., more subscription and contributions payable by the employer to the CMPF. The concerned workmen were working underground submit that they will be deprived of these advantages on their being transferred to work on the surface. The Section 9A of the I.D. Act, 1947 runs thus :—

> "No employer, who proposes to effect any change in the conditions of service applicable to any workmen in respect of any matter specified in the 4th Schedule, shall effect such change—
>
> (a) Without giving to the workmen likely to be affected by such change a notice in the prescribed manner of the nature of the change proposed to be effected; or
>
> (b) Within 21 days of giving such notice provided. . ."

Provision of Section 9A of the Act comes into operations the moment an employer proposes to change in conditions of service applicable to any workmen, and one this is done 21 days notice has to be given to the workmen. Admittedly, no notice was given under Section 9A of the I.D. Act to the concerned workmen. The object of Section 9A of the I.D. Act, as observed by the Hon'ble Supreme Court in M/s. TISCO Ltd. versus the workmen reported in (1972) (2) SCC-333 (1972 Lab. I.C.P-1123) is as follows :—

> "The real object and purpose of enacting Section 9A seems to be to afford an opportunity to the workmen to consider the effect of the proposed change, and, if necessary, to represent their point of view on the proposal. Such a consultation further serves to stimulate a feeling of common joint interest of the management and workmen in the industrial practice and increased productivity. This approach on the part of the industrial employer would reflect his harmonious and sympathatic co-operation in improving the status and dignity of the industiral employee in accordance with the egalitarian and progressive tend of our indsutrial jurisprudence, which strives to treat the capital and labour as co-sharers and to break away from the traditions of labours subsurvence to capital."

The real test as to the circumstances in which Section 9A would apply, is laid down by the Hon'ble Supreme Court in the above quoted observations. In the present case the grant of underground allowance, more E.L. and more contributions by the employer to C.M.P.F. were implied conditions of service of the concerned workmen while they were working underground and that by withdrawing those allowances the employer effected a change adversely and materially affected the service conditions of the workmen and as such Section 9A of the I.D. Act was applicable and the non-compliance of the provisions before transferring the concerned workmen from underground to surface were unjust and not in accordance with law. Section 9A of the I.D. Act comes into operations the moment the employer proposes to change any condition of service applicable to a workman and 21 days notice has to be given to the workmen. The management, undoubtedly, effected substantial change in the conditions of service because the workmen were deprived of the underground allowance more E.L. and more contributions by the employer towards CMPF. There is no question before the Tribunal for going into the matter on merit whether the management had a right to transfer the concerned workmen from underground mines to the surface. The only point fell for determination was whether there was any change in the conditions of the service of the workmen and whether the provisions of Section 9A of the I.D. Act were complied with. I have discussed above that there was change in the conditions of service of the concerned workmen due to their transfer from underground to the surface requiring 21 days prior notice under Section 9A of the I.D. Act and that the provisions of Section 9A has not been complied with.

In view of the facts, evidence, circumstances and the principles of the provisions of Section 9A of the Industrial Disputes Act involved, I hold that the action of the management in depriving the concerned workmen to underground allowance and other benefits by shifting them to surface duty to operate Russian Pumps w.e.f. 1-3-81 without 21 days' notice as required under Section 9A of the I.D. Act was not justified and legal. In the above view of the matter the concerned workmen are entitled to the underground allowance and other benefits which they were getting while wroking underground w.e.f. 1-3-81.

However, it is still open to the management to give a notice under Section 9A of the I.D. Act if they like to effect the proposed change in the conditions of services applicable to the concerned workmen.

This is my Award.

Sd/-

I.N. SINHA, Presiding Officer
[No. L-24012(21)/81-D.IV(B)]

C. D. BHARDWAJ, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, तारीख 2 मई, 1983

का० आ० 1165.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बड़ौदा बैंक, अहमदाबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एम० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय निर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या बड़ौदा बैंक, कायरा क्षेत्र, अहमदाबाद के प्रबन्धतन्त्र की अपनी शाखा सन्तपीपाली, नडियाड के पीयन-कम-वाचमैन श्री जगदीश चन्द्र एन० वालन्द की 18-9-77 से सेवायें समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित अकर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[संख्या एल-12012/299/82-डी-II (ए)]

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1983

S.O. 1165.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bank of Baroda, Ahmedabad, and their workman in respect of the matter specified in the schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bank of Baroda, Kaira Region, Ahmedabad in relation to its Santpipali Branch, Nadiad in terminating the services of Shri Jagdishchandra N. Valand, Peon-cum-Watchman, with effect from 18-9-77 is justified: If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/299/82-D.II.(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1983

का० आ० 1166.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में देना बैंक, चिखली के प्रबंधतंत्र से संबंधित एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याया-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या प्रादेशिक प्रबन्धक, देना बैंक, प्रादेशिक कार्यालय, सूरत का अपने ज्ञापन सं० आर० ओ० पी० ई० आर० 282/82, तारीख 15-2-82 के अधीन अपनी शाखा समरोली, डाकघर चिकली, बुल्सन के संबंध में यह मानने की कार्यवाही न्यायोचित है कि अधीनस्थ कर्मचारी श्री बी० के बरोदिया ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दी थी, यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।"

[सं० एल-12012/180/83-डी-2 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 28th December, 1983

S.O. 1166.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Dena Bank, Chikkli and their workman in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad; and refers the said dispute for adjudication in the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Regional Manager, Dena Bank, Regional Office, Surat in relation to their Branch Samroli, P.O. Chickli, Bulson in having treated Shri B. K. Barodia, Sub-staff, under their Memo. No. RO|PER|282|82 dt. 15-2-82 that he had abanded the job of his own volition is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-12012/180/83-D.II(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का० आ० 1167.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय स्टेट बैंक, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या भारतीय स्टेट बैंक, अहमदाबाद के प्रबन्धतंत्र की पुनीत आश्रम रोड़, मणिनगर, अहमदाबाद की अपनी शाखा के चौकीदार, श्री वी० जे० ठाकुर की अक्तूबर, 1982 में सेवायें समाप्त करने तथा फिर उसके नियोजन के लिये विचार न करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-12012/276/83-डी-2 (ए)]

एन० के० वर्मा, डेस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi the 28th February, 1984

S.O. 1167.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists beteen the employers in relation to the management of State Bank of India, Ahmedabad, and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot, shall be the Presiding Officer, with the headquarters at Ahmedabad, and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of State Bank of India, Ahmedabad in relation to their Punit Ashram Road Branch, Maninagar, Ahmedabad in terminating the services of Shri V. J. Thakkar, Watchman, in October, 1982 and not considering him for further employment is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-12012/276/83-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

ORDER

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1168.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Distt. Gaya and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD.

Reference No. 30 of 1983.

In the matter of an Industrial Dispute under S. 10 (1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India, Dahanabad Branch.

AND

Their workmen.

PRESENT : Sd/-

Shri I. N. Sinha, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of the employers.—Shri Niamatullah, Personnel Manager.

On behalf of the workmen.—Shri A. P. Pandey, General Secretary, State Bank of India Staff Association.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Bank.

Dhanbad, 8th March, 1984

AWARD

This is an Industrial Dispute under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its notification No. I-12012/288/82/D-II(A) dated 30-3-83 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication on the following terms:—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of the State Bank of India in relation to its Jahanabad Branch (Distt. Gaya) in terminating the services of Shri Ram Chandra Pandey. Temporary Messenger-cum-Guard with effect from 17-9-81 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

2. Soon after the receipt of the reference notices were issued upon the parties to file their written statement. Accordingly the union filed their written statement. Thereafter the parties prayed time for filing settlement in the matter. Ultimately the parties filed memorandum of settlement in this case in terms of which the management of the State Bank of India agrees to appoint Shri Ram Chandra Pandey, the concerned workman, provided he is found suitable. As the terms of the settlement are beneficial to both the parties, I accept the same and pass award accordingly. The settlement will form part of the Award.

I. N. SINHA, Presiding Officer

[No. I-12012/288/82-D.II(A)]

FORM—H

FORM FOR MEMORANDUM OF SETTLEMENT

Name of Parties :

Representing Employer.—Shri Niamatullah Personnel Manager.

Representing Workman.—Shri A. P. Pandey, General Secretary, State Bank of India Staff Association.

Workman.—Shri Ram Chandra Pandey.

Shri Ram Chandra Pandey was engaged as a temporary Guard-cum-Messenger at our A. D. B. Jehanabad and Jehanabad branches during 1980 to 1982. Altogether, he worked for 150 days as temporary Guard-cum-Messenger and for 238 days as daily wage labourer with occasional breaks. Shri Pandey's services were terminated on the 31st March, 1982, by our Jehanabad Branch without giving any retrenchment benefits to him. Shri Pandey aggrieved by the Bank's action in terminating his services raised an Industrial Dispute through the General Secretary, SBI Staff Association. The conciliation proceedings ended in failure. The concerned parties i.e. SBI Staff Association through its General Secretary, the aggrieved workman, Shri Ram Chandra Pandey and the Management of SBI through its Personnel Manager have entered with a settlement under Section 18 of the Industrial Disputes Act. The terms of the settlement are as under:—

(i) that the General Secretary, SBI Staff Association, will withdraw the Industrial Dispute raised by him on behalf of the workman, Shri Ram Chandra Pandey;

(ii) that the management of SBI agrees to appoint Shri Ram Chandra Pandey provided he is found suitable in the interview and medical examination and verification of his antecedents and fulfil the necessary qualification as per rules of the Bank;

(iii) that Shri Ram Chandra Pandey will have no claim of any nature whatsoever including back wages, arrears and seniority etc.

A. P. Pandey,
General Secretary.
SBI Staff Association.

Sd/- HIAMATULLAH,
Personnel Manager
State Bank of India,
Local Head Office, Patna.

Sd/-
(RAM CHANDRA PANDEY)
WORKMAN

Witnesses :

1. (A. Banerjee, Personnel Deptt., LHO, Patna).
2. (Anant Kumar Sinha, A.G.S., SBISA).

I. N. SINHA, Presiding Officer

S.O. 1169.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Chandigarh in the Industrial Dispute between the employers in relation to the State Bank of India, Chandigarh and their workmen which was received by the Central Government on 9-3-84.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CHANDIGARH.

Case No. I.D. 92/83 CHD; 112/81 (N. DELHI)

PARTIES :

Employers in relation to the management of State Bank of India.

AND

Their Workman.—Diwan Singh.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri V. K. Gupta.

For the Workman.—Shri J. G. Verma.

INDUSTRY : Banking. STATE : Chandigarh.

AWARD

Dated the 7th of March, 1984

The Central Government, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act 1947 vide their Order No. I-12012/28/80-D.II.A. dated the 30th of July, 1981 read with S.O. No. S-11025(2)/83 dated the 8th of June, 1983 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of State Bank of India, Chandigarh, in terminating the services of Shri Diwan Singh, Messenger with effect from 13-3-75 is justified ? If not, to what relief is the worker concerned entitled ?".

2. When the case came up for hearing, the parties reported a compromise and filed the Memo of Settlement Ex. C. 1. with a prayer to return a No-dispute Award and the submission that despite the fallacy of his cause, the Bank management have agreed to provide fresh employment to the petitioner|Workman purely on the ground of compassion.

3. On hearing the parties and persuing the records, I feel satisfied with the propriety of the Settlement whose terms and conditions are fair to both of them, and in particular to the Workman who now stands assured of re-employment. Therefore, on approving the same, I hereby return my Award in the following terms:

(a) Petitioner/Workman shall be re-employed in the Respdt. Bank's service as a fresh entrant without any benefit or claim for back wages or continuity of service for the intervening period.

(b) He shall be entitled to get only those benefits which otherwise are admissible as per his age on the date of fresh entry after the settlement.

(c) He shall be re-employed after he furnishes the requisite proof of his age to the satisfaction of the Bank Management.

(d) The instant settlement shall be taken as a one time arrangement and concession to an individual imposing no procedental obligations on the Bank's Management.

CHANDIGARH :

7-3-1984.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012|28|80-D.II(A)]

New Delhi, the 24th March, 1984

S.O. 1170.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. II, Bombay in the Industrial Dispute between the employers in relation to the Bank of Maharashtra, Pune, and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th March, 1984.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande.—Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2|40 of 1983

Employers in Relation to the Management of Bank of Maharashtra, Pune;

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers.—1. Shri D. J. Bhanage, Advocate.
2. Shri R. M. Nijampurkar, Officer.

For the Workmen.—1. Shri R. D. Jog, President, Bank of Maharashtra Karamchari Sangh. 2. Shri V. D. Karamarkar, Joint Secretary, Bank of Maharashtra Karmachari Sangh.

INDUSTRY : Banking. STATE : Maharashtra

Bombay, the 6th March, 1984

AWARD

(Dictated in the Open Court)

By their Order No. L-12012|87|83-D.II.A., dated 8-11-1983 the following dispute has been referred for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :

"Whether the action of the management of Bank of Maharashtra, Pune in relation to their Shrirampur Branch, Distt. Ahmednagar in terminating the services of Shri R. R. Yadav, a part-time clerk with effect from 30-4-81 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The facts giving rise to the present dispute lie in a narrow campus. Shri R. R. Yadav, was employed by the Bank of Maharashtra in Shrirampur Branch, District Ahmednagar as a part-time clerk to work for 12 hours in a week on 15-11-1976 and from the said time onwards till 1-5-1981 he continued to serve the Bank continuously on monthly wages equal to 1|3rd of the pay scale drawn by the regular clerks. Shri Yadav was graduated sometime in the year 1977 or so. Now on 1-5-1981, although the workman had put in more than 4 years of continuous service, without following the procedure under Section 25F of the Industrial Disputes Act i.e. without giving him one month's notice and offering retrenchment compensation equal to 15 days' salary for every year of service, the termination was tried to be brought out.

3. The workman therefore challenges the said termination and seeks the usual relief of reinstatement etc.

4. The Bank by their written statement have opposed the claim. It is contended that the termination was brought about because the workman ceased to be a student and that his continuance would have marred other students' prospects.

5. On the strength of the above pleadings the following issues arise for determination and my findings are:

Issues	Findings
1. Whether on the ground of loss of confidence the Bank could have removed Shri Yadav from service ?	Yes by following procedure
2. Does it not amount to retrenchment ?	Yes
3. Whether the graduation could have been treated as disqualification by the Bank ?	No
4. Is the removal void and illegal ?	Yes
5. If so, to what relief the workman is entitled ?	As per order
6. To what award ?	As per order.

REASONS

6. As already stated, the facts are not disputed and it stands admitted that during the period from 15-11-1976 to 1-5-1981 the workman was in service of the Bank continuously and that his salary was equal to 1|3rd of regular pay scale. Now once though as a part-timer, he was performing duties for 12 hours in a week, and once it is proved that he had put in more than 4 years service continuously, Section 25F can be attracted and while terminating the service the legal formalities laid down there shall have to be followed, otherwise the termination becomes bad and illegal. It can never be gain-said that the termination brought about by the Bank on 1-5-1981 without complying with the provision of Section 25F is bad and illegal and not justified at all.

7. It is stated that the workman initially an under-graduate, during the continuance of service became a graduate by passing Bachelor of Arts examination and I am given to understand he had earned on the strength of graduation the graduation increments. Now I can understand the policy of the bank, in order to render help to the students to enable them to complete their studies, to employ them as part-timer. But even in such case the graduation would never become a disqualification. Only thing it would be that it would open avenues for the employees to seek the regular employment by going through the requisite procedure. Naturally as part-timer merely because during the continuance of his service became a graduate should not be put against him because it can never be a misconduct. On this ground therefore there cannot be termination nor it would be a termination on the ground of any misconduct so as to avoid the attraction of the definition of retrenchment under Industrial Disputes Act. It would still be a termination on whatsoever reason.

8. However, when the question of reliefs is gone into, the fact that the workman was a student given the concession for working for 12 hours in a week so that he could complete his studies, will have to be borne in mind. If the workman had graduated it was his duty to apply for regular service through regular procedure and if he failed to do so, his continuance as a part-timer would not be of any use, neither to the workman nor to the Bank. On the contrary, a continuance of a workman who had completed his graduation would mean depriving of the opportunity which the Bank may extend to another student for com-

pletion of his studies. In my view therefore this is not a case of reinstatement and although the termination is bad and in contravention of provisions under Section 25F, the only relief to which the workman would be entitled is the back wages from 1-5-1981 till today at the rate equal to the wages he was earning on 30-4-1981 plus a compensation of Rs. 2,000. The Bank may consider to employ him regularly in case he is otherwise found to be suitable and secondly there is the discretion vesting in the Bank. After all having put in some years of service in the Bank, should he have if not a right atleast some concession, so that the workman should expect a permanent service with the Bank provided otherwise legally permitted.

Award accordingly.

dated : 7-3-84.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-12012/87/83-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1984

का० आ० 1171.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, मन्दामर्री डिवीजन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, मन्दामर्री डिवीजन, डाकघर-कल्याण खानी, अदिलाबाद (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र द्वारा कोल फिल्लर, श्री मेकाला राम पोशाम की 23-8-82 से सेवाएं समाप्त करना न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।

[सं० एल० 22011/45/83-डी 3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 13th March, 1984

S.O. 1171.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Co., Ltd., Mandamarri Division and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947, the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Singaroni Collieries Co. Ltd., Mandamarri Division P.O. Kalyani Khani. Distt. Adilabad (A.P.) are justified in dismissing Shri Mekala Raya Posham, Coal Filler, from service with effect from 23-8-82. If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-22011/45/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का०आ० 1172.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज लि०, डाकघर रामकृष्णपुर, जिला अदिलाबाद (आ०प्र०) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के प्रबंधतंत्र की लिपिक ग्रेड-I, श्री जी० हरिहरन को स्थानापन्न भत्ता देने से मना करने तथा पिट कार्यालय सहायक के रूप में उनका स्थायीकरण न करने की कार्यवाही न्यायोचित्य है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-22011/26/83-डी-3(बी)]

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 1172.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to the Messrs Singareni Collieries Co. Ltd. P.O. Ramakrishnapur, Distt. Adilabad (A.P.) and their workmen in respect of the matter specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., in denying payment

of Officiating allowance and confirmation to Shri G. Harihanan, Clerk Gr. I as Pit Office Assistant, is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

[No. L-22011/26/83-D.III(B)]

आदेश

का०आ० 1173.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, कोठागुडियम डिवीजन, डाकघर वेंकटेश खानी, जिला खम्माम (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबंधतन्त्र से संबद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, कोठागुडियम के प्रबंधतंत्र का 28-7-1981 से मुन्शी के रूप में कार्य कर रहे श्री कुडिपुडी सूर्यनारायण को नियमित आधार पर मुन्शी के पद के चुनाव के लिए न बुलाना तथा उसका मुन्शी के रूप में स्थायीकरण न करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है"

[सं० एल 22012/109/83-डी० III-बी०]

ORDER

S.O. 1173.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Singareni Collieries Co. Limited, Kothagudium Division P.O. Venkatesh Khani District Khammam (A.P.) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd. Kothagudium were justified in not calling Shri Kudipudi Suryanarayana acting as Munshi with effect from 28-7-1981 for selection to the post of Munshi on a regular basis? And not confirming him as Munshi? If not, to what relief is the workman concerned entitled?".

[No. L-22012(109)/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च 1984

का०आ० 1174.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, कोठागुडियम डिवीजन, डाकघर वेंकटेश खानी, जिला खम्माम (आ०प्र०) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, कोठागुडियम के प्रबंधतंत्र का सेरापर खलासी, श्री थल्ला दुर्गैया, को अपनी आयु के निर्धारण के लिए गैदरिंग स्टेशन न भेजना तथा उसे 31-1-83 को सेवा निवृत्त करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मचार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-22012/117/83-डी-III(बी)]

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1984

S.O. 1174.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to the Management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudium Division, P.O. Venkatesh Khani, Distt. Khammam (A.P) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudium are justified in not sending Shri Thalla Durgaiah, Seraper Khalasi, sand gathering station for assessment of his age and retiring him on 31-1-83. If not, to what relief is workman concerned entitled?"

[No. L-22012/117/83-D.III(B)]

आदेश

का०आ० 1175.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, कोठागुडियम डिवीजन, डाकघर वेंकटेश खानी, जिला खम्माम (आ० प्र०) के प्रबंधतन्त्र से संबंद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947(1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एस० श्रीनिवासन राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कॉलिअरीज कं० लि०, कोठागुडियम डिवीजन, डाकघर वेंकटेश खानी के प्रबंधतंत्र का सं० 5-ए इंक्लाइन में फिटर श्री टांगुटुरी पोशम, को 24-9-1980 से वर्ग-5 का वेतन देने से मना करना न्यायोचित है? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

[सं० एल-22012/112/82-डी-2(बी)]

ORDER

S.O. 1175.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudium Division, P.O. Venkatesh Khani Distt. Khammam (AP) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed.

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the management of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Kothagudium Division, P.O. Venkatesh Khani, are justified in refusing category V wages to Shri Tanguturi Posham, Fitter No. 5A Incline, with effect from 24-9-1980? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-22012/112/83-D.III(B)]

आदेश

का० आ० 1176.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, पश्चिम क्षेत्र बड़ौदा के ग्रुप महाप्रबन्धक के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7 क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या महाप्रबन्धक, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, पश्चिमी क्षेत्र, बड़ोदा के नैमित्तिक श्रमिक, श्री जी० यू० सिसोदिया की 16-5-75 से सेवाएं समाप्त करने की कार्यवाही वैध तथा न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मचार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-30012/5/83-डी-3 (बी)]

ORDER

S.O. 1176.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to the management of Group General Manager, Oil & Natural Gas Commission, Western Region, Baroda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of the sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be the Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the General Manager, Oil & Natural Gas Commission, Western Region, Baroda in terminating the services of Shri G. U. Sisodia, Casual Labour with effect from 16-5-1975 was legal and justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

[No. L-30012/5/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1984

का० आ० 1177.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में इंडिया सीमेन्ट लि० के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या इंडिया सीमेंट लि० के सूना पत्थर खदानों, धालाज्यू, पो, डाकघर शंकर नगर, जिला तिरुनेलवेली के प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने चूना पत्थर खदानों में वैगन ड्रिल आपरेटरों की सहायतार्थ जुटाए गए दो हैल्परों में से एक को वापिस लेना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो वैगन ड्रिल आपरेटर किस अनुतोष के हकदार है ?

[सं० एल-29011/79/83-डी-3 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1984

S.O. 1177.—Whereas the Central Government is of opinion that an Industrial Dispute exists between the employers in relation to the management of India Cements Ltd. and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10

of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Limestone Quarries of India Cements Limited, Thalaiyuthu, Sankarnagar Post Office, District Tirunelveli are justified in withdrawing one of the two Helpers provided to assist the Wagon Drill Operator in their Limestone quarries? If not, to what relief are the Wagon Drill Operators entitled?"

[No. L-29011/79/83-D.III(B)]

आदेश

का० आ० 1178.—इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट औद्योगिक विवाद श्री एम० वी० रमण रेड्डी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित पड़ा है, जिसे श्रम और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम विभाग) के आदेश संख्या एल-22011/24/83-डी-3 (बी) दिनांक 19 मई, 1983 के द्वारा उन्हें भेजा गया था ;

और श्री एम० वी० रमण रेड्डी की सेवाएं अब उपलब्ध नहीं रही हैं;

अतः, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ख की उपधारा (i) के साथ पठित धारा 7-क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम० श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त श्री एम० वी० रमण रेड्डी, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के समक्ष लंबित उक्त विवाद के संबंध कार्यवाही को वापस लेती है और उसे श्री एम० श्रीनिवास राव, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद को इस निदेश के साथ स्थानांतरित करती है कि उक्त अधिकरण आगे कार्यवाही उस प्रक्रम से करेगा, जिसपर वह उसे स्थानांतरित की जाए तथा विधि के अनुसार उनका निपटान करेगा ।

अनुसूची

"क्या सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० के प्रबन्धतन्त्र की मशीन माइनिंग आपरेटरों, मशीन माइनिंग हेल्परों तथा ए० ए०-50 आपरेटरों को (1) वर्दियां, (2) धुलाई भत्ता और (3) धूलि भत्ता देने से इन्कार करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-22011/24/83-डी-3 (बी)]

ORDER

S.O. 1178.—Whereas the Industrial Dispute specified in the Schedule hereto annexed is pending before Shri S. V. Ramana Reddy, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad, having been referred to him vide the Ministry of Labour & Rehabilitation (Department of Labour), Order No. L-22011(24)/83-D.III(B) dated the 19th May, 1983.

And whereas, the services of Shri S. V. Ramana Reddy are no longer available;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A read with sub-section (1) of Section 33B of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal, the Presiding Officer of which shall be Shri M. Srinivasa Rao with headquarters at Hyderabad and withdraws the proceedings in relation to the said dispute pending before Shri S. V. Ramana Reddy, Presiding Officer, Industrial Tribunal, Hyderabad and transfers the same to Shri M. Srinivasa Rao Presiding Officer Industrial Tribunal, Hyderabad with the directions that the said Tribunal shall proceed with the proceedings from the stage at which they are transferred to it and dispose of the same accordingly to law.

SCHEDULE

"Whether the management of Singareni Collieries Co. Ltd., is justified in not giving (1) Uniforms (2) Washing Allowance and (3) dust allowance to Machine Mining Operators, Machine Mining Helpers and A.M.-50 Operators?" and If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

[No. L-22011(24)/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1984

का० आ० 1179.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में विजयलक्ष्मन क्ले माइन्स, मुलावना डाकघर, कुन्दरा के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुलराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या विजय लक्ष्मन क्ले माइन्स, डाकघर मुलावना, कुन्दरा, जिला क्वीलोन के प्रबन्धतंत्र की खान सर्वेक्षक, श्री एस ब्रुनोस को 1-5-83 से बर्खास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-29012/57/83-डी-3 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 27th February, 1984

S.O. 1179.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Vijayalekshamana Clay Mines, Mulavana P.O., Kundara, and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arul Raj shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Vijayalekshmana Clay Mines, P.O. Mulavana, Kundara Quilon Dist. in dismissing from service Shri S. Brunose, Supervisor of the mine, with effect from 1-5-83 is justified ? If not, to what relief is the workman concerned entitled ?"

[No. L-29012/57/83-D.III(B)]

ORDER

New Delhi, the 27th March, 1984

S.O. 1180.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Bhubaneswar in the industrial dispute between the employers in relation to the Bolani Ore Mines of Durgapur Steel Plant of S.A.I.L and their workmen, which was received by the Central Government on the 20th March, 1984.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri J. M. Mahapatra, M.Com., LL.B.,
Presiding Officer,
Industrial Tribunal,
Bhubaneswar.

Industrial Dispute Case No. 5 of 1983 (Central)

Dated Bhubaneswar, the 15th March, 1984

BETWEEN

The employers in relation to the Bolani Ore Mines of Durgapur Steel Plant of S.A.I.L. ...First-party

AND

Their workmen. ...Second-party

APPEARANCES :

Shri K. N. Misra,
Dy. Chief Personnel Manager,
Steel Authority of India
Ltd., Durgapur Steel Plant,
Bolani Ores Mines. ..For the first-party

Shri Kshetra Mohan Mohanta ..Second-party

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour, in exercise of the powers conferred by Section 7-A, and Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication as per their Order No. L-26012(1)/83-D.III-(B) dated 6-12-1983 :

"Whether the action of the management of Bolani Ore Mines of Durgapur Steel Plant of SAIL, Bolani in dismissing Shri Kahetra Mohan Mohanta, Typits-cum-Clerk, Stores & Purchase Department, with effect from 8th October, 1982 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. On the date of first hearing, i.e., 3-3-1984, both the parties filed a petition along with a Memorandum of Settlement praying to pass an Award in terms of the settlement. They admitted the terms of the settlement and stated that they had entered into the settlement amicably without any coercion or duress. The settlement appears to be fair. Hence I pass this Award in terms of the settlement, and the Memorandum of Settlement 3-3-198 do form part of the Award.

J. M. MAHAPATRA, Presiding Officer.

[No. L-26012/1/83-D.III(6)]

Memorandum of Settlement under Form-H (Rule-58) of Industrial Dispute Act between the Management of Steel Authority of India Ltd., Durgapur Steel Plant, Bolani Ores Mines and their workman Shri Kshetra Mohan Mohanta, represented by Barbil Workers' Union.

PARTIES PRESENT :

On behalf of the Employer

1. Shri K. N. Misra,
Dy. Chief Personnel Manager,
SAIL, Durgapur Steel Plant,
Bolani Ores Mines, Bolani.

On behalf of the Workmen

1. Shri Kshetra Mohan Mohanta, Concerned Workman.

SHORT RECITAL OF THE CASE

Shri Kshetra Mohan Mohanta was dismissed from his services with effect from 8-10-1982 vide Order No. B4/B-4388 dated 7-10-1982 for misconduct under Company's Standing Orders.

Asst. Secretary, Barbil Workers' Union raised a dispute before the Asst. Labour Commissioner (Central), Rourkela for conciliation. On failure of conciliation, the dispute was referred before the Central Industrial Tribunal, Bhubaneswar for adjudication. For the interest of industrial harmony and to avoid litigation, both the parties agreed on the following terms.

TERMS OF AGREEMENT

1. Management agreed to reinstate Shri Kahetra Mohan Mohanta in the services of the Company.

2. Shri Kshetra Mohan Mohanta will be allowed to resume his duties in the same pay, scale and designation after acceptance of the joint petition by the Tribunal.

3. The period of absence from 8-10-1982 till the date of joining will be regularised by granting leave as admissible to him as per leave Rules of the Company and the services will be treated as continuous. He will not get any back wages for the above period other than the leave salary as may be admissible to him.

4. Both the parties agree to approach to the Hon'ble Industrial Tribunal, Bhubaneswar to pass a 'no dispute award in terms of the agreement.

(K. N. Misra) 3-3-84

(Kashetra Mohan Mohanta)

Made part of the Award.

Sd/- J. M. Mohapatra.

15-3-84

Presiding Officer
Industrial Tribunal
Bhubaneswar.

Witness .

Sd/- Illegible

Operator MEA
Bolani Ores Mines.

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का०आ० 1181—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि० के राउरकेला स्टील प्लांट की पूरनापानी चूना पत्थर और डोलोमाइट खदान, पूरनापानी में ठेकेदार सुन्दरगढ़ माइनिंग लेबर कन्ट्रेक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि० के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे० एम० मोहपात्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या स्टील अथोरिटी आफ इंडिया लि० के राउरकेला स्टील प्लांट की पूरनापानी चूना-पत्थर और डोलामाइट खदान, पूरनापानी ठेकेदार सुन्दरगढ़, माइनिंग लेबर कन्ट्रैक्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लि० के प्रबन्धतंत्र द्वारा 25-7-83 से 755 कर्मकारों की छंटनी करना तथा उनको 25-3-83 से 7-8-83 तक की अवधि की सेवा में कांटिन्यूटी की स्वीकृति न देना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-29011/86/83-डी-3 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 1181.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the mangement of Sundargarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Contractor, in Purnapani Limestone & Dolomite Quarry of Rourkela Steel Plant of SAIL, Purnapani and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desireable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mohapatra shall be the Presiding Officer, with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the retrenchment of 755 workers by the management of Sundergarh Mining Labour Contract Co-operative Society Ltd., Contractor, Purnapani Limestone & Dolomite Quarry of Rourkela Steel Plant of SAIL, Purnapani with effect from 25-7-83 and non-grant of continuity of service to them for the period from 25-3-83 to 7-8-83 is justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

[No. L-29011/86/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

का० आ० 1182.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०, रामागुण्डम डिवीजन-2, डाकघर गोदावरी खानी, जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री एम. श्रीनिवास राव होंगे, जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या मैसर्स सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, रामागुण्डम डिवीजन-2, डाकघर गोदावरी खानी, जिला करीमनगर (आन्ध्र प्रदेश) के प्रबन्धतंत्र द्वारा जी. डी. के 5 इन्क्लाइन के शाटफायरर-एवं-माइनिंग सरदार, सर्व श्री आर. वेंकाटी, के. सैलु और चौधरी रामू को पहली फरवरी, 1982 से उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप पहली मार्च, 1982 से एक से अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने को इन्कार करना न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-22012/77/83-डी-3 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 1st March, 1984

S.O. 1182.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Management of M/s. Singareni Collieries Co., Ltd., Ramagundam Division II, P.O. Godavarikhani, Distt., Karimnagar (A.P.) and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri M. Srinivasa Rao shall be the Presiding Officer, with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the mangement of Messrs Singareni Collieries Co. Ltd., Ramagundam Division II, Post Office Godavarikhani, Distt. Karimnagar (A.P.) are justified in denying one additional increment to S/Shri R. Venkaty, K. Sailu and Ch. Ramulu, Shortfirers-cum-Mining Sirdars of GDK 5 Incline with effect from the 1st March, 1982 consequent on their promotion from the 1st February, 1982 ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?

[No. L-22012/77/83-D.III(B)]

आदेश

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1984

का० आ० 1183.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, मेहसाना, के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण

गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जी० एस० बरोत होंगे, जिनका मुख्यालय अहमदाबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, मेहसाना के परियोजना प्रबन्धक की सितम्बर, 1982 के अपने कार्यालय आदेश द्वारा फायर-मैन ग्रेड-3 सर्व श्री जादूराम पाण्डे, सर बीरसिंह, पी० सी० शर्मा, महेश कुमार, सत्यनारायण शर्मा वी० सी० मोरे और एम० सी० गौड़ के मूल वेतन में कमी करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[सं० एल-30011/6/83-डी-3(बी)]

नन्द लाल, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 2nd March, 1984

S.O. 1183.—Whereas the Central Government is of opinon that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Oil and Natural Gas Commission, Mehsana and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now therefore in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri G. S. Barot shall be Presiding Officer, with headquarters at Ahmedabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the Project Manager, Oil & Natural Gas Commission, Mehsana in reducing the initial pay of S/Shri Jaduram Pandya, Sarbir Singh, P. C. Sharma, Mahesh Kumar, Satyanarayan Sharma, V. C. More and S. C. Gaur, Firemen Grade III, vide his Office Order of September, 1982 was legal and justified ? If not, to what relief are the workmen concerned entitled ?"

[No. L-30011/6/83-D.III(B)]

NAND LAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 8 मार्च, 1984

का०आ० 1184—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में बोलानी ओर माइंस आफ दुर्गापुर स्टील प्लांट आफ मैसर्स स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि० के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजिकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायानिर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7क और धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री जे० एम० मोहपात्रा होंगे, जिनका मुख्यालय भुवनेश्वर में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायानिर्णयन के लिये निर्देशित करती है ।

अनुसूची

"क्या मैसर्स स्टील आथारिटी आफ इंडिया लि०, दुर्गापुर स्टील प्लांट की बोलानी ओर माइंस के प्रबंधतंत्र की सुरक्षा संरक्षक, श्री जुगल किशोर राय, को 8 अक्तूबर, 1982 से सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो यह कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

[सं० एल-29011/9/83-डी-3 बी/डी-3 (ए)]

ए० वी० एस० शर्मा, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 28th March, 1984

S.O. 1184.—Whereas the Central Government is of the opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bolani Ore Mines of Durgapur Steel Plant of Messrs Steel Authority of India Limited and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri J. M. Mohapatra shall be the Presiding Officer with headquarters at Bhubaneswar and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Bolani Ore Mines of Durgapur Steel Plant of Messrs Steel Authority of India Limited in dismissing from service Shri Jugal Kishor Roy, Security Guard with effect from the 8th October, 1982, is justified ? If not, to what relief is this workman entitled?"

[No. L-29011(9)/83-D.III.B/D.III(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer.

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1984

का०आ० 1185—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में तुतीकोरीन पत्तन न्यास, तुतीकोरीन के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन के लिये निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० अरुणराज होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्याय-निर्णयन के लिये निर्देशित करती हैं ।

अनुसूची

"क्या तुतीकोरीन पत्तन न्यास प्रजातांत्रिक कर्मचारी संघ, तुतीकोरीन का तुतीकोरीन पत्तन के कर्मचारी, सर्व श्री वी० एस० डिचेंडी, वी सुब्बईया, एस० गोपालपिल्लई, एम० संकरालिंगम पिल्लाई और एम० एमेन्थल को पेंशन लाभ देने की मांग करना न्यायोचित है ? यदि न्यायोचित है, तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

[संख्या एल-44011/9/83-डी-4 (ए)]

एम० एम० पराशर, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 28th February, 1984

S.O. 1185.—Where the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Tuticorin Port Trust, Tuticorin and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said idspute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrail Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Arulraj shall be the Presiding Officer with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Is Tuticorin Port Trust Democratic Staff Union Tuticorin, justified in demanding pensionary benefits to S/Shri V. S. Ditchaudy, V. Subbiah, S. Gopalpillai, S. Sankaralingam Pillai and M. Emmanuel, employees of Tuticorin Port if justified to what relief the workmen are entitled?"

[No. L-44011/9/83-D.IV(A)]

S. S. PRASHER, Desk Officer

नई दिल्ली 20 मार्च, 1984

का० आ० 1186.—तमिलनाडु राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री गंगाधर जस के स्थान पर श्री एस० नरसिंहन, आयुक्त-व-सचिव, श्रम तथा रोजगार विभाग को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है; अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, "[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 24 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री एस० नरसिंहन,
आयुक्त, तथा सचिव, तमिलनाडु सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग, मद्रास,
(तमिलनाडु)"

[संख्या यू-16012/3/84-एच आई०]

New Delhi, the 20th March, 1984

S.O. 1186.—Whereas the State Government of Tamil Nadu has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri S. Narasimahan, Commissioner & Secretary, Labour & Employment Department to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation in place of Shri Gangadhar Jas;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4]", for the entry against Serial Number 24, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri S. Narasimhan,
Commissioner & Secretary to the Government of Tamil Nadu,
Labour & Employment Dept,
MADRAS."

[No. U-16012/3/84-H.I]

नई दिल्ली, 21 मार्च, 1984

का० आ० 1187.—कर्नाटक राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री एम० चित्तरंजन दास के स्थान पर श्री फिलिपोस मथाई, सचिव, कर्नाटक सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850 (अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, "[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मद 15 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात् :—

"श्री फिलिपोस मथाई,
सचिव, कर्नाटक सरकार,
समाज कल्याण तथा श्रम विभाग,
बंगलौर।"

[संख्या यू-16012/8/83-एच० आई०]

New Delhi, the 21st March, 1984

S.O. 1187.—Whereas the State Government of Karnataka has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), nominated Shri Philipose Mathai, Secretary to the Govt. of Karnataka to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri M. Chittaranjan Das;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "[Nominated by the State Governments under clause (d) of section 4]", for the entry against Serial Number 15, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Philipose Mathai,
Secretary to the Govt. of Karnataka,
Social Welfare & Labour Department,
Bangalore."

[No. U-16012/8/83-H.I.]

का० आ० 1188.—हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के खण्ड (घ) के अनुसरण में श्री आर० के० आनन्द के स्थान पर श्री हर्ष गुप्ता, आयुक्त-व-सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उस राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामनिर्दिष्ट किया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 के अनुसरण में, भारत सरकार के श्रम

मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 850(अ), दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "[राज्य सरकारों द्वारा धारा 4 के खण्ड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]" शीर्षक के नीचे मदसं 13 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायेगी, अर्थात्:—

"श्री हर्ष गुप्ता,
आयुक्त-व-सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार,
श्रम और रोजगार, विभाग
शिमला।"

[संख्या यू-16012/13/82-एच० आई०]

S.O. 1188.—Whereas the State Government of Himachal Pradesh has, in pursuance of clause (d) of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nominated Shri Harsh Gupta, Commissioner-cum-Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh to represent that State on the Employees' State Insurance Corporation, in place of Shri R. K. Anand;

Now, therefore, in pursuance of section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. 850(E), dated the 21st October, 1980, namely :—

In the said notification, under the heading "(Nominated by the State Governments under clause (d) of section (4)", for the entry against Serial Number 13, the following entry shall be substituted, namely :—

"Shri Harsh Gupta,
Commissioner-cum-Secretary to the
Govt. of Himachal Pradesh,
Labour & Employment Department,
Simla."

[No. U-16012/13/82-H.I.]

नई दिल्ली, 24 मार्च 1984

शुद्धि पत्र

का० आ० 1189.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा (4) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का० प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 735 तारीख 17 दिसम्बर, 1982 द्वारा मैसर्स टेलकम फैक्टरी, अलीपुर 248, ए० जे० बोस रोड, कलकत्ता (डब्ल्यू बी 1769) को उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन दी गई छूट को तुरन्त रद्द करती है।

[फा० सं० एस० 35014 (356)/82-पी एफ II]

New Delhi, the 24th March, 1984

CORRIGENDUM

S.O. 1189.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (4) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby cancels with immediate effect the exemption under sub-section (2A) of section 17 of the said Act granted to M/s. Telecom Factory, Alipore, 248, A.J. Bose Road, Calcutta (WB/1769) by the Notification of the Government of India in the late Ministry of Labour S.O. No. 735 dated 17 December, 1982.

[F. No S-35014(356)/82-PF.II]

शुद्धि पत्र

का० आ० 1190.—भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), 30 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 1959 और 1960 पर प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2006 तारीख 14 अप्रैल, 1983 में—

(i) पंक्ति 6 में "(2क)" के स्थान पर "(3 ख)" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 9 में "कर्मचारी" के स्थान पर "नियमित कर्मचारी" पढ़ें।

(iii) पंक्ति 17 में "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें।

(iv) पंक्ति 19 में "उक्त स्थापन" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों" पढ़ें।

[सं० एस-35014/62/83-ध० नि० 2]

CORRIGENDUM

S.O. 1190.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. SO. 2006, dated 14th April, 1983 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 30th April, 1983 at page 1960—

(i) in line 4, for "(2A)" read "2B)',.

(ii) in line 8 for "employees" read 'regular employees'.

(iii) in line 17, for "(2A)" read "(2B)'.

(iv) in lines 19 and 20 for 'said estabilsbment' read 'regular employees of the said estabilshment'.

[No. S-35014/62/83-PF III]

शुद्धि पत्र

का० आ० 1191.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 1958 पर प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2005 तारीख 14 अप्रैल, 1983 में—

(i) पंक्ति 6 में "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 9 में "कर्मचारी" के स्थान पर "नियमित कर्मचारी" पढ़ें।

(iii) पंक्ति 17 में "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें।

(iv) पंक्ति 19 में "उक्त स्थापन" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों" पढ़ें।

[सं० एस-35014/63/83- ध० नि० 2]

CORRIGENDUM

S.O. 1191.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation S.O. No. 2005 dated 14th April, 1983 published in the Gazette of India, Part II Section 3 Sub-section (ii) dated the 30th April, 1983 at page 1959—

(i) in line 4, for "(2A)" read "(2B)".

(ii) in line 8 for "'employees" read 'regular employees'.

(iii) in line 17, for "(2A)" read "(2B)".

(iv) in lines 19 and 20 for 'said estabilshment' read 'regular employees of the said establishment'.

[No. S-35014/63/83-PF.II]

शुद्धि पत्र

का० आ० 1192.—भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 30 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 1956 और 1957 पर प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2004 तारीख 14 अप्रैल, 1983 में—

(i) पंक्ति 6 में, "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें।

(ii) पंक्ति 9 में, "कर्मचारी के स्थान पर "नियमित कर्मचारी" पढ़ें।

(iii) पंक्ति 17 में, "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें ।

(iv) पंक्ति 19 में "उक्त स्थापन की" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों की" पढ़ें ।

[सं० एस०-35014/64/83-भ०नि० 2]

CORRIGENDUM

S.O. 1192.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation No. S.O. 2004 dated 14th April, 1983 published in the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (ii) dated the 30th April, 1983 at page 1957—

(i) in line 4, for "(2A)" read "(2B)".

(ii) in line 9 for "employees" read 'regular employees'.

(iii) in line 17, for "(2A)" read "(2B)".

(iv) in lines 19 and 20 for 'said establishment' read the regular employees of the said establishment'.

[No. S-35014/64/83-PF.II]

शुद्धिपत्र

का०आ० 1193—भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) तारीख 30 अप्रैल, 1983 के पृष्ठ 1969 और 1970 पर प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 2012 तारीख 14 अप्रैल, 1983 में—

(i) पंक्ति 6 में, "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें ।

(ii) पंक्ति 9 में, "कर्मचारी के स्थान पर "नियमित कर्मचारी पढ़ें"।

(iii) पंक्ति 17 में, "(2क)" के स्थान पर "(2ख)" पढ़ें ।

(iv) पंक्ति 19 में, "उक्त स्थापन" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों" पढ़ें ।

[सं० एस-35014/65/83-भ० नि० 2]

CORRIGENDUM

S.O. 1193.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Rehabilitation S.O. No. 2012 dated 14th April, 1983 published in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 20th April, 1983 at page 1970—

(i) in line 4, for "(2A)" read "(2B)".

(ii) in line 8 for "employees" read 'regular employees'.

(iii) in line 17, for "(2A)' read "(2B)".

(iv) in line 19, for 'said establishment' read 'regular employees of the said estabilshment'.

[No. S-35014/65/83-PF.II]

शुद्धिपत्र

का० आ० 1194—भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 15 जनवरी, 1983 में पृष्ठ 413-414 पर प्रकाशित, भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 409, तारीख 10 दिसम्बर, 1982 में,

(i) पांचवीं पंक्ति में "2क" के स्थान पर "2ख" पढ़ें ।

(ii) सातवीं पंक्ति में "उक्त स्थापन के कर्मचारी" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारी" पढ़ें ।

(iii) पंद्रहवीं पंक्ति में "2क" के स्थान पर "2ख" पढ़ें ।

(iv) सोलहवीं पंक्ति में "उक्त स्थापन" के स्थान पर "उक्त स्थापन के नियमित कर्मचारियों" पढ़ें ।

[संख्या एस-35014/423/82-भ० नि०-2]

CORRIGENDUM

S.O. 1194.—In the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 409 dated 10th December, 1982 pubilshed in the Gazette of India, Part II Section 3, Sub-section (ii) dated the 15th January, 1983 at page 414-415,—

(i) in line 4, for "(2A)" read "(2B)".

(ii) in line 8 for "employees of the said estabilshment" read "regular employees of the said estabilshment";

(iii) in line 17, for "(2A)" read "(2B)".

(iv) in lines 19 and 20 for "employees of the said establishment" read 'regular employees of the said estabilshment'

[No. S-35014/423/82-PF.II]

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1984

का० आ० 1195.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है, और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77,78,79, और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की चुकी है] के उपबंध मध्य प्रदेश राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्:—

"जिला देवास, तहसील देवास में औद्योगिक एस्टेट, ए०बी० रोड़, देवास तथा राजस्व ग्राम अमोना, बारखेड़ी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र ।"

[संख्या एस० 38013/4/84 एच० आई]

New Delhi, the 26th March, 1984

S.O. 1195.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI, [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Madhya Pradesh, namely :—

"The areas comprised within
Industrial Estate,
A.B. Road, Dewas and
revenue villages Amona,
Barakhedi in Tehsil Dewas,
District Dewas."

[No. S-38013/4/84-HI]

का०आ० 1196.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 अप्रैल, 1984 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय 4 (धारा 44 और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) और अध्याय 5 और 6 [धारा 76 की उपधारा (1) और धारा 77, 78, 79

और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"उत्तरी आरकोट जिले में वैल्लोर तालुक में अरियूर राजस्व ग्राम के अन्तर्गत आने वाले अरियूर क्षेत्र।"

[संख्या एस-38013/3/84 एच० आई०]

ए.०के० भट्टाचारी, अवर सचिव

S.O. 1196.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st April, 1984 as the date on which the provisions of Chapter IV (except sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapters V and VI [except sub-section (1) of section 76 and sections 77, 78 79 and 81 which have already been brought into forcel of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely :—

"The Ariyur area comprised within
the Revenue Village,
Ariyur in Vellore Taluk
in North Arcot District."

[No. S-38013/3/84-HI]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

का० आ० 1197.—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 33-ग की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 4650 तारीख 19 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन करती है ; अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुबद्ध तालिका में क्रमांक 2 और 2-क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"2 भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1698 तारीख 22 मई, 1965 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय बम्बई-1	बम्बई शहर तथा बम्बई उप शहर जिला	उद्योग केन्द्रीय रेलवे, एयर इंडिया, इंडियन एयर लाइनसेस, बैंक, बीमा और महाराष्ट्र राज्य में जिला थाना, जलगांव, जलना, धुलियां औरंगाबाद, अहमद नगर, भीर, नांडेड, प्रभानी तथा गोवा और दमन दीव संघ राज्य क्षेत्र में दमन और दीव ।
2 क भारत सरकार, श्रम, रोजगार और पुनर्वास रोजगार मंत्रालय (श्रम और रोजगार विभाग) की अधिसूचना सं० 1970 तारीख 28 मई 1968 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय सं०-2 बम्बई	जिला बम्बई शहर तथा जिला बम्बई उप शहर	उद्योग पश्चिम रेलवे पत्तन और गोदियां, नौसैनिक गोदी-बाड़ा, रक्षा प्रतिष्ठान, डाक और तार, टेलीफोन, भारतीय खाद्य निगम, भारत सरकार मिंट तथा सभी अन्य उद्योग, जो न्यायालय संख्या-7 को सौंपे गए हैं। और महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग, कोल्हापुर, संगाली, सतारा शोलापुर, उस्मानाबाद, नासिक, लटूर, रायगढ़, पुणे जिले और गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में गोवा ।"

टिप्पणी :— भारत के राजपत्र के तारीख 30-12-1976 के भाग दो, खण्ड 3, उपखंड (II) में अधिसूचना सं० 4650 तारीख 19-12-1967 द्वारा प्रकाशित मुख्य अधिसूचना में तदनंतर निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया :—

(1) अधिसूचना सं० का० आ० 1175 तारीख 20-3-1968, 30-3-1968 का राजपत्र ।

(2) अधिसूचना सं० का० आ० 668 तारीख 11-2-1969, 22-2-1969 का राजपत्र ।

(3) अधिसूचना संख्या का० आ० 1894 तारीख 9-5-1969, 17-5-1969 का राजपत्र ।

(4) अधिसूचना संख्या का० आ० 1768 तारीख 30-4-1969, 10-5-1969 का राजपत्र ।

(5) अधिसूचना सं० का० आ० 2796 तारीख 3-7-1971 24-7-1971 का राजपत्र ।

(6) अधिसूचना सं० का० आ० 3810 तारीख 23-9-1972, 4-11-1972 का राजपत्र ।

(7) अधिसूचना सं० का० आ० 4521 तारीख 26-9-1975, 18-10-1980 का राजपत्र ।

(8) अधिसूचना सं० का० आर० 2914 तारीख 13-10-1980, 25-10-1980 का राजपत्र ।

(9) अधिसूचना सं० का० आ० 45 तारीख 19-12-1981, 2-1-1982 का राजपत्र ।

(10) अधिसूचना सं० का० आ० 1633 तारीख 16-4-1982, 1-5-1982 का राजपत्र ।

(11) अधिसूचना सं० का० आ० 4014 तारीख 22-11-1982, 4-12-1982 का राजपत्र ।

(12) अधिसूचना सं० का० आ० 4207 तारीख 7-11-1983, 19-11-1983 का राजपत्र ।

[सं० एम० 11020/3/83-डी०-I (ए)]

एस० एच० एस० अय्यर, अवर सचिव

New Delhi, the 27th March, 1984

S.O. 1197.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 33C of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of

India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Department of labour and Employment) No. S.O. 4650, dated the 19th December, 1967, namely:—

In the Table annexed to the said notification, for serial No. 2 and 2A and the entries relating thereto, the following serial No. and entries shall be substituted, namely:—

"2.	Labour Court, Bombay constituted under Section 7 of the said Act, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. S.O. 1698, dated the 22nd May, 1965.	Industries from the Bombay City District and the Bombay Sub-urban District:—Central Railway, Air-India, Indian Airlines, Banks, Insurance. And the districts of Thane, Jalgaon, Jalna Dhaulia, Aurangabad, Ahmednagar, Bhir, Nanded, Parbhani in the State of Maharashtra and Daman and Diu in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.
2A.	Labour Court No. 2, Bombay constituted under Section 7 of the said Act, by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitaton. (Department of Labour and Employment No. S.O. 1970, dated the 28th May, 1968).	Industries from the Bombay City District and the Bombay Sub-urban District: Western Railway, Ports and Docks, Naval Dockyards, Defence Establishments, Post and Telegraph, Telephones, Food Corporation of India, Government of India Mint and all other Indsutries not assigned to Court No. 1. And the district of Ratnagiri, Sindhudurg, Kolhapur, Sangli, Satara, Sholapur, Osmanabad, Nasik, Latur, Raigad, Pune in the State of Maharashtra and Goa in the Union Territory of Goa, Daman and Diu."

Note:—Principal Notification published vide S.O. 4650 dated 19-12-67, Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gzazette of India dated 30-12-1967 subsequently amended by:—

(i) Notification No. S.O. 1175, dated 20-3-68, Gazette of 30-3-68.

(ii) Notification No. S.O. 668, dated 11-2-69, Gazette of 22-2-69.

(iii) Notification No. S.O. 1894, dated 9-5-69, Gazette of 17-5-69.

(iv) Notification No. S.O. 1768, dated 30-4-69, Gazette of 10-5-69.

(v) Notification No. S.O. 2796, dated 3-7-71, Gazette of 24-7-71.

(vi) Notification No. S.O. 3810, dated 23-9-72, Gazette of 4-11-72.

(vii) Notification No. S.O. 4521, dated 26-9-75, Gazette of 18-10-80.

(viii) Notification No. S.O. 2914, dated 13-10-80, Gazett of 25-10-80.

(ix) Notification No. S.O. 45, dated 19-12-81, Gazett of 2-1-82.

(x) Notification No. S.O. 1633, dated 16-4-82, Gazette of 1-5-82.

(xi) Notification No. S.O. 4014, dated 22-11-82, Gazette of 4-12-82.

(xii) Notification No. S.O. 4207, dated 7-11-83, Gazette of 19-11-83.

[No. S 110 0/3/33-D.I(A)]

S.H.S. IYER, Under Secy.

New Delhi, the 27th March, 1984

S.O. 1198.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank Note Press Dewas and their workmen, which was received by the Central Government at the 15th March, 1984.

BEFORE JUSTICE SHRI K. K. DUBE, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(1)/1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bank Note Press, Dewas and their workmen represented through the Bank Note Press Karamchari Sangh, 41 Radhaganj, Dewas (M.P.).

APPEARANCES :

For Workman—Shri S. K. Rao, Advocate.

For Management—Shri A. P. Tare, Advocate.

INDUSTRY : Bank Note Press DISTRICT : Dewas (M.P.)

AWARD

Dated March 9, 1984

In exercise of its powers under Sec. 10 of the Industrial Disputes Act 1947 the Central Government referred the following dispute to this Tribunal, for adjudication, vide Notification No. L-42012/49/80-D.II(B) Dated 6th January, 1981:—

"Whether the action of the management of Bank Note Press, Dewas in superseding Shri J. S. Nair, Senior Operator by his juniors for the post of Senior Operator and Junior Supervisor is legal and justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled and with effect from what date ?"

2. The dispute essentially concerned supersession of Shri J. S. Nair, Senior Operator, in the services of the Bank Note Press, Dewas, Shri S. K. Rao, learned Counsel appearing for the workman, has moved this Tribunal praying that they do not want to contest the dispute as the Bank Note Press has already promoted the workman. In the opinion of the workman the dispute has completely lapsed. They also do not want to press for the costs.

3. Having regard to the fact that the Bank Note Press has already promoted Shri J. S. Nair no dispute exists now between the workman and the management of the Bank Note Press. The reference has accordingly become infructuous. This award is, therefore, rendered in the following terms:—

The Bank Note Press, Dewas, having promoted Shri J. S. Nair, Senior Operator, the dispute referred to this Tribunal comes to an end. Since there has been a promotion of

Shri Nair the dispute stands settled. There shall be no order as to costs.

K. K. DUBE, Presiding Officer.

[No. L-42012(49)/80-D.II(B)]

S.O. 1199.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board and their workmen which was received by the Central Government on the 9th March, 1984.

BEFORE SHRI I. P. VASISHTH, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBUNAL CHANDIGARH.

Case No. I.D. 68|83 CHD 155|81 (DELHI)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhakra Beas Management Board, Nangal Township-Punjab.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

For the Employers:—Shri R. L. Kaith.

For the Workmen:—Shri R. K. Singh.

Bhakra Beas Management Board STATE—Punjab.

AWARD

Dated the 3rd of March, 1984

The Central Government, Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1) (d) of the Industrial Disputes Act 1947, hereinafter referred to as the Act, vide their Order No. L-42011(4)|81-D.II.B. dated the 3rd of November, 1981 read with S.O. No. S-11025(2)|83 dated the 8th June, 1983 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Bhakra Beas Management Board, Chandigarh in not protecting the wages of 13 Machine Tool Operators, Annexure 'A' on their re-employment in 1972 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?"

ANNEXURE—A

List of 13 Machine Tool Operators.

Sr. No. Name of the Workman.

1. Shri Ram Nath
2. Shri Kishan Chand
3. Shri Bhagat Ram
4. Shri Mangat Ram
5. Shri Gurdas Ram
6. Shri Didar Singh
7. Shri Sarwan Singh
8. Shri Ram Asra
9. Shri Karam Singh
10. Shri Ram Milan
11. Shri Dilbag Rai
12. Shri Ram Singh
13. Shri Amar Singh

2. Unfortunately the Claim Statement does not give a clear insight in the anatomy of the dispute but all the same one could gather from the pleadings and the evidence brought on records that the bone of contention revolves around the management's refusal to protect the previous wages of the petitioner/workmen at the time of their re-employment. To be precise, all the petitioners were employed under the same Management for quite sometime as M.T.Os. when all of them, along with a few others, were retrenched some time between February to October, 1968. All the connected benefits, which normally go with retrenchment, were also given to them.

3. It was propounded by the petitioners that in the year 1972 they were re-employed as M.T.Os. and fixed at the starting salary of Rs. 110 in the revised scale of Rs. 110-180 in spite of the fact that some of their colleagues who had been similarly retrenched and re-employed by the management, were given the benefit of their previous service and fixed at a higher level on the protection of last drawn pay.

4. It was also revealed that a number of Organisations including the Punjab Government and the managements of the BSL and Anandpur Hydel Project were protecting the last drawn pay of all such re-employed staff but their objections and entreaties for a similar treatment on the principle of equity and fair play failed to evoke any constructive response from the respondent|management.

5. Thus forced by the circumstances, the petitioner/workmen raised an Industrial dispute which could not be settled in the Conciliation proceeding despite the intervention of the ALC(c) and hence the reference.

6. Contesting the proceedings on all counts, the management denied that there was any occasion for the Appropriate Government, to make a reference to the Tribunal because there was neither any dispute nor any apprehension thereof between the parties. Elaborating their cause, the management averred that the petitioner-workmen were given re-employment by virtue of Section 25-H of the Act and fixed at the initial stage of Rs. 110 in the revised scale of Rs. 110-180 without any protest from their side who rather kept on enjoying the arrangement for a period of almost 8 years without any murmur. The management pleaded that they had given the protection of last drawn pay in case of some other employees purely on the merits of each and every case and, otherwise too, the petitioners could not claim any extra incentives because their re-employment was on fresh basis which was consciously and voluntarily accepted by them.

7. The parties were taken to trial on the following issues framed over and above the terms of reference.

(1) Whether the reference is legally void, infirm or incompetent as alleged? OR

(2) Whether the petitioner-workmen are estopped by their act and conduct? OR

8. In support of their respective versions the parties adduced verbal as well as documentary evidence which I have carefully persued and heard them at length. My issuewise discussion and findings are as under :—

Issue No. 1

9. There could not, perhaps, be a more illusory objection to the validity and the competence of the reference than the management's contention that there was no pending or apprehended dispute between the parties. From the history of the case detailed above, it should be abundantly clear that there was a triable dispute in the petitioners' effort to seek parity with some of their co-workers in the matter of fixation of pay and, as such, the Appropriate Govt. was fully justified in seeking judicial adjudication. I, accordingly, answer the issue against the management.

Issue No. 2

10. The management's trump card in propounding the theory of estoppal was based on petitioners' acceptance of

re-employment at the initial pay of Rs. 110 in the scale of Rs. 110-180 without raising any objection. But they appear to have lost sight of the fact that the cause of action accured to the petitioners as and when they came to know that some of their co-workers had been fixed up in the said scale on protecting their pay drawn at the time of retrenchment. It was at that stage, that they raised out on the technicalities of estoppal. In other words be evident from the letters Exts. W26 & 27. It may also be worthwhile to note that it was not even suggested to any of the workmen-petitioners in their cross-examination that they were aware of the concession given to their co-workers at the time of their own re-employment.

11. In my considered opinion unless a party is fully conscious of a fact and voluntarily surrenders or forgoes the consequential benefit arising therefrom, it cannot be knocked out on the technicalities of estoppel. In other words the act of giving up of the right must not only be voluntary but also a conscious one. It is besides the point that at the particular time of their re-employment the petitioners were placed in a precarious position since the refusal to accept the job was fought with the risk of unemployment and consequent starvation. I, thus, return the issue against the management.

Issue of Reference :

12. That directly confronts the Tribunal with the real contest between the parties as to how far the management was justified in denying the protection of previous pay to the petitioners? The petitioners led two-fold evidence in their attempt to discredit the action of the management. One set of evidence related to the existence of a common pattern in a number of similarly placed Organisations like Punjab Government Beas Project, BSL Project and Anandpur Hydel Project. But it was rightly urged on behalf of the management that I need not strain myself on such type of arrangement prevailing in others Organisations because it can not have any binding effect on the parties to our reference for the simple reason that was no express or implied understanding between them to follow any of those Organisations in such matters.

13. However, the second set of evidence is quite relevant and appears to have a direct bearing on our case. Leaving aside the secular testimony of the petitioners, which, in the very nature of things, may be tainted and self serving, we have a number of documents to settle the issue. Letter Ex. W-18 shows that at one stage the benefit was declined to one Kishan Singh Work mistry but was then given to him under the direction of the Member Irrigation BBMB in the year 1972; Letter Ex. W19 reveals the grant of the benefit to a set of 8 workmen in October, 1973 whereas the letter Ex. W20 confirms the release of such facility in favour of another set of 5 workmen. The assertion of WW1 Ran Singh stands unrebutted that none of the retrenched employees, who were re-employed, was subjected to any Trade Test. It was thus, contended that the Management acted discriminately in depriving the petitioners of the protection of their last drawn pay.

14. On behalf of the management it was submitted that there was no understanding or agreement between the parties to protect their previous pays that in the above said instance the facility was accorded in the light of certain guidelines originating in individual's merit and that was how that the case of Kishan Chand was taken up separately whereas in the matter of Shri Sita Ram and seven others (Ex. W19) and Ran Singh and four others (Ex. W20), it was specifically recorded that it would not form any precedent. I was then referred to the case of the Workmen of PSEB Vs. Haryana State Electricity Board 1981 Lab. I.I.C. 1586 for the legal proposition that there was no obligation on the management to protect the previous pay of the retrenched employees at the time of their re-employment.

15. I am afraid, the learned representative of the management appears to have lost sight of the distinct nature of the facts of the judicial pronouncement cited by him. In that case an entire Organisation was transferred to Employer 'H' without his undertaking to retain, recruit or re-employ the workmen of the former. It was, therefore, held that the Transferee was not bound to pay the same wages as paid by the Transferor. But in our case the Employer was the same very person.

16. However, in so far as the contention that each and every case was individually taken up on merits for according the benefit is concerned, it may not perhaps be faulted because all the aforesaid employees were also initially fixed at the starting point of the scale just like the petitioners but then they made certain representations on different occasion which were examined and decided on the individual's merits. Of course they might not have been subjected to any Trade Test but then none of them was employed as MTO in the category of the petitioners as should be evident from the relevant orders Ex. W18, W19 and W20. In other words it may be said that they belonged to a different category. It was vehemently urged before me, and I think with considerable logic, that when a retrenched employee is given re-employment even in his earlier Trade it is primarily his previous service record, rather than a new Trade Test, which is crucial for offering the particular terms and conditions of employment. So to that extent the discrimination could be assumed to be reasonable.

17. But beyond it the management stands on a slipery ground in turning a completely deaf ear to the petitioner's demand. A bare reading of letter No. 5259-69|BBMB|1713|46/Sup. dated 13-5-1976 from the Secretary to their Irrigation Member (Ex. W22) would leave no manner of doubt that a number of workmen placed like the petitioners were agitating the point for quite some time, and that there was a sort of labour unrest in view of the seeming disparity in the matter of pay fixation; obviously because they were neither apprised of the criterian nor could possibly know about their service record—since the procedure of Trade Test was not adopted by the management. It was against such back drop that they (management) took a one time decision to bring in the Industrial peace by evolving a Uniform—Policy of allowing one increment in the new scale for two completed years of past service subject to a maximum of 5 increments, to all the retrenched workman at the time of their re-employment. But unfortunately this policy benefit was not given to the petitioner Workmen and there is no explanation for it.

18. I, accordingly hold that the respondent|management was bound to honour its own policy commitment as envisaged in the above quoted letter Ex. W22 even though it may not have any legal obligation to protect the petitioner's pre-retrenchment wages. Thus, the issue is answered partly in favour of the parties.

Relief :

19. To sum up my aforesaid discussion on the various aspects of the matter and the points raised before me, I reutrn my Award in favour of the Workmen with a direction to the management to fix their salary in accordance to the policy decision laid down in the above quoted letter No. 5259-69|BBMB|1813|46|Sup. dated 13-5-1976 (Ex. W22).

20. Before parting with the reference I may like to record that according to the common case of the parties one of the workman Shri Ram Milan died sometime in July-Aug. 1980, whereas another workman named Kishore Chand retired on 30th of June, 1982 on reaching the age of superanuation; therefore, for the obvious reasons, the benefit would be accorded to them for the particular period till they served the respondent|management, and in the case of Ram Milan, the arrears would be paid to his legal heirs.

I. P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-42011(4)|81-D.II(B)]

S.O. 1200.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Hyderabad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Cantonment Board, Secunderabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 15th March, 1984.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)

AT HYDERABAD

PRESENT :

Sri M. Srinivasa Rao, M.A.,LL.B., Industrial Tribunal.

Industrial Dispute No. 4 of 1984

BETWEEN

Workmen of Secunderabad Cantonment Board, Secunderabad.

AND

The Management of Secunderabad Cantonment Board, Secunderabad.

APPEARANCES :

Sri G. Bikshapathi and Sri N. Mohan Rao, Advocates—for the Workmen.

Sarvasri M. Panduranga Rao, C. Sreenivasa Baba, B. G. Ravinder Reddy and Govind Prakash, Advocates for the Management.

AWARD

The Government of India by its Letter No. L-13011(1)/78-D.II.B. dated 31-3-1981 referred a dispute between the Management of Cantonment Board, Secunderabad and its Workmen under Sections 7A and 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 to this Tribunal for adjudication. The dispute referred as per the Schedule is :

"1. Whether the action of the employer, Cantonment Board, Secunderabad in retrenching the following six workmen on the dates shown against each, is lawful and justified ? If not, to what relief are the workmen entitled ?

Sl. No.	Name	Designation	Date of Reinstatement
1.	Sri M.C. Parthasarthy	Engineer	28-10-76
2.	Sri M.A. Haneef	Draftsman	30-9-76
3.	Sri F. Thomas	Driver	28-10-76
4.	Sri G. Paish	Fireman	28-10-76
5.	Sri Anand Rao	Fireman	30-6-76
6.	Sri Nagabhushanam	Fireman	1-8-76

2. Whether the action of the employer, Cantonment Board, Secunderabad of not paying gratuity to S/Shri M. C.Parthasarthy, Engineer, M. A. Haneef, Draftsman, R. Thomas, Driver, G. Paish, Fireman, Anand Rao, Fireman, Nagabhushanam, Fireman is justified ? If not, to what relief the workmen concerned are entitled."

2. A claims statement is filed by the workmen represented by the President of their Union i.e., Secunderabad Cantonment Board Employees Union, with the following averments. M. C. Parthasarthi the first claimant in the reference was appointed on 6-10-1949 and had been discharging the duties satisfactorily. M. A. Haneef, the second claimant, was appointed in 1946 and was in continuous service till his retrenchment with effect from 30-9-1976. The post of Draftsman is essential. F. Thomas, the third claimant, was appointed in 1946 and was in continuous service till his retrenchment from 28-10-1976. Claimants 4, 6 and 6 the Firemen were appointed in 1946 and were in service till their retrenchment with effect from 28-10-1976, 30-9-76 and 1-8-1976 respectively.

3. The Cantonment Boards are the creations under the Cantonments Act 1924. The service conditions are governed by the Cantonment Fund Service Rules 1937 as amended from time to time. There were also awards rendered by the National Industrial Tribunal, Bombay and also settlements that govern the service conditions, Wage structure etc. The provisions of the Industrial Disputes Act are applicable in respect of the maters governing the service conditions and other benefits.

4. There is only one post of Engineer and one post of Draftsman and they are indispensible for proper functioning and maintenance of the Cantonment Board. The first petitioner-claimant was President of the Board Employees Union since 1967 and Petitioners 2 to 6 were his supporters. The Respondent Board bore grudge against them and waiting for an opportunity to do away with their service. While so the G.O.C. in Chief, Southern Command, Pune issued a Circular in May, 1975 and another circular dated 5-9-75. Taking advantage of those instructions, the Board prevailed upon the Head Quarters and got its approval to terminate the services of the Petitioners under Rule 8(1)(f) of Cantonment Fund Rules. The Board issued letters dated 30-6-1976 terminating the services of the Petitioners 1 to 5 with effect from 30-9-1976 and they were relieved infact on different dates. The Gratuity was not paid along with the termination notice but was paid long thereof. Petitioner No. 6 was working as Leading Fireman. His post was abolished under Special Board Resolution No. 1 dated 9-3-1976. The Board passed another resolution removing the Petitioner No. 6 from service under Rules 8(1)(c) and notice was issued for his removal from 1-8-1976. Subsequently, when the Union took up the matters with the Headquarters, the Board was informed that its action smacked of vindictiveness and deprived the individual of terminal benefits under Rule 8(1)(c). The Board after considering the advice of their Headquarters passed Resolution on 15-2-1977 treating it as discharge under Rule 8(1)(e) and that is irregular and unlawful and confirms the vindictive attitude of the Board.

5. The conditions precedent for retrenchment under Section 25F of the Industrial Disputes Act are not complied with. The termination of services is arbitrary and colourable exercise of powers, the termination orders were passed as a measure of punishment. The action amounts to victimisation and unfair labour practice for the Trade Union activities of the Petitioners. Rule 8(1)(e) is not applicable to the cases of these Petitioners and it is purely a mala fide action and reduction was not warranted. The rule of first come last go was not observed in discharging the petitioners. The post of Engineer abolished in 1976 was again restored in 1979 and Petitioner No. 1 ought to have been given the said post. The Board misunderstood the instructions of the Headquarters and committed irregularities in terminating the services as a measure of economy and public interest. Petitioners 1 to 5 remained un-employed and could not get alternative employment. The claimants finally pray that the termination orders may be set aside and Petitioners 1 to 5 may be directed to be reinstated with full back wages and their continuity of service and other attendant benefits and compensation may be granted in lieu of reinstatement to the widow of Petitioner No. 6.

6. In the counter file on behalf of the Cantonment Board it is stated that the dispute is not an industrial dispute and the Petitioners were engaged in the work of the Board which is in the nature of sovereign function of the State and not as an industry and therefore the reference itself is incompetent. That apart, the Petitioners are not workmen and particularly Petitioner 1 as Engineer was drawing salary of Rs. 1,364.00 per month and was doing mainly supervisory and managerial work and the second petitioner also was doing supervisory work and was drawing salary of Rs. 698.00 per month. The operation of the Industrial Disputes Act is excluded by necessary implication and the service condition of the employees are governed by the Catnonment Fund Servant Rules which are statutory in nature. The first Petitioner might be the President of the Cantonment Board Union but the Board is not aware whether Petitioner 2 to 6 are his supporters and in any case that has no relevance. The allegations that the Board bore grudge against the first Petitioner and his supporters and was waiting for an opportunity etc., are not correct. It is true that the G.O.C., Southern Command, Pune issued Circular to effect economy measures and abolish posts which are surplus. The reference to the policy of reviewing cases of persons that completed 55 years of service etc., by the claimants is irrelevant. The allegation that the Board passed resolution for abolition of 43 posts as a measure of victimisation is false. In view of the directions and also in the interest of economy of the Board, it decided to abolish certain posts but that was not by way of victimisation. The allegation that the Board prevailed upon the Head Quarters for terminating the services of the Petitioner is also incorrect. The Board is trying its best to see that the employees as far as possible are not retrenched even though certain posts were

abolished and the Board explored the possibilities of providing alternative appointments. Only when they could not offer such alternative employment, the services were terminated. The allegation that the gratuity was not paid is not correct. All the Petitioners were given three months notice and they were given retirement benefits. The allegation that the procedure for retrechment was not complied with is false. They were paid three months salary instead of one months salary required by Industrial Disputes Act. Further when posts are abolished Section 25(F) is not attracted. The Petitioners were given three months notice and also compensation. The termination of services is legal and bona fide, and they were not as a measure of punishment nor is it mala fide. It was as a measure of economy only. The posts of Engineer and the Draftsman at that point of time were found not necessary and they were therefore, abolished, and there were no mala fides in that. The dispute regarding the 6th Petitioner abates. The Petitioners have to prove that they got no alternaive employment. Finally it is submitted by the Board that the Petitioners are not entitled to any relief and the claim has to be dismissed.

7. In support of the claim of the workmen five witnesses in all are examined including petitioners 1 to 4 as W.Ws. 1, 2, 3 and 4 respectively one Salatha Bai is examined as W.W. 5 stating that she is the widow of 6th Petitioner Nagabhushanam. On behalf of the Cantonment Board one B. S. Ramchander Rao who is now working as Selection Grade Clerk is examined as M.W. 1 and G. Narsimha Rao the present Head Accountant of the Board is examined M.W. 2 Exs. W1 to W6 and Ex. M1 to M16 are the documents got marked by the parties in support of their respective versions.

8. The second issue in the reference relates to payment of gratuity. Admitedly the gratuity due to the claimants has been paid by the Cantonment Board and there is no claim to be adjudicated upon now with reference to this issue, The learned counsel for the workmen fairly submits that no relief is therefore required with reference to Issue No. 2.

9. The first issue refers to the discharge of the six claimants and the demand advanced on their behalf for their reinstatement or other consequential reliefs. Of the six claimants mentioned in the reference, claimant No. 6 is no more alive and in the claims statement itself it is mentioned that he passed away on 18-11-1976. W.W.5 Salatha Bai is examined as a widow of this sixth claimant but no legal heir certificate is produced and the Management's counsel states that the Management does not know about her and it is not established by the workmen that she is the widow and legal heir of the deceased claimant No. 6. When he died in 1976 itself, about five years prior to the reference of this dispute by the Central Government to this Tribunal, no attempts have been made either to bring the legal heirs of that deceased workman on record either as legal representative or as claimants to any benefits that might be payable to that workman. By the date of the reference that workman died and when no steps are taken for bringing the L.Rs. on record, the claim abates as far as this deceased claimant is concerned. This Tribunal cannot grant any relief to W.W. 6 recognising her as the legal heir or sole legal heir of this workman in the absence of any legal heir certificate produced by her. This is, apart from the merits of the claim.

10. The first claimant Sri M. C. Parthasarthy was an Engineer of the Board and in his evidence as W.W. 1, he states that on 13-6-1980 he attained the age of superannuation and completed 58 years and he would also not therefore be entitled to ask for reinstatement in any event .Therefore, he states in his evidence that he is now asking for arrears of salary from the date of his retrenchment to the date of superannuation and the consequential refixation of pension. The other three workmen in the reference are said to have not attained the age of superanuation and therefore the original relief mentioned in the claims statement is canvassed for them.

11. Before referring and considering the contentions of the parties, it is convenient to refer to the few undisputed aspects that are relevant in this case. The claimants in this dispute were the employees of the Cantonment Board. The cantonment boards are formed under the Cantonment Act of 1924 and the service conditions of employees are governed by the Cantonment Funds Servant Rules. The G.O.C. in Chief, Southern Command, Pune is the Headquarters for all the Cantonment Boards which have to follow the instructions issued by the Headquarters. As per Rule 8(1)(e) of the Cantonment Fund Servant Rules, the Board or the Officer appointing a servant may discharge him in pursuance of a reduction or revision of establishment and not otherwise. Sub-rule 2 of Rule 8 provides for three months notice or three months salary in lieu of that notice if any discharge is to be made under Rule 8(1)(c) before the servant attains the age of 58 years [Sub-clause (a), (b), (c) & (d) of Rule 8(1) refer to other forms of discharge but we are not concerned with them in this matter]. Though Sri M. A. Haneef the second claimant as W.W. 2 states that he was not issued any notice nor paid any retrenchment compensation at the time of retirement, the record shows that all these claimants were given three months notice before terminating their services. It is so urged in the counter. Ex. W2 resolution of the Board that met to discuss the telegram dated 29-10-1975 received from the Head Quarters, shows that three months notice were directed to be given to the incumbents of the abolished posts. Exs. W3, W4 and W5 are the notices issued accordingly to three of these workmen. In these notices it was conveyed that the Cantonment Board abolished the post under Rule 8(1)(e) and the addressee was holding that post and he was being given three months notice of discharge and he was informed that his services would not be required after the three months date mentioned therein. It is also mentioned therein that the addressee would be paid the compensatory gratuity admissible. In view of these notices that support the plea in the counter regarding the issuance of the notices and when W.W. 1 himself does not say that no notice was given to him before discharging him, it can be taken as an undisputed fact that three months notices before affecting discharge were given to these claimants as per the Catonment Fund Servant Rules as against one month's notice contemplated under the industrial dispute. The documents got marked by consent would further show that the Head Quarters at Pune issued instructions to observe strict economy in view of the financial stringency and suggested that the Boards might not justifiably retain the posts of Engineer/Assistant Engineer and the normal work of maintenance which would also be affected by the paucity of funds could be attended to by the lower level staff and utmost economy has to be observed and some of the posts might be done away with. (vide Ex. W1).

12. The counter of the management and the evidence putforth by it is that as per the circulars of the Head Quarters 17 posts were abolished to observe economy and in Ex. M16 the Head Quarters agreed to that abolition and the discharges thereafter were affected issuing three months notice to these said claimants.

13. It is contended on behalf of the workmen that the retrenchment or discharge of these claimants is illegal, that it was affected as a measure of punishment for their union activities, that it was by way of victimisation on the part of the Management and that the post of Engineer was subsequently revised and therefore the termination of these claimants should be set aside. To this the Management's contentions are that because the posts were abolished these have to be discharged, that no one in the Cantonment Board bore any grudge against any of these claimants and there was no victimisation at all and the post of the Engineer was found un-necessary at that point of time though it was revived subsequently and the discharge orders are valid and the claim of the workmen cannot be allowed. It is also contended that the Management has no knowledge of Cantonment Board Employees' Union and this Union cannot validly respresent the case of these workmen and the claim is in respect of individual disputes only and it does not involve any industrial dispute, and therefore the reference at the instance of the Union itself is bad It is also contended that the activities of the Cantonment Board do not amount to industry and these claimants were not employed as workmen in any industry and the Board was discharging the sovereign functions in maintaining the roads and communications and therefore the discharge relating to such employees cannot be the subject matter of an industrial dispute.

14. Though in the claims statement it is mentioned that for the Union activities and by way of victimisation the cantonment Board discharged these claimants and though W.W.I in his evidence mentioned that for the Union activities and as he was the President of the Cantonment Board Employees Union and the other five claimants are his supporters in Union activities they were all retrenched, the information elicited from him and other W.Ws in eross examination would go to show that it is not at all an active union and the discharge of the claimants would not at all before any union activities or by way of victimisation or as a measure of punishment. The evidence of W.W.I is that he was President of the Cantonment Board Employees' Union from 1967 to 1980 i.e. for fourteen years commencing from the next year of his removal from service. He states that from 1973 he is the Vice President of the All India Cantonment Board Employees' Federation till now, But admittedly he ceased to be the President of the Secunderabd Cantonment Board Employees Union by 1980, even by the date of this reference. He does not say in his evidence what activities his Union was undertaking during his Presidentship and how or why any one would be prejudiced against him for those activities. The Board has to decide by majority and it is not the Excutive Officer alone that takes decisions. In cross examination, he says that this dispute was taken up by his Union when he was the President but he states that there was no resolution by the General Body or the Executive of his Union for sponsoring this dispute, He says that the strength of the Union was 400 and he does not know whether the power to sponsor a dispute of the workmen vests in the general body alone. He tries to say that in his capacity as President, he sponsored this cause but there is no sanction behind it. W.W.2 states that he does not know the names even of the office bearers of the Union and he says that the other union members are still in service. When he does not know even the names of the Executive committee of the union, he cannot be said to be an active Unionist. W.W.3 F.Thomas, the third claimant refers to All India Cantonment Board Employees' Federation only and does not refer to the Secunderabad Cantonment Board Employees Union. Though he says that their Union is a registered one, he cannot tell its number and tells us that he does not know whether the union is functioning or ceased to function. G. Papaiah the fourth claimant as W.W.4 does not say that he was a member of the Union or that he was removed for his union activities. Therefore, the averment in the claims statement that these claimants are active unionists and for that they were removed by way of victimisation is merely a plea for its own sake advanced falsely and to gain some sympathy falsely if possible. None of these claimants appear to be Union activist nor is there anything to indicate that their removal was not as part of the obolition of the posts but as a measure of punishment.

15. The post of Draughtsman has not been revived. The evidence of M.W.2 show that except the post of Engineer no other posts that were abolished have been revived. M.W. 2 maintains that the removal of these claimants was as a measure of economy only. He says subsequently the post of Engineer came to be revived and the supervisor was made the Junior Engineer as the restrictions on construction of buildings were relaxed in some of the areas of the Board and number of colonies have come up after relaxation of those restrictions W.W.2 tries to say that now there is need for post of Draughtsman in view of the increased constructions activity. But admittedly that post is not revived and there is no Draughtsman post for taking back this W.W.2. W.W.3 the Road Roller Driver admits that there is no post of Road Roller Driver in the Board now. He states that he was also operating asphalt mixer machine and that machine is still there and it is lying idle. But he admits that he does not know whether the Cantonment Board handed over its Roads to Secunderabad Municipality. W.W. 4 Pappaiah the Fireman also admits that after abolishing the posts of Firemen there is no such post in the Board. The post of Engineer came to be revived as the building activity increased in the Board area. But that was revived or created in September 1981 only as per the communication dated 13-9-1981 from the Head Quarters which communication was enclosed to Ex. M13. From this communication it can be seen that the Board by its letter dated 29-7-1981 asked the Head Quarters for sanctioning that post. The Board might be corresponding with the Head Quarters for sanctioning that post from an earier period, but it came to be sanctioned in 1981 only by which date W.W. 1 attained the age of superannuation. Therefore the claimants cannot justifiably say that there are vacant posts for them and they could be taken back in those posts. As rightly pointed out by M.W. 1 these posts were abolished and consequently these claimants were discharged and there has been no possibility of taking them back unless the post are resanctioned or revived.

16. When the posts were abolished and there was reduction in the establishment these claimants came to be discharged under Rule 8(1)(e). It is not shown that the discharge was not bona fide or that it was improper r by way of victimisation or as a measure of punishment. For discharging them these claimants were given three month's notice as provided by the Rules and they have been paid gratuity due to them and admitedly all these claimants are also getting their regular pensions from the date of that discharge. On a consideration, I am of the view that the action of the Cantonment Board in discharging these claimants under Rule 8(1)(e) of the Cantonment Fund Service Rules is neither illegal nor unjust.

17. That apart, there is also considerable force in the contention of the Management that even if I.D.Act is applicable, the first claimant cannot be considered as a workman and he cannot ask for any relief from this Tribunal under the I.D. Act. This contention is extended to the second claimant the Draftsman also. As per Section 2(s) of the I.D.Act, in order to qualify as a workman, one should not be employed in a supervisory capacity drawing wages exceeding Rs. 500.00 nor he should be carrying on the functions of managerial nature. Section 2(s) (iv) take such persons out of the purview of the definition of the "workman". Seeing this plea in the counter, W.W.1 starts his evidence with an attempt to show that he was not having administrative control and therefore he would also be a workman. The evidence shows that there is only one Engineer for the Cantonment Board, The evidence of W.W.1 shows that he was getting Rs.1,440.00 per month at the time of the discharge order. He admits that he was the top most officer of the Engineering Department of the Board and there were two Supervisors under him and one Clerk and one Draftman work under him in his section besides some Class IV employees. He admits that all civil works of the Cantonment Board would be under his supervision. M.W.1 states that the Executive Officer takes disciplinary action on the recommendation of the Engineer and M.W.2's evidence is that the duties of the Engineer were to supervise the works of the staff under him and supervise the building construction and the Draftman and others work under the supervision of the Engineer. The evidence on record would thus show that the first claimant W.W.1 comes squarely within the purview of Section 2(s) (iv) of the I.D. Act and he cannot be considered as a workman. If he cannot be a workman, any dispute raised by him cannot be a dispute between the employer and workman and cannot become an industrial dispute. On this ground also the claim on behalf of the first claimant has to be rejected. The second claimant W.W. 2 was a Draftsman and he states that he was drawing Rs. 900.00 per month at the time of his discharge. But on a consideration of the evidence and the material before me it is not possible to conclude that he would also come under Section 2(s)(iv). It cannot be said that he was employed in a Supervisory capacity. The other claimants were admittedly not employed in supervisory capacity and therefore this contention cannot be pressed by the Management against them. Thus, I hold that in any event the first claimant is not a workman and he cannot be granted any relief by this Tribual in any event.

18. Another important contention of the Management is that the activities in which these claimants were employed cannot be considered as industry and the Cantonment Board in maintaining the roads was discharging the soverign functions and was not running an industry and the I.D. Act would not therefore apply to the claims of such employees. In the Management of India Government Mint, Hyderabad v. Workmen of India Government Mint and Another reported in N.R.C. in 1983(I) A.L.T. page 55, our High Court has held that the Mint is not an industry as it performs regal functions and therefore the dispute cannot be considered as an industrial dispute for making a reference. The Bangalore Water Supply case decided by a Full Bench of seven judges of Supreme Court and reported in 1978(I)(LLJ), page 349

is the conclusive and authoritative pronouncement on this aspect. It decides what activity can be considered as an industry and what activities of the corporation have to be excluded from that definition. The exercise of deciphering his Lordship Justice Krishna Iyer in this judgement need not be undertaken by me now t ofind out whether the maintenance of roads by the Secunderabad Cantonment Board for which purpose these claimants in the reference were employed would be an industry, as Chief Justice Sandawalia of the Punjab and Haryana High Court in state of Punjab Vs. Kuldip Singh reported in 1983 L.I.C. page 83 has explained the purport and ambit of the judgement of the Supreme Court while following it in that case which is similar to the one before me. The Chief Justice of the Punjab and Haryana High Court in that full bench decision, on a consideration of the Bangalore Water Supply case and following the principles laid down by the Supreme Court therein, held that the establishment, construction and maintenance of National and State Highways is an essential governmental function and it is in no way even remotely analogous to trade or business and consequently it cannot come within the ambit of "industry" as defined. His Lordship has clearly explained that in the present day of modern technology it cannot be said that the road building machinery like Bull Dozers, Coal Tar Heater and Spreaders etc., are not integral part of road construction and maintenance and that activity cannot be considered as industry. All these claimants before me were employed in this governmental function of laying and maintaining roads and supervising construction of building activities in the Cantonment Board area. Those activities carried on by the Cantonment Board cannot be equated to carrying an industry. These claimants therefore cannot be considered as workmen employed in an industry to maintain any claim and ask for any relief from this Tribunal under the I.D. Act.

19. On a consideration, and in the light of the foregoing, I hold that the activities in which the claimants were employed by the Cantonment Board were not an industry and the Board was carrying the Governmental activities when it was maintaining the roads and other constructions and the claimants cannot be said to have been engaged in any industry or avocation, and therefore their discharge cannot give rise to valid industrial dispute for adjudication by this Tribunal. On this ground alone it can be ruled that the claimants are not entitled to any relief in this industrial dispute from this Tribunal. I further hold that the first Petitioner in any event is not a workman within the meaning of that term in the Industrial Disputes Act and he is therefore not entitled to any relief from this Tribunal. I further hold that this dispute cannot be considered as an industrial dispute as it is not sponsored by any Union as claimed in the claims statement. On merits also, I hold that the discharge of these claimants by the Cantonment Board was valid and proper and cannot be considered as illegal and there are no posts revived for reinstatement of any of these claimants and the claimants are not therefore entitled to any relief as they have been paid all the amounts due to them under the Rules while affecting discharge and are also being paid their regular pension as per Rules. Thus on the point of the nature of employment of the claimants in sovereign activities and on the point that it is not an industrial dispute duly sponsored and also on merits, I hold that these claimants are not entitled to any relief.

Award passed accordingly.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 18th day of February, 1984.

Sd. Illegible,

Industrial Tribunal.

Appendix of Evidence

Witnesses Examined for the Workmen :	Witnesses Examined for the Management
W.W.1 M. C. Parthasarathy	M.W.1 D.S. Ramcahander Rao
W.W.2 M. A. Haneef	M.W.2 G. Narasimha Rao
W.W.3 F. Thomas	
W.W.4 G. Papaiah	
W.W.5 Salatha Bai	

Documents filed by the Workmen :

Ex. W1 By consent. True copy of the letter No. 12677/MLC Head-quarter Southern Command Pune dt. 3rd May, 1975 regarding review of estabilshment pattern in the Sanitation and public works branches of Cantonment boards.

Ex. W2 By consent. Extract from the Proceedings of the Special meeting of the Cantonment Board held at the Office of the Cantonment Board, Secunderabad on 4th November, 1975, regarding the abolition of posts of Cantonment Engineer, Sanitary Superintendent and Draftsman.

Ex. W3 True Copy of the letter No. 3331 dt. 30-6-81 addressed by the Executive Officer, Cantonment Board, Secunderabad to M.A. Hanif, Draftsman, regarding reduction or revision of Estabilshment in Cantonment Board, Secunderabad.

Ex. W4 True Copy of the letter No. 3335, dt. 30-6-81 addressed by the Cantonment Executive Officers, Secunderabad to F. Thomas, regarding reduction or Revision of Establishment in Cantonment Board, Secunderabad.

Ex. W5 True Copy of the letter No. 3334, dt. 30-6-76 addressed by the Cantonment Executive Officer, Secunderabad G. Papaiah, regarding the reduction or revision of Estabilshment in Cantonment Board, Secunderabad.

Ex. W6 Death Certificate dt. 18-11-76 of T. S. Nagabhushanam issued by the Assistant Surgeon Cantonment Board Dispensary Picket.

Document marked for the Management : by Consent

Ex. M1 Extract from the Proceedings of the ordinary Meeting of the Cantonment Board held on 23-10-75.

Ex. M2 Telegram dt. 13-11-75 regarding review of Estabilshment.

Ex. M3 Letter No. 12677/1/MLC from Headquarter Southern Command dt. 15-11-75 to the President Cantonment Board, Secunderabad, regarding the Review of Establishment pattern in the Sanitation and Public Works branches of Cantonment Boards.

Ex. M4 Extract from the Proceedings of the Special meeting of the Cantonment Board held at the Office of the Cantonment Board, ecunderaad on 9-3-76.

Ex. M5 Extract from the Proceedings of the Ordinary meeting of the Cantonment Board held at the office of the Cantonment Board, Secunderabad on 25-11-75.

Ex. M6 Extract from the Proceedings of the ordinary meeting of the Cantonment Board held at the office of the Cantonment Board, Secunderabad on 27-12-77.

Ex. M7 Letter No. 554, dt. 27-1-78 addressed by Brigadier, President, Cantonment Board, Secunderabad to the General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command, Pune, regarding the redesignation of the

post held by Shri B. Kistiah, Supervisor as Junior Engineer, Secunderabad Cantonment.

Ex. M8 Letter No. 1895, dt. 24-4-78 addressed by Brigadier, President, Cantonment Board, Secunderabad, to the General Officer Commanding-in-Chief Headquarters Southern Command, Pune, regarding the redesignation of the post held by Shri B. Kistiah, Supervisor as Junior Engineer, Secunderabad Cantonment.

Ex. M9 Letter No. 7680/B/XIII/DLC, dt. 11-5-78 addressed by General Officer Commanding-in-Chief, Southern Command, Pune, to the President, Cantonment Board, Secunderabad, regarding the redesignation of the post held by Sri B. Kistiah, Supervisor as Junior Engineer, Secunderabad Cantonment.

Ex. M10 Office Order No. 2356, dt. 24-5-1978 issued by Cantonment Executive Officer to B. Kistiah, Supervisor.

Ex. M11 C.B.R. No. 11 dated 29-7-80 regarding the Resolution of the post of Cantonment Engineer and Junior Engineer in the pay scale of Rs 1050-1600.

Ex. M12 Letter No. 4976, dt. 1-8-80 addressed by the Office of the Cantonment Board, Secunderabad to the General Officer, Commanding-in-Chief, Headquarter Southern Command, Pune, regarding the redesignation of the post held by Sri B. Kistiah, Junior Engineer as Cantonment Engineer, Secunderabad Cantonment.

Ex. M13 Letter No. 7680/B/XV/DLC, dt. 30-9-81 addressed by the General Officer Commanding-in-Chief Directorate of Defence, Lands and Cantonments, Ministry of Defence Southern Command, Pune, to the President, Cantonment Board, Secunderabad, regarding the creation of the post of Cantonment Engineer (Assistant Engineer) in the Secunderabad Cantonment Board.

Ex. M14 Copy of the letter No. 8289/RET/Co/CB/MLN, dt. 5-9-75 addressed by the General Officer, Commanding-in-Chief to the President, Cantonment Board, Secunderabad in Southern Command regarding the review of cases of Cantonment Board Employees after attaining the age of 55 years or completing 30 years of service.

Ex. M15 Office Order No. 6763, dt. 16-11-81 issued by Cantonment Executive Officer to B. Kistiah, Cantonment Engineer, Secunderabad Cantonment Board.

Ex. M16 Letter No. 12677/MLC, Headquarters Southern Command dt 15-6-76 issued by General Officer Commanding-in-Chief to the President, Cantonment Board, Secunderabad regarding the review of Estabilshment pattern in the Sanitation and Public Works Branches of Cantonment Board.

M. SRINIVASA RAO Industrial Tribunal

[No. L-13011(1)/78-D.II(B)]

T. B. SITARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984